लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[तृतीय माला
Third Series]

[खंड 42, 1965/1887 (शक)
Volume, XLII, 1965/1887 (Saka)]

[20 अप्रैल से 1 मई, 1965 तक/30 चैत्र से 11 वशाख, 1887 (शक)तक
April 20 to May 1, 1965/Chaitra 30 to Vaisakha 11, 1887 (Saka)]

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 42 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 41—50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची

अंक 41—मंगलवार 20 अप्रैल, 1965/30 चैत्र, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
924	राज्यों का गेंहू का कोटा	3849—53
925	चुकन्दर से चीनी तैयार करने की परियोजना	3853–54
926	उचित मूल्य की दुकानों की कार्य प्रणाली	3855–56
927	उर्वरकों का वितरण	3856—60
929	टिड्डी नियंत्रण	3860–61
930	गांवों में डाक सेवायें	3861—63
931	ग्रामीण ऋण	3863—65
932	आदिम जाति खंडों में सड़कें	3866—68
933	चीनी निर्यात सम्बन्धी नीति	3868–69
934	हिन्दी योजना को क्रियान्वित करने के लिये समितियां	3869–70

प्रश्नों के लिखित उत्तर

928	किसानों को ऋण	3870–71
935	बिहार में गन्ने की पिराई	3871
936	चीनी का उत्पादन	3871–72
937	अनाज के भाव	3872
938	खाद्य क्षेत्रों का मूल्यों पर प्रभाव	3873
939	पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय प्रबन्ध	3873
940	बम्बई के नाविकों द्वारा हड़ताल की धमकी	3874
941	अनाज की वसूली	3874
942	दिल्ली में राशन व्यवस्था	3874
943	आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण का पुनर्गठन	3875
944	चीनी मूल्य जांच आयोग	3875
945	उचित मूल्य की दुकानों का लूटा जाना	3875–76

अतारांकित प्रश्न संख्या		
2366	बागबानी का विकास	3876
2367	राजस्थान में स्थानीय विकास कार्य	3876

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 41—Tuesday, April 20, 1965/Chaitra 30, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
924	Wheat Quota of States	3849–53
925	Project for Beet Sugar	3853–54
926	Working of Fair Price Shops	3855–56
927	Distribution of Fertilizers	3856–60
929	Locust Control	3860–61
930	Postal Services in Villages	3861–63
931	Rural Debt	3863–65
932	Roads in Tribal Blocks	3866–68
933	Sugar Export Policy	3868–69
934	Committees for implementation of Hindi	3869–70

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
928	Credit to Farmers	3870–71
935	Crushing of Sugarcane in Bihar	3871
936	Production of Sugar	3871–72
937	Prices of Foodgrains	3872
938	Impact of Food Zones on Prices	3873
939	Financial management of the Panchayati Raj Institutions	3873
940	Threatened Strike by Bombay Seamen	3874
941	Procurement of Foodgrains	3874
942	Rationing in Delhi	3874
943	Reorganisation of Income-tax Appellate Tribunals	3875
944	Sugar Price Enquiry Commission	3875
945	Looting of Fair Price Shops	3875–76
Unstarred Questions Nos.		
2366	Development of Horticulture	3876
2367	Local Development Works in Rajasthan	3876

*The sign+ marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2368	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण . . .	3877
2369	छोटे पत्तनों का सर्वेक्षण .	3877
2370	सरकारी क्षेत्र में होटल . . .	3877-78
2371	होटल वालों तथा टेक्सी चालकों को ऋण . . .	3878
2372	दूध के सम्भरण के लिये धातु के टोकन . . .	3878–79
2373	खादी ग्रामोद्योग भवन	3879
2374	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	3879
2375	मध्य प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग .	3879–80
2376	उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन	3880
2377	मत्स्य पालन का विकास	3880–81
2378	उत्तर भमि को उपजाऊ बनाना	3881
2379	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण . .	3881
2380	चूहों द्वारा फसल को हानि	3881–82
2381	वायनाड बस्तीकरण योजना	3882
2382	बस्तर क्षेत्र के आदिवासी	3882
2383	बस्तर क्षेत्र के आदिवासी .	3883
2384	खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ	3883
2385	विधियों का अनुवाद	3883–84
2386	नालागढ़ समिति .	3884
2387	दिल्ली में नया पुल .	3884
2388	राकेट यात्रा . . .	3885
2389	विस्तार कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण .	3885
2390	पीने के पानी के लिये कुएं . .	3885
2391	तीर्थ स्थान	3886
2392	कोयला खान भविष्य निधि . . .	3886
2393	सहकारी आन्दोलन . . .	3886–87
2394	चावल की नई किस्म	3887
2395	दस्तकारी उद्योग, उड़ीसा	3887
2396	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां . . .	3888
2397	अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम . .	3888
2398	सोवियत संघ से भेड़ें . . .	3888–89
2399	भारतीय जहाज "विश्व ज्योति" . .	3889
2400	भेड़ विकास फार्म . . .	3889
2401	केरल में मस्लिम लीग . . .	3889–90

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
2368	Vocational Training of S.C. and S.T.	3877
2369	Survey of Minor Ports	3877
2370	Hotels in Public Sector	3877–78
2371	Loan for Hoteliers and Taxi Operators	3878
2372	Metal Tokens for Milk Supply	3878–79
2373	Khadi-Gramodyog Bhawan	3879
2374	S.C. and S.T. in Madhya Pradesh	3879
2375	Khadi and Village Industries in Madhya Pradesh	3879–80
2376	Old Age Pensions in U.P.	3880
2377	Development of Fisheries	3880–81
2378	Reclamation of Waste Land	3881
2379	Welfare of S.C. and S.T. in U.P.	3881
2380	Crop damaged by Rats	3881–82
2381	Wyand Colonisation Scheme	3882
2382	Adivasis of Bastar Area	3882
2383	Adivasis of Bastea Area	3883
2384	F.A.O. Experts	3883
2385	Translation of Laws	3883–84
2386	Nalagarh Committee	3884
2387	New Rail Bridge in Delhi	3884
2388	Rocket Travel	3885
2389	Training of Extension Workers	3885
2390	Wells for Drinking Water	3885
2391	Places of Pilgrimage	3886
2392	Coal Mines Provident Fund	3886
2393	Co-operative Movement	3886–87
2394	New variety of Rice	3887
2395	Hendicrafts Industry, Orissa	3887
2396	Colonies for S.Cs. & S.Ts. in Orissa	3888
2397	Ambar Charkha Training Courses	3888
2398	Sheep from U.S.S.R.	3889–89
2399	Indian vessel "Vishva Jyoti"	3889
2400	Sheep Development Farms	3889
2401	Muslim League in Kerala	3889–90

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2402	कार्ड धारियों को दुग्ध सम्भरण	3890
2403	सहकारी समितियां	3890-91
2404	अनाज का सम्भरण	3891
2405	केन्द्रीय संग्रह डिपो	3891-92
2406	महिला सहकारी समितियां	3892
2407	विदेशी पर्यटन यातायात	3892-93
2408	सहकारी फल परिरक्षण तथा डिब्बाबन्दी एकक	3893-94
2409	मीनक्षेत्र सम्बन्धी निगम	3894
2410	पहाड़ी क्षेत्र में भेड़ पालन	3894
2411	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था	3894
2412	मद्रास में फल तथा अनुसंधान केन्द्र	3895
2413	अन्तर्राज्यीय जल परिवहन निगम	3895
2414	पशुओं के सघन विकास खंड	3895-96
2415	कृषि फार्म	3896
2416	चीनी मिलें	3896-97
2417	केरल विधान सभा के लिये चुनाव	3897
2418	संविधान का हिन्दी संस्करण	3897
2419	कलकत्ता-गोहाटी मालवाहक सेवा	3898
2420	बीज प्रगुणन क्षेत्र	3898
2421	संयुक्त राज्य अमरीका से गेंहू का आयात	3898-99
2422	केरल सड़क परिवहन निगम	3899
2423	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	3899-3900
2424	भण्डागार निगम	3900
2425	आसाम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	3900
2426	राष्ट्रीय समुद्रीय प्रौद्योगिकी संस्था	3900-01
2427	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	3901
2428	कृषि विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	3901
2429	तुना मछली को पकड़ना	3901-02
2430	दूध के कार्डों की पुनः अवधि बढ़ाना	3902
2431	स्टेनलेस स्टील मिल्क बार	3902
2432	दमदम हवाई अड्डा	3903
2433	समुद्रीय इंजीनियरी पाठ्यक्रम	3903

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
2402	Milk Supply to Card Holders	3890
2403	Cooperative Societies	3890–91
2404	Supply of Foodgrains	3891
2405	Central Storage Depots	3891–92
2406	Women's Cooperative Societies	3892
2407	Foreign Tourist Traffic	3892–93
2408	Cooperative Fruit Preservation and Canning Units	3893–94
2409	Fisheries Corporation	3894
2410	Rearing of sheep in Hill areas	3894
2411	I.A.R.I.	3894
2412	Fruit-*cum*-Research Station in Madras	3895
2413	Inter-State Water Transport Corporation	3895
2414	Intensive Cattle Development Blocks	3895–96
2415	Agricultural Farms	3896
2416	Sugar Mills	3896–97
2417	Kerala Assembly Elections	3897
2418	Hindi Version of the Constitution	3897
2419	Calcutta-Gauhati Freighter Service	3898
2420	Seed Multiplication Farms	3898
2421	Import of Wheat from U.S.A.	3898–99
2422	Kerala Road Transport Corporation	3899
2423	Coal Mines Provident Fund Organisation	3899–3900
2424	Warehousing Corporation	3900
2425	Welfare of S.C. & S.T. in Assam	3900
2426	National Institute of Marine Technology	3900–01
2427	S.C. & S.T. Employees of F. & A. Ministry	3901
2428	International Cooperation for Agricultural Improvement	3901
2429	Tuna Fishing	3901–02
2430	Revalidation of Milk Cards	3902
2431	Stainless Steel Milk Bar	3902
2432	Dum Dum Airport	3903
2433	Marine Engineering Courses	3903

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
प्रधान मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा का मुल्तवी किया जाना	3903—08
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	3903
श्री स्वर्ण सिंह	3903—08
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	3909
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	3909
प्राक्कलन समिति—	
अस्सीवां प्रतिवेदन	3909
लोक-लेखा समिति—	
पैंतीसवां प्रतिवेदन	3909
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन .	3909
अनुदानों की मांगें	3910—44
स्वास्थ्य मंत्रालय	3910—24
श्री हिम्मतसिंहका	3910—11
डा० चन्द्रभान सिंह	3911—12
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	3912—13
श्री विश्वनाथ राय	3913
श्री गौरी शंकर कक्कड़	3913
श्री मोहन स्वरूप	3913—14
श्री गोकुलानन्द महन्ती	3914—15
श्री किशन पटनायक	3915
श्री शिव चरण गुप्त	3915—16
डा० सुशीला नायर	3916—24
उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय	3925—44
श्री दाजी	3925—28
श्री श्यामलाल सर्राफ . .	3928—29
श्री म० प० स्वामी	3929—32
श्री क० ना० तिवारी	3932—33
श्री नारायण दांडेकर	3933—35
श्री हेडा	3939—41
श्री सुब्बरामन	3941—42
श्री बड़े . . .	3942—43
डा० राम मनोहर लोहिया . .	3943
श्री विभुधेन्द्र मिश्र	3943—44
श्री अचल सिंह	3944

Subject	PAGES
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Postponement of Prime Minister's visit to U.S.	3903—08
Shrimati Renu Chakravartty	3903
Shri Swaran Singh	3903—08
Re : Motion of Privilege	3909
Re : Calling Attention Notice (Query)	3909
Paper laid on the Table	3909
Estimates Committee—	
Eightieth Report	3909
Public Accounts Committee—	
Thirty-fifth Report	3909
Committee on Public Undertakings—	
Fifth Report	3909
Demands for Grants	3910—44
Ministry of Health	3910—24
Shri Himmatsingka	3910–11
Dr. Chandrabhan Singh	3911–12
Dr. L.M. Singhvi	3412–13
Shri Bishwanath Roy	3913
Shri Gauri Shankar Kakkar	3913
Shri Mohan Swaroop	3913–14
Shri Gokulananda Mohanak	3914–15
Shri Kishen Pattnayak	3915
Shri Shiv Charan Gupta	3915–16
Dr. Sushila Nayar	3916—24
Ministry of Industry and Supply	3925—44
Shri Daji	3925—28
Shri Sham Lal Saraf	3928–29
Shri M.P. Swamy	3929—32
Shri K.N. Tiwary	3932–33
Shri N. Dandekar	3933—35
Shri Heda	3939—41
Shri Subbaraman	3941–42
Shri Bade	3942–43
Dr. Ram Manohar Lohia	3943
Shri Bibudhendra Misra	3943–44
Shri Achal Singh	3944

लोक सभा
LOK SABHA

गुरूवार, 20 अप्रैल, 1965 / 30 चैत्र, 1887 (शक)
Thursday, April 20, 1965/Chaitra 30, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS]

राज्यों को गेंहूं का कोटा

+

*924. श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उनका आयात किये हुये गेहूं का कोटा बढ़ा दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा कितनी वृद्धि की मांग की गई है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). कुछ राज्य सरकारों ने आयातित गेहूं की बहुत बड़ी मात्रा भेजने के लिये कहा था मगर उनकी ये मांगें पूर्णरूपेण पूरी नहीं की जा सकीं। एक विवरण जिसमें उन राज्यों की मार्च और अप्रैल, 1965 के लिये मांगी गयी और इन दोनों महीनों में अलाट की गयी मात्रा दी गयी है लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4213/65।]**

Shri Yashpal Singh: I am not talking of the demand but the promises made by the Government. The Government had promised 1 lakh and 20 thousand tons of wheat out of which only 57,000 tons of imported wheat have been supplied ; how would this injustice be redressed ? The figures for Madras are not there ; perhaps their demand is being met in full.

श्री दा० रा० चह्वाण: कमी वाले राज्यों में गेहूं की सप्लाई अनाज की उपलब्धता और राज्य की आवश्यकता देख कर की जाती है। जैसा कि माननीय सदस्य को पता है अटलांटिक और गल्फ की पत्तनों में बहुत देर तक हड़ताल रही थी। इस कारण आयात कार्यक्रम योजना के अनुसार नहीं चल सका।

Shri Yashpal Singh : Whenever the supply is to be made to U.P. either the wagons are not there or the supply position is bad. I want to know clearly when this injustice will be redressed otherwise we may have to go on hunger-strike.

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : सभा को पता है कि अमरीका की पत्तनों में हड़ताल के कारण पिछले तीन महीनों से कोई सप्लाई नहीं आ रही है। अब स्थिति ठीक हो गई है और खाद्य सचिव अमरीका जाकर अनाज के जहाज सान्तट आधार पर भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। पत्तनों से अनाज शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था भी कर दी गई है। हमें आशा है कि इस महीने के अन्त तक सभी राज्यों की मांगें पूरी कर दी जायेंगी। मई का महीना अच्छा रहेगा क्योंकि इस महीने हमें 80,000 टन की सप्लाई की आशा है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या इसका प्रभाव केवल उत्तर प्रदेश पर पड़ा है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह तो अपने कम साधनों के राशन करने का प्रश्न है। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य ने मद्रास का उल्लेख किया था। मार्च के महीने में मद्रास को 10.7 हजार टन अनाज मिला था और उत्तर प्रदेश को 57,000 टन मिला था।

श्री दी० चं० शर्मा : इस विवरण को देख कर बहुत दुःख होता है, क्योंकि जो सप्लाई मांगी गई थी और जो सप्लाई दी गई है उसमें बहुत अन्तर है। यह न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के मामले में है अपितु अन्य राज्यों के मामले में भी है। हमें सदैव यह बताया गया कि हमारे पास सुरक्षित भंडार हैं। उन भंडारों का क्या हुआ ? क्या उनसे उन राज्यों की मांगें पूरी नहीं हो सकतीं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: माननीय सदस्य बहुत पुराने संसद सदस्य हैं और उनको हमारी कठिनाई समझ में आ गई होगी। कठिनाई यह है कि आयातित गेहूं की बहुत अधिक मांग के कारण सुरक्षित भंडार समाप्त हो गये हैं। परन्तु मांग और सप्लाई में जो यह अन्तर है वह अमरीका की पत्तनों में हड़ताल के कारण हुई।

श्री स० चं० सामन्त : जिन चावल खाने वाले राज्यों ने गेहूं खाने की आदत डाल ली है, क्या उनको कोई विशेष सुविधा दी जा रही है कि उनका गेहूं का कोटा कम न किया जाय।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह कम साधनों के अभिभाजन का प्रश्न है। उन राज्यों में भी जहां हम चावल की मांग को गहूं देकर पूरा कर रहे हैं, गेहूं उपलब्ध स्टाक के आधार पर दिया गया है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : हम जानते हैं कि कमी थी । हमारा प्रश्न यह है कि जब कमी थी तो कुछ मामलों में सप्लाई 60 प्रतिशत थी और कुछ अन्य मामलों में यह 10 प्रतिशत से भी कम थी जैसा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मामले में देखा गया है । इस असमता को वह किस प्रकार युक्तियुक्त ठहरा सकते हैं।

श्री रंगा : यह उनकी आवश्यकता के अनुसार था ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : जब कि मांग 50,000 टन की थी, केवल 5,000 टन दिये गये ।

अध्यक्ष महोदय : मांग एक समान नहीं हो सकती थी । इसलिये जो कमी की गई वह भी एक समान नहीं हो सकती थी । यह बहुत ही सरल बात है ।

Shri Ram Sewak Yadav: In the statement placed on the Table the allotment of the quota has not been according to the demand. I want to know the basis according to which this quota was allotted ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : संसाधनों की उपलब्धता ही आवंटन का आधार है। जिन क्षेत्रों में गेहूं की पैदावार होती है, यह स्वाभाविक है कि किसान के पास जो स्टाक है उनको भी ध्यान में रखा जाता है ।

Shri Ram Sewak Yadav: Sir, please listen to my submission also. Different states have been allotted quota, less in some cases and more in the other cases. If the demand is more and the quota allotted is less, because the imported wheat had not been received, then this reduction should have been made for all the states ; I want to know whether there is some basis for this allotment or it is according to their whims ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has replied that while allotting imported wheat in the wheat producing areas the stocks with the producers are also taken into account.

Shri Sarjoo Pandey : The buffer stocks have been exhausted, the imported wheat is not coming because of strike in America and the demands of the states are increasing; what steps do you propose to take to prevent the situation degenerating into famine ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं अध्यक्ष महोदय को यह बताने के लिये आभारी हूं कि कोटा मांग के अनुसार नहीं दिया जाता । वास्तव में स्थानीय उपलब्धता को देखते हुये कोटा बहुत कम कर दिया गया है । वर्तमान स्थिति यह है कि इस महीने के अन्त तक हम राज्यों की लगभग सभी मांगें पूरी कर देंगे और इसके पश्चात् कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : विवरण से यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश ने 52,000 टन की मांग की थी, जबकि उसे 5,000 टन दिया गया। क्या मैं इस अन्तर का कारण जान सकता हूं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जसा कि मैं ने कहा था मांग और चीज है और जो कोटा दिया जाता है वह भिन्न चीज है । मुझे खेद है कि विभिन्न राज्यों को आयातित गहूं का जो कोटा दिया गया है उसको दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा है । मैं एक और विवरण रख कर इस त्रुटि को दूर कर दूंगा ।

श्री पु० र० पटेल : वे राज्य, जहां गेहूं पैदा होता है, भी आयातित गेंहूं की मांग करते हैं । क्या कारण है कि विदेशी गहूं का मूल्य देशी गेहूं से बहुत कम है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : विदेशी गेहूं के मूल्य को सरकार नियंत्रित करती है क्योंकि वह ही इसके मूल्य निश्चित करती है। देसी गहूं का मूल्य माकट द्वारा निश्चित किया जाता है ।

श्री पु० र० पटेल : क्या गेंहूं ––उत्पादक राज्यों द्वारा विदेशी गहूं की मांग करने का कारण यह है कि विदेशी गेहूं का मूल्य देसी गहूं के मूल्य से बहुत कम है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसाकि मैं ने कहा विदेशी गेहूं के मूल्य को सरकार नियंत्रित करती है . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जो मूल्य सरकार निश्चित करती है क्या वह देसी गेहूं के मूल्य से कम है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : विदेशी गेहूं का मूल्य निसन्देह कम है ।

श्री कपूर सिंह : जब अनाज प्राप्त करने की मांगें तैयार की जाती हैं तो क्या अतिरेक राज्यों की मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वास्तव में प्रत्येक राज्य से अनाज प्राप्त करने के लिए तथा राज्य से बाहर सप्लाई करने के लिए जो कोटा निश्चित किया जाता है वह पूर्णतया राज्य सरकार के परामर्श से किया जाता है ।

श्री कपूर सिंह : यह मेरा प्रश्न नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : तात्पर्य यह है कि क्योंकि राज्य सरकार से परामर्श किया जाता है अतः राज्य सरकार राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है ।

श्री रंगा : तात्पर्य एक बात है और सीधा उत्तर दूसरी बात है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस मामले में तात्पर्य और जो हो रहा है दोनों एक ही चीज हैं । राज्य को यह निश्चय करना होता है कि कितना अनाज प्राप्त किया जा सकता है और राज्य की सिफारिशों के आधार पर कार्य किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार अपनी अतिरेक आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वास्तव में राज्य सरकारों ने स्वयं ही आंकड़ दिये हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : कोटा देते समय क्या जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सात करोड़ है इसे 57,000 टन अनाज मिल रहा है, पश्चिम बंगाल को 52,000 टन अनाज मिल रहा है ।

श्री त० त० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि राज्य की आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय जनसंख्या, शायद निश्चायक कारक होती हैं ।

चुकन्दर से चीनी तैयार करने की परियोजना

+

*925. **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चुकन्दर से चीनी तैयार करने के लिये एक मार्गदर्शी परियोजना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर स्थापित की जायेगी ;

(ग) क्या मशीनों के नमूने देश में ही तैयार किये जायेंगे और मशीनों का निर्माण भी यहीं किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो ये कहां से प्राप्त की जायेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) यमुना नगर पंजाब में ।

(ग) और (घ). मशीनों के कुछ नमूने (अर्थात् डिफ्यूजर, प्रेलीमर, बाशर और स्लाइसर) डनमार्क से आयात किये जा रहे हैं और शेष मशीनरी स्वदेशी होगी ।

श्री स० चं० सामन्त : भारत में कौन से राज्य बड़े पैमाने पर चुकन्दर से चीनी तैयार करते हैं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : भारत में चुकन्दर से चीनी नहीं बनाई जाती है । चुकन्दर शीत जलवायु में पाया जाता है । हम तो केवल परीक्षण कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या चुकन्दर भी किसी राज्य में पाया जाता है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : सब राज्यों में नहीं ; केवल कुछ क्षेत्रों में ।

अध्यक्ष महोदय : यह क्षेत्र किन राज्यों में हैं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इस चुकन्दर को चीनी का चुकन्दर कहा जाता है। इसका उत्पादन सभी राज्यों में नहीं हो रहा है । जैसा कि मैंने कहा इसका उत्पादन केवल शीत प्रदेशों में हो सकता है ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, फिलहाल तो हम केवल परीक्षण कर रहे हैं । जहां तक चुकन्दर का सम्बन्ध है परीक्षण के प्रयोजनों के लिए इसका छोटी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जाता । अभी इस पर प्रयोग हो रहा है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्योंकि अब सरकार मार्गदर्शी परीक्षण करने जा रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस देश में चुकन्दर का उपभोग किया जाता है और क्या इसके निर्माण की संभावना है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : देश में उत्पादन के लिए एक मार्गदर्शी परीक्षण किया जा रहा है । जब इसमें कुछ प्रगति होगी उसके पश्चात् ही निर्यात के बारे में सोच सकते हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या इस मार्ग दर्शी परियोजना के परिव्यय का भी अनुमान लगाया गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : गन्ने के प्रति एकड़ औसत उत्पादन से जो अनुमान लगाया गया है, उसके आधार पर चुकन्दर से चीनी बनाने का परिव्यय गन्ने की चीनी से 10 रुपये प्रति टन कम होगा । यह औसत परिव्यय के आधार पर है । वास्तविक व्यवहार में भी इसे सिद्ध करना पड़ेगा ।

श्री विश्वनाथ राय : चुकन्दर से चीनी बनाने की परियोजना को अन्तिम रूप देने से पहले क्या यह जांच कर ली गई है कि चुकन्दर पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा जिससे भविष्य में हानि न उठानी पड़े ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जी नहीं । अभी केवल परीक्षण किया जा रहा है । अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें प्रगति होगी अथवा नहीं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : तुंगभद्रा परियोजना में जहां कई लोगों ने चीनी के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिये हैं, क्या उनको चुकन्दर से चीनी बनाने के लिए भी लाइसेंस दिये जायेंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं कि मैं बता सकूं कि तुंगभद्रा क्षेत्र में चुकन्दर पैदा किया जा सकता है कि नहीं । यदि यह वहां पैदा हो सकती है तो, मेरे विचार में, लाइसेंस का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know whether the beet sugar will be cheaper than the cane sugar and how much ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has already told.

Shri Rameshwaranand : May I know the production of sugarcane per acre and how much sugar can be produced therefore and how much beet is produced in one acre and how much sugar is produced therefrom ? Has the area of the land been also taken into consideration ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : एक एकड़ से औसत 13 टन गन्ने का उत्पादन होता है ; जबकि एक एकड़ भूमि में लगभग 15 टन चुकन्दर का उत्पादन होता है । गन्ने की अपेक्षा चुकन्दर से अधिक चीनी प्राप्त होगी । निर्माण का परिव्यय भी कुछ अधिक ही आयेगा । इसी कारण गन्ने की चीनी तथा चुकन्दर की चीनी के मूल्यों में पर्याप्त अन्तर होगा ।

उचित मूल्य की दुकानों की कार्य प्रणाली

*926. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 8 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 412 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोफेसर वी० एम० दांडेकर के नेतृत्व में बताये गये दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसको अनाज की उचित मूल्य की दुकानों की कार्य प्रणाली का पुनर्विलोकन करने, इन दुकानों के माध्यम से बेचे जाने वाले अनाज के भाव निश्चित करने तथा उन दुकानों के द्वारा अनाज की बिक्री के कारण अनाज की मंडी पर पड़ने वाले सामान्य प्रभाव की जांच करने का कार्य सौंपा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस की क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृ.ष मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह विषय प्रकाश में आया है कि अनाज की अनियमित सप्लाई के कारण, विशेषतया उन क्षेत्रों में जहां गेहूं पैदा नहीं होता, वहां मार्केट में गेहूं का मूल्य दुगना हो गया है, यदि हां, तो मूल्यों की इस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न को दोहरा दीजिए ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या उचित मूल्यों की दुकानों को अनाज की अनियमित सप्लाई के कारण, विशेषतया उन क्षेत्रों में जहां गेहूं पैदा नहीं होता, बाजार में भाव दुगुने हो गये हैं और यदि हां, तो मूल्यों की इस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस प्रश्न का सम्बन्ध उचित मूल्य की दुकानों की कार्यप्रणाली के बारे में जांच से है और इसका उत्तर यह दिया गया है कि प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं हुआ । मेरा विचार है कि जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है वह इससे भिन्न है ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच नहीं है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज के नियंत्रित मूल्य भिन्न भिन्न हैं और क्या इस के कारण गेहूं का अत्याधिक तस्कर व्यापार होता है और जिसके फलस्वरूप इसे काले बाजार में बेचा जाता है ?

श्री त० त० कृष्णमाचारी : मैं इस मत से सहमत हूं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि यह दांडेकर समिति अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में कितना समय लेगी, तथा क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस समिति ने अभी तक कितने राज्यों का दौरा किया है और क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य का भी दौरा किया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दूंगा। आशा है कि प्रतिवेदन बहुत शीघ्र तैयार हो जायेगा —शायद 15 दिन या एक महीने में।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाई गई है कि केन्द्र द्वारा उचित मूल्य की दुकानों को दिये गये गेहूं की काफी मात्रा बोगस राशन कार्डों द्वारा, जो कि दुकानदारों के पास पडे रहते हैं, प्राप्त करके बाजार में बेची जाती है, और यदि हां, तो क्या यह समिति इस मामले पर भी विचार करेगी और यह देखेगी कि गेहूं केवल असली कार्ड वालों को दिया जाय।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने जिस तथ्य का उल्लेख किया है, वह सर्व-विदित है। उचित मूल्य की दुकानों से गेहूं अन्य स्थानों में भी भेजा जाता है। परन्तु समिति को सारे प्रश्न पर विचार करना चाहिये। वह क्या करेगी और क्या वह उचित मूल्य की दुकानों की कार्य-प्रणाली के इस विशेष पहलू पर रिपोर्ट देगी, इसको हम केवल उनकी रिपोर्ट आने के पश्चात ही बता सकेंगे।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार उससे अवगत है कि उचित मूल्य की दुकानों में काले बाजार का एक कारण, और शायद जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है कि उचित मूल्य की दुकानों में कार्यकर्त्ताओं को बहुत कम लाभ कम होता है, इतना होता कि भाड़ा देने के पश्चात उनके पास कुछ नहीं बचता ?

अध्यक्ष महोदय : समिति का उससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह जरूरी नहीं कि अधिक लाभ के देने से उचित मूल्य की दुकानों के मालिक काला बाजार नहीं करेंगे।

उर्वरकों का वितरण

*927. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 24 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक के वितरण के बारे में भारत में अमरीकी सहायता मिशन की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : सरकार ने उर्वरकों के वितरण की दीर्घ तथा अल्पकालीन समस्याओं पर विचार करने के लिए जो विशेषज्ञ समिति स्थापित की है, वह समिति अपनी जांच के दौरान में अन्य बातों के साथ-साथ इस सिफारिशों पर भी विचार करेगी। आशा है कि समिति मई, 1965 में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सरकार आगे कार्यवाही करेगी।

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या यह सच नहीं है कि उर्वरकों के वितरण तथा उत्पादन के बारे में कठिनाइयों को महसूस किया गया है कि और पिछले 10 वर्षों में सरकार को इस बारे में शिकायतें भेजी गई हैं, और यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने अभी तक क्यों कोई विशिष्ट कार्यवाही नहीं की ?

श्री शाहनवाज खां : इस समिति को स्थापित करने का मुख्य कारण तो यही है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूं कि माननीय उपमंत्री ने 24 नवम्बर, 1964 को इस बारे में दिये गये उत्तर को ठीक उसी प्रकार अब दोहरा दिया है :–

अध्यक्ष महोदय : अब भी वही स्थिति हो सकती है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मेरा निवेदन यह है कि सरकार द्वारा पिछले चार महीनों में कोई कार्यवाही नहीं की गई और इससे यह स्पष्ट है कि वे इस समस्या की गम्भीरता को कोई महत्व नहीं देते हैं ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : उर्वरकों की पूर्ति सम्बन्धी स्थिति में काफी सुधार हुआ है । देशीय उत्पादन में वृद्धि हुई है । सही आंकड़े तो मैं नहीं बता सकता परन्तु पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है । यथार्थ समस्या तो यह है कि मांग अधिक है और पूर्ति कम। जब तक इस अन्तर को दूर नहीं किया जाता तब तक कुछ दुरुपयोग होना लाजमी है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : लेबनान, टर्की और घाना जैसे देशों ने उर्वरकों के उत्पादन मे 45 से 101 प्रतिशत तक वृद्धि की है और वे इसका उपयोग विवेकपूर्वक करते हैं । क्या अपने देश में अपने लोगों को उसी तरह उर्वरकों का उपयोग करने के बारे में बताने के लिये किसी एजेंसी की स्थापना की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : देश भर में एक कार्यकुशल और विस्तृत एजेंसी है । मांग तो है परन्तु प्रश्न उपलब्धता का है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : उर्वरकों की अपर्याप्त पूर्ति के अतिरिक्त, क्या उर्वरकों में बड़े पैमाने पर मिलावट की जाती है, और यदि हां, तो क्या यह समिति इस प्रश्न पर भी विचार करेगी और कुछ उपाय सुझायेगी जिससे उर्वरकों में मिलावट न हो सके ।

श्री शाहनवाज खां : यदि समिति से ऐसी कोई शिकायत की जायेगी, तो वे अवश्य इस मामले पर भी विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यह समिति इस पहलू पर भी विचार करेगी ।

श्री शाहनवाज खां : मैं नहीं जानता कि उनको इस बारे में विशेष रूप से कहा गया है ।

श्री दाजी : एक अध्ययन दल ने पहले ही अपनी सिफारिशें दे दी हैं । अब एक और समिति इन सभी बातों पर पुनः विचार करने जा रही है । मैं नहीं समझता हूं कि इस दूसरी समिति को स्थापित करने का प्रयोजन क्या है? क्या इसकी स्थापना उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये की गई है अथवा यह उसी विषय पर नये सिरे से विचार करेगी जिस पर एक अध्ययन दल ने पहले ही रिपोर्ट दे दी है ?

श्री शाहनवाज खां : यह समिति उर्वरकों के वितरण, उत्पादन, आयात आदि सभी पहलुओं पर विचार करेगी ।

श्री दाजी : और फिर एक तीसरी समिति इन सिफारिशों की क्रियान्विति के प्रश्न पर विचार करेगी ।

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं, कोई तीसरी समिति स्थापित नहीं की गई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका के दैक्टेल कार्पोरेशन के साथ मिल कर विशाल उर्वरक कारखानों को स्थापित करने की योजना खटाई में पड़ गई है और यदि हां, तो क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न पैट्रोलियम और रसायन मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

श्री रंगा : यह अच्छा हुआ कि इस समय वित्त मंत्री जी अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं । इसको ध्यान में रखते हुए जो कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मांग की तुलना में पूर्ति कम है और खाद्य और कृषि मंत्री यह शिकायत करते रहे हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिये पर्याप्त संख्या में कारखानों को स्थापित करने के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं की गई है, तो वित्त मंत्री जी चौथी योजना में आवंटन पर विचार करते समय क्या कदम उठाना चाहते हैं. .

अध्यक्ष महोदय : वह अब खाद्य मन्त्री के रूप में उत्तर दे रहे हैं ।

श्री रंगा : वह वित्त मन्त्री भी तो हैं । इसीलिये तो मैंने प्रश्न को यह कहते हुए आरम्भ किया है कि यह अच्छा है कि वह प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं । इस प्रश्न का उत्तर दो मंत्रियों द्वारा दिये जाने की बजाये वह अकेले दोनों मंत्रालयों के उत्तर दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री रंगा : यह देखने के लिये वह कौनसे कदम उठाना चाहते हैं कि यह त्रुटि दूर हो और हमारे देश में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उन आवश्यक वस्तुओं के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन को पर्याप्त प्राथमिकता दी जाये ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उर्वरकों को अत्यधिक महत्व देने की बात को स्वीकार किया गया है । तीसरी योजना के 800,000 मीट्रिक टन नाइट्रोजन के लक्ष्य को पूरा किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है, इसका उत्पादन 500,000 मीट्रिक टन अथवा इससे कुछ अधिक होगा । चौथी योजना के लिये 15 अथवा 20 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं । यदि हम 20 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखें तो बहुत अच्छा रहेगा ।

विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में दो पहलू हैं । एक उर्वरकों के आयात के लिये विदेशी मद्रा जुटाने का है। मैंने इस वर्ष इस बारे में भरसक प्रयत्न किये हैं परन्तु उर्वरकों का अतिरिक्त आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा जुटाने में गम्भीर कठिनाई है । जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है, यदि कारखाने स्थापित करने की बात है तो विदेशी मुद्रा के आवंटन में इसको उच्च प्राथमिकता दी जाती है । सरकार इस मामले की ओर ध्यान दे रही है । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि इस मामले के बारे में हमें भरसक प्रयत्न करने चाहियें ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सरकार ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत उर्वरकों के सम्भरण के लिये कहा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : पी० एल० 480 के अन्तर्गत उर्वरक नहीं आते हैं ।

श्री बड़े : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि उर्वरकों के वितरण सम्बन्धी प्रश्न पर एक समिति विचार कर रही है । जब तक यह समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करती तब तक इस की क्या

स्थिति रहेगी ? उर्वरकों के वितरण के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से कई शिकायतें आई है। क्या सरकार इनका निवारण करने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां, जब भी कोई विशिष्ट शिकायत हमारे ध्यान में लाई जाती है तो हम उपचारीय कार्यवाही करते हैं।

Shri Yashpal Singh : It had been stated in this hon. House by the Government, the well-wisher of farmers, sometime back that while fertilizers are being imported from USA@Rs. 250/-per ton. it is supplied to farmers @Rs. 400 per ton. i.e. at a profit of Rs. 150/- per ton. May I know whether any reduction has been made in this profit ? Will the committee make any recommendation that this profit should not be taken from the farmers ?

Shri Shahnawaz Khan : The committee would look into this matter also.

Shri Rameshwaranand : We are unable to import fertilisers for want of requisite foreign exchange. I had drawn your attention to this matter earlier also that after the application of fertilisers, if water is not available, the crops simply withered away and by continuous application of fertilisers, the land becomes less fertile, In view of this whether the Government are considering to make use of dung of cows, buffalos, goats and sheep for which no foreign exchange is required and it also makes the land more fertile ?

Shri Shahnawaz Khan : Thank you for this useful opinion. We would look into this matter also.

Shri Vishram Prasad : Fertilisers are being dumped where there are no irrigation facilities and fertilisers mixed with salt are sold. Sal ammoniac is also being prepared out of it. Will the Committee look into all these things also.

Shri Shahnawaz Khan : I would be grateful to him if the hon. Member gives some such specific cases to me.

Shri Vishram Prasad; I would give him.

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has just said that the supply is not enough to cope with the demand, but on the contrary we come accross some reports. Have the Government received any complaint from Uttar Pradesh to the effect that fertilisers are forced on the farmers and those who do not accept it, are not given loans from the co-operatives ; and if so, what are the Government doing in regard thereto ?

Shri Shahnawaz Khan : Both types of complaints have been received. Some say that it is not available and some say that it is forced on them. Whenever such compaints are received, they are looked into.

Shri K. N. Tiwary : On the one hand you say that it is not available and on the other hand the Sindri Fertilisers factory has suffered a loss of Rs. 2 crores and this loss is due to the fact that the raw material is not being made available to them by import for want of foreign exchange. But we are importing fertilisers after spending more foreign exchange.....

Mr. Speaker : You are arguing.

Shri K. N. Tiwary: Will the Government make such arrangements so that more fertilisers are produced at Sindri Factory ?

Shri Shahnawaz Khan : The Government are increasing the number of fertiliser factories.

टिड्डी नियंत्रण

+

*929. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री विश्वनाथ पाण्डय :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पौदा रक्षण और टिड्डी कार्यों के लिये और विमान खरीदने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने; इस पर कितना व्यय होगा तथा वे किन स्थानों पर रखे जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, कुछ और विमान खरीदने या किसी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

(ख) विवरण तैयार किया जा रहा है । ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether tear gas can be used for locust-control ?

Shri Shahnawaz Khan : I may tell the hon. Member that the aircraft is meant for destroying insects and not for bringing tears in the eyes of the people.

Shri Yashpal Singh : Would these aircrafts be imported or would be manufactured here in our H.A.L. Factory ?

Shri Shahnawaz Khan : These are imported from abroad.

Shri Vishwa Nath Pandey : What would be their cost ?

Shri Shahnawaz Khan : Our intention is to purchase 18 more aircrafts and their cost works out to be about 26 lakhs of rupees.

श्री दी० चं० शर्मा टिड्डी नियन्त्रण के लिये अपर्याप्त व्यवस्था के कारण हमें प्रत्येक वर्ष कितनी हानि उठानी पड़ती है ? क्या पिछले कुछ वर्षों में इस हानि में वृद्धि हो रही है अथवा इसमें कमी हो रही है ?

श्री शाहनवाज खां : अनुमान है कि टिड्डियों, रोगों और मारकों के कारण हमारी फसलों को 10 से 15 प्रतिशत अर्थात् 1,000 करोड़ रुपये की हानि होती है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हानि में वृद्धि अथवा कमी हो रही है ।

श्री शाहनवाज खां : हम इसको कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri R.S. Pandey: May I know whether besides these aircrafts which you are importing from abroad, in what other way you are thinking to solve this problem ?

Shri Shahnawaz Khan: The first is that in order to destroy locust spray is done by aircrafts and secondly the hoppers are burried in the trenches before their feathers grow.

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने एक विमान विशेष रूप से इन कार्यों के लिये बनाया है । इस को ध्यान मे रखते हुए हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड से खरीदने की बजाये इन विमानों को बाहर से मंगवाने के क्या कारण हैं ?

श्री शाहनवाज खां : यह एक विशेष रूप का विमान है और इसमें विशेष गीयर लगे होते हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या उन्होंने हिन्दुस्तान एयरक्राफट लिमिटेड से सलाह की थी ?

श्री शाहनवाज खां: स्थानीय विमान इतने नहीं हैं कि हम उन्हें खरीद सकें ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Do the Government think it proper that the crops should be got insured because it can be advantageous ?

Mr. Speaker : No one would insure the crops against locusts.

Shri Bade : It is in the report that if the crops are destroyed by locusts, such crops should, at once be, got insured. What have you considered about it ?

Mr. Speaker: This question relates to import of aircrafts and as such this question does not arise.

श्री कन्डप्पन: क्या सरकार ने किसानों को थोड़ी शक्ति वाले स्प्रेयर देने की कोई योजना बनाई है ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां । इस देश में स्प्रेयर बनाने के लिये पहले ही एक योजना है ।

Postal Services in Villages

***930. Shri Tan Singh:** Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the Posts and Telegraphs Department has been consulted regarding the possibilities of postal services being handled by the Village Panchayats ;

(b) if so, the reaction thereto ;

(c) whether any experiments have been made in carrying out the postal services through panchayats ; and

(d) if so, the result thereof ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :(क) जी हां। सन् 1960 में डाक तथा तार विभाग को सुझाव दिया गया था कि अतिरिक्त विभागीय डाकघर चलाने की जिम्मेदारी उन पंचायतों को सौंपी जाए जो इसके लिए कहे।

(ख) डाक तथा तार विभाग ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Tan Singh : May I know the reasons given by Posts and Telegraphs for not accepting this suggestion and whether this Ministry is satisfied with those reasons ?

श्री ब० सू० मूर्ति : डाक तार विभाग ने कहा कि वह इन अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को चलाने की जिम्मेवारी उनको सौंपना पसन्द नहीं करेगा जब कि वह पंचायतों से सभी सहायता लेना पसन्द करेगा।

Shri Tan Singh : What are those items on which Posts and Telegraphs have sought assistance and whether the panchayats are prepared to extend that ?

श्री ब० सू० मूर्ति : उन्होंने कुछ नहीं दिया है।

Shri Gauri Shankar Kakkar : Is the Minister aware that similar work is got done by the primary school teachers. What difference does it make if this Panchayats do it and whether P. & T. have given any suggestion in this regard ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी हां। अतिरिक्त विभागीय डाकघरों से अभिप्राय पूर्ण डाकघर को स्थापित करने की लागत को कम करने का है और इसलिये उनसे यह शर्त तय की गई है कि उन्हें कुछ घंटों के लिये काम करना होगा। अध्यापकों, कारनामों और अन्य व्यक्तियों को इस काम के लिये रखा जाता है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि डाक विभाग डाकघरों को यत्रों और सरपंचों को इसलिये देने से इंकार करता है कि उनमें से अधिकांश अनपढ़ हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : पंचों और सरपंचों को डाकघरों को सौंपने का प्रश्न नहीं उठा था। पंचायतों को सौंपने की बात थी।

श्री दी० चं० शर्मा : पंचायतें और क्या हैं यदि पंच और सरपंच नहीं हैं ?

श्री श्रीनारायण दास : क्या पंचायतराज मन्त्रालय को सुझाव दिया गया था और क्या मन्त्रालय ने डाक विभाग को यह सुझाव भेजने से पहले इसकी जांच करा ली थी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी नहीं। अधिक संख्या में अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के खोलने को सुविधाजनक बनाने के लिये पंचायतों की सेवा लेने का प्रश्न मन्त्रालय ने ही उठाया था।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : डाक घर का कार्य लेने के बाद सरपंच का पदनाम क्या होगा ? क्या उसको सरपंच ही कहा जायेगा अथवा पोस्ट मास्टर ?

श्री दाजी : अब जब कि पंचायतों को भू-राजस्व इकट्ठा करने के अधिकार दिए गए हैं और अनेक मामलों में वे इसको सफलतापूर्वक कर रही है; क्या पंचायत मन्त्रालय डाक तार विभाग के नकारात्मक उत्तर से सन्तुष्ट हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सू० कु० डे) : हम तो यह चाहते हैं कि डाक विभाग ही नये डाक घर खोलें और मैं समझता हूं कि गांवों में डाकघरों को स्थापित करने का उनका कार्यक्रम योजना के अनुसार चल रहा है ।

Shri Rameshwaranand: What are the reasons for not entrusting the work of post offices to panchayats when they are prepared to accept the same pay as the teachers ?

श्री सु० कु० डे : डाकघरों को पंचायतों को सौंपने का प्रश्न अध्यापकों से डाकघरों में कुछ समय के लिये काम लेने के प्रश्न से सर्वथा भिन्न है ।

Shri Bade: His question was different which the hon. Minister could not follow.

Mr. Speaker: What I have understood is this when we are taking work from the teachers by paying them some remuneration, then what is the necessity of entrusting this work to the panchayats.

Shri Rameshwaranand: My question was that why this postal work is not given to the panchayats when they are prepared to charge the same remuneration as given to the teachers ?

श्री ब० सू० मूर्ति : किसी भी अवस्था पर वेतन का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं रहा है । अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को पंचायतों को सौंपने के लिये कहने में मन्त्रालय का उद्देश्य ग्रामीण लोगों की सेवा करने का था । वेतन का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : यदि पंचायतों को डाकघरों का काम सौंप दिया जाये और वे इसमें सफल न हों तो ऐसी स्थिति में डाकघरों का काम उन व्यक्तियों को सौंपने के प्रबन्ध किये गये हैं जिन्होंने वर्तमान पंचों को अपना मत नहीं दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : डा० सरोजिनी महिषी ।

डा० सरोजिनी महिषी : इस सम्बन्ध में पंचायत डाक विभाग को किस प्रकार की सेवाएं देना चाहती हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : डाक और तार विभाग को लोगों के सहयोग से और उनकी सहायता से जहां भी जरूरत हो पंचायतों की सेवाएं चाहिये थीं ।

ग्रामीण ऋण

931. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक के अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा विनियोजन सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार 1961–62 में देश में खेतिहर परिवारों का कुल ऋण लगभग 1030 करोड़ रुपये का था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये ऋण मुख्य रूप से उन लोगों से लिये जाते हैं जो अत्यधिक ब्याज लेते हैं; और

(ग) जरूरतमंद किसानों को आसान शर्तों पर तथा आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 1030 करोड़ रुपए के ऋण में से लगभग 244 करोड़ रुपए सहकारी ऋण के थे और लगभग 22 करोड़ रुपए सरकारी तकावी ऋण के थे। निश्चित जानकारी उपलब्ध न होने के कारण यह कहना सम्भव नहीं है कि दूसरी किस्म के ऋण अत्यधिक ब्याज लेने वालों से लिए गए थे।

(ग) किसानों को बढ़ती मात्रा में ऋण सुलभ करने के लिए सहकारी ऋण के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। फसल ऋण पद्धति के अन्तर्गत सहकारी ऋणों को उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुस्थिर रूप से लगाया जा रहा है। 1963–64 में सहकारी ऋण (अल्प, मध्य तथा दीर्घकालीन) की मात्रा लगभग 310 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या किसान मालिकों, दूरवासी जमींदारों और भूमिहीन मज़दूरों के बीच अनुपात का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है?

श्री शिन्दे : सर्वेक्षण समय समय पर किये जाते हैं, परन्तु इस समय उपलब्ध आंकड़ों से निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि जमींदारों, दूरवासी जमींदारों और भूमिहीन मज़दूरों के बीच कितना कितना ऋण बंटा हुआ है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : अब चूंकि सर्वेक्षण कर लिया गया है, यह विशिष्ट जानकारी एकत्र कर ली जानी चाहिये थी। जरूरतमन्द काश्तकारों अथवा किसानों को ऋण देने के लिये और क्या प्रयत्न किये जायेंगे और दूसरे यह पता लगाने के लिये कि बार बार कौन ऋण लेते हैं ताकि उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके?

श्री शिन्दे : ऋण के विस्तार की प्रवृत्ति को देखने से पता चलता है कि अधिकांश ऋण वास्तविक काश्तकारों द्वारा लिया जाता है। ऋण का विस्तार काफी तेज़ी से हो रहा है। 1951–52 में ऋण की मात्रा 27 करोड़ रु० थी, और गत वर्ष के अन्त तक यह संख्या 310 रु० तक पहुंच गई है।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : सरकार द्वारा सरल शर्तें और सुविधाएं दिये जाने के बावजूद भी सरकार गरीबों और जरूरतमन्दों को महाजनों के पंजों से छुटा नहीं सकी है। क्या सरकार ने इसके कारणों के अध्ययन करने का प्रयत्न किया है?

श्री शिन्दे : इस समय लगभग 40 प्रतिशत काश्तकार सहकारी ऋणों के अन्तर्गत आते हैं। 1951–52 में जब कि प्रथम ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण किया गया था तो यह सहकारी ऋण केवल 3 प्रतिशत था जो कि इस समय लगभग 25 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि महाजनों द्वारा ऋण दिया जाना आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है।

श्री इकबाल सिंह : किस जिले में सब से अधिक ऋण दिया जाता है और क्या यह सच है कि अधिकतम ऋण उन जिलों में है जहां पर गैहूं पैदा होता है और काश्तकारों को उनके उत्पादन का मूल्य नहीं मिलता है ?

श्री शिन्दे : इस समय ऋण को उत्पादन के साथ लिया जाता है । स्वभावतः जिन क्षेत्रों में रोक फसलें उगाई जाती हैं वहां पर अन्य जिलों की अपेक्षा ऋण की मात्रा अधिक है ।

श्री हेडा : क्या सरकार को इसका पता है कि देश के कुछ भागों में, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात सहकारी ऋण योजना बहुत अच्छी तरह चल रही है जब कि अन्य भागों में पार्टीबाज़ी होती है और यदि हां, तो क्या उपचारीय उपाय किये जा रहे हैं ताकि जरूरतमन्द किसानों को जो अधिक उत्पादन करना चाहते हैं सरलता से ऋण मिल सके ?

श्री शिन्दे : उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं । वास्तव में, हम ने सुझाव दिया है कि फसल ऋण पद्धति को सारे देश में लागू किया जाये । इसको महाराष्ट्र गुजरात और कुछ अन्य राज्यों में सफलता मिली है । इसके अतिरिक्त, वास्तव में हम समितियों और समूचे ऋण ढांचे में जीवन डालना चाहते हैं ।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : यह बहुत हद तक सहकारी लीडरी पर निर्भर करता है जिसका लाना सरल नहीं है ।

श्री कन्डप्पन : क्या सरकार को पता है कि काश्तकारों की गरीबी की हालत को देखते हुए उनसे ऋणों पर जो ब्याज लिया जाता है वह बहुत ऊंचा है ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार यह जानती है यह एक तथ्य है ।

श्री कन्डप्पन : क्या सरकार का इस बारे में भी कुछ करने का विचार है?

श्री शिन्दे : इस मामले पर एक समिति ने विचार किया था जिसने तकावी और सहकारी ऋण की समस्या की जांच की थी । इसने सुझाव दिया है कि कुछ क्षेत्रों से जहां कि ब्याज ऊंचा है उसको घटाया जाय । भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और हमने उनको राज्य सरकारों को भेज दिया है ।

श्री रंगा : क्या सरकार ने इसका अनुमान लगाया है कि गुजरात की कुछ सहकारी समितियों को परिक्रामी ऋण द्वारा अब तक क्या सफलता मिली है इस ऋण के द्वारा किसान को कुछ राशि के ऋण की पेशकश की जाती है, परन्तु वह इसको तुरन्त ही नहीं ले सकता है । यह स्थानीय बैंक के साथ है । जब उसको आवश्यकता होती है वह रकम लेता चला जाता है और जब उसके पास कुछ फालतू पैसा होता है तो वह उसे वापस कर देता है । इस प्रकार कृषि प्रयोजनों के लिये उसे हमेशा आवश्यक ऋण मिल सकता है ।

श्री शिन्दे : जैसा कि मैं ने बताया, गुजरात में मुख्यतः फसल ऋण पद्धति को अपनाया जाता है । मान लीजिये कोई किसान विभिन्न फसलें उगाता है, स्वभावतः फसलों की आवश्यकता के अनुसार ऋण दिये जाते हैं । शायद माननीय सदस्य उसी का जिक्र कर रहे हैं ।

आदिम जाति खंडों में सड़कें

*932. **श्री ह० च० सोय** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में आदिम जाति खण्डों में सड़कों का सुधार करने, सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने तथा माध्यमिक स्कूल खोलने की आवश्यकतायें अत्यधिक अनुभव की जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यय की विभिन्न मदों के अन्तर्गत बड़ी राशियों का व्यय तथा उपयोग करना शेष है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो आदिम जाति के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु राशियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) हां, ये अत्यधिक अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं में से हैं :

(ख) हां ।

(ग) पूर्तियां ना होने का कारण है कि आदिम जातियों ने कल्याणकारी योजनाओं के प्रति अगुए बन कर अपने भाग का अंशदान नहीं दिया । आदिम जातियों की बुरी आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पीने के पानी की योजनाओं के प्रति सार्वजनिक अंशदान की शर्तों को हटा दिया है और दूसरी योजनाओं के लिये अंशदान हटाने के लिये मामला सरकार के विचाराधीन है । बिहार सरकार ने एक विशेष कार्य-क्रम चालू किया है जिस से आशा है कि मंजूर की हुई राशि भविष्य में पूरी तरह से काम में लाई जाएगी ।

Shri H. C. Soy : May I know whether Government are aware and if not whether Government will get it investigated that there are two main reasons for not utilising the grants given to these people *i.e.* (1) The B.D.O. etc., the supervisory staff is not trained in a manner as would generate sympathy in them towards these people, and (2) these people are so poor that they cannot give shramdan when asked to do it for completing certain work ? Do Government propose to go into this question ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं अपने उत्तर में पहले ही बता चुकी हूं कि पीने के पानी को देने की योजनाओं के लिये हम ने अंशदान को हटा दिया है । आदिम क्षेत्रों में जो अन्य योजनाएं आरम्भ की गई हैं उनके लिये अंशदान हटाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या एक कारण यह है कि गरीबी के कारण वे श्रमदान नहीं कर सकते ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह सच है । यही मुख्य कारण है कि हमने एक योजना में अंशदान को हटा दिया है । अन्य योजनाओं के संबंध में भी हम इसको हटाने पर विचार कर रहे हैं ।

Shri H. C. Soy : I had asked about giving training to the supervisory staff.

श्रीमती चन्द्रशेखर : जो व्यक्ति आदिम जातीय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जिनसे वहां काम करने की आशा की जाती है उनको आदिम जातीय कार्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको इसके लिये तैयार भी किया जाता है ।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या माननीय मंत्री को पता है कि बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में ऐसा नहीं किया गया है और यह अत्यावश्यक है कि ऐसा किया जाये और इसलिये कुओं आदि का कोई काम नहीं किया जा रहा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : बिहार सरकार ने एक विशेष कार्यक्रम चालू किया है और हम आशा करते हैं कि आवंटनों का पूर्ण उपयोग किया जायेगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : Has the attention of this Ministry been drawn to the fact that the officers and particularly those belonging to Community Development who go in the villages differ very much with the masses in respect of their language and dress and that is the reason for their not succeeding in their work ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी, नहीं । खण्ड विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी जिनसे आदिम जातीय क्षेत्रों में काम करने की आशा की जाती है उनको आदिमजातीय भाषाएं सीखनी पड़ती हैं और इसके लिये उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है ।

श्री बसुमतारी : माननीय उपमंत्री ने कहा कि आदिम जातीय लोग अवसर का फायदा नहीं उठा सके हैं और इस लिये उन्हें योजनाओं से लाभ नहीं हुआ है । सके लिये कि वे लोग इस अवसर का फायदा उठायें उनको आगे लाने के लिये सरकार ने किस व्यवस्था पर विचार किया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : क्योंकि आदिम जातीय लोग अंशदान नहीं दे सकते थे इसलिये कार्यक्रमों को पूर्णरूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका और सफलता नहीं मिल सकी । अब हम ने जनता के अंशदान को हटा दिया है । इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं कह सकती हूं ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : आदिम जातीय क्षेत्रों में रहने वाले इन लोगों के पिछड़ेपन और अनक्षरता को ध्यान में रखते हुए, इन लोगों को आगे लाने और आदिम जातीय खण्डों में विकास कार्यों के साथ उनका संबंध पैदा करने के लिये उनको क्या ठोस प्रोत्साहन दिये जाते हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : सभा इससे अवगत है कि ये आदिम जातीय खण्ड सामुदायिक विकास खण्डों जैसे ही हैं । परन्तु आदिम जातीय खण्डों में छोटे-छोटे क्षेत्र हैं, कम व्यक्ति और अधिक धन और आदिम जातीय विकास के लिये विशेष कार्यक्रम निर्धारित हैं ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : प्रोत्साहन क्या है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इन कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए सार्वजनिक अंशदान को हटाना एक प्रोत्साहन होगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Is it a fact that the tribal people are not benefiting properly by the aid and co-operation which is given by the Centre to the Madhya Pradesh tribal people ? Have the Government received any complaint to this effect ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह बता सकती हैं कि क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यदि किसी विशिष्ट शिकायत की सूचना हमें दी जायेगी तो हम उसकी जांच करेंगे ।

चीनी निर्यात सम्बन्धी नीति

*933. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 16 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 455 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के निर्यात के फलस्वरूप 1965 में होने वाली विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय के भारतीय चीनी मिल्स एसोसियेशन को दी जाने वाली अनुमानित सहायता से कम होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी चीनी के निर्यात की नीति में कोई उलटफेर करने के बारे में विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) इस समय शर्करा के अन्तर्राष्ट्रीय भाव कम चल रहे हैं।

(ख) पूर्वानुमान लगाना कठिन है ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में कहा कि इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है । मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह प्रवृत्ति जारी रहेगी और यदि हां, तो क्या सरकार अधिक सहायता देने सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने का विचार कर रही है क्योंकि कमाई जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि को देखते हुए इतनी अधिक सहायता देना उचित नहीं है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मेरे सहयोगी बता चुके हैं कि पूर्वानुमान लगाना कठिन है । चूंकि हम अमरीका तथा अन्य देशों को चीनी भेजने का वचन दे चुके हैं अत: हमें उसका पालन करना होगा । यदि मूल्य गिर जाने के कारण हम इस समय चीनी नहीं भेजते हैं तो फिर हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी चीनी की खपत नहीं कर पायेंगे । अत: सरकार को कुछ हानि उठानी ही पड़ेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार समूचे चीनी उद्योग को सहायता देती रहेगी और क्या गन्ना उत्पादकों को भी गन्ने के अधिक मूल्य के रूप में सहायता देगी?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: इस समय चीनी का मूल्य जहाज में लदान करते समय 960 रुपये प्रति टन है। गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य देने के कारण इस मूल्य में 150 रुपये प्रति टन की वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तथा देश के अन्दर मूल्यों में अन्तर होने का यह भी एक कारण है। यदि हम गन्ना उत्पादकों को और अधिक देंगे तो यह अन्तर और भी बढ़ जायेगा।

Shri Vishram Prasad: May I know the quantity of sugar to be supplied to America, at what rate it will be supplied and when it is likely to be supplied?

श्री दा० रा० चह्वाण: 91,000 ट०। 585 रुपये प्रति टन की दर पर।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : चीनी मिल एसोसिएशन को चीनी का निर्यात करने के लिए कितनी रियायत दी गई है और क्या किसानों को निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कोई प्रोत्साहन दिया गया है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: मैं बता चुका हूं कि किसानों को अधिक मूल्य देने के कारण थोड़े ही समय में चीनी के मूल्य बहुत बढ़ गये।

श्री स० मो० बनर्जी : भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि हम निर्यात के लिए अब तक दिये गये वचन पूरे करेंगे किन्तु भविष्य में हम निर्यात के लिए वचनबद्ध नहीं होंगे। क्या यह सच है कि 1965 में भी निर्यात के लिए और समझौते किये गये और यदि हां, तो देश को हानि पहुंचा कर ऐसा क्यों किया गया?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अमरीका को 91,000 टन भेजने के लिए समझौता किया गया। इस प्रकार अमरीका को 127,000 टन चीनी भेजी जायेगी। वहां पर अन्य देशों की अपेक्षा चीनी के मूल्य अधिक हैं। ऐसा हमने अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में अपनी चीनी की मांग को और मूल्यों को बनाये रखने के लिए किया है। हमें कुछ मूल्य बढ़ने की आशा है। पिछले हफ्ते यह मूल्य 23 पौंड था आशा है इसमें वृद्धि होगी क्योंकि एक बार इसमें 100 पौंड तक की वृद्धि हुई थी।

Committees for Implementation of Hindi

\+

*934. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri P.L. Barupal :
Shri Rameshwaranand :
Shri Utiya :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Committees for the implementatipn of Hindi Scheme have been constituted in his Ministry and in its sub-ordinate and attached offices in pursuance of the orders of the Ministry of Home Affairs ;

(b) the number of meetings held and the details of the work done by these Committees in those offices where they have been duly constituted ; and

(c) if the Committees have not been formed in some offices, the reason therfor ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Such Committees have been constituted in the Ministry as well as in a number of its Attached and Subordinate Offices.

(b) In all 19 meetings have been held in the various Offices. At these meetings the progress of implementation of the instructions received from the Ministry of Home Affairs from time to time were discussed and decisions taken, as considered necessary, for the further implementation of those instructions.

(c) Committees have been formed in 29 Offices. They could not be formed in the remaining Offices because either some of these Offices are still in the process of formation (such as the Agricultural Prices Commission) or they are too small to require separate Hindi Committees. However, these Offices are also examining the matter.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the total number of offices in which such Committees have not so far been constituted and the time by which they will comply with the orders of the Ministry of Food and Agriculture and the Ministry of Home Affairs in this respect ?

Shri Shah Nawaz Khan : I have already stated that only few small offices have so far not constituted such committees.

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether the circular issued by the Ministry regarding the use of Hindi words such as *SACHIV* for Secretary and *UP-SACHIV* for Deputy Secretary, was unconstitutional and if not, the reasons for withdrawing it ?

Shri Shah Nawaz Khan : We generally follow the instructions issued by the Ministry of Home Affairs.

Mr. Speaker : This is no answer to the question asked by the hon. Member. He wants to know that why that circular was withdrawn.

Shri Shah Nawaz Khan : I have no information about it at this stage. I want notice for it.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

किसानों को ऋण

*928. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के खाद्य निगम ने किसानों को ऋण देने के लिये कार्यवाही की है ताकि अनाज का अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके ;

(ख) क्या क्षेत्रफल का विचार किये बिना ऋण के रूप में नियत राशि देने की विद्यमान प्रणाली के स्थान पर उन भूमियों के क्षेत्रफल के अनुपातानुसार जिसमें खेती करने का विचार हो ऋण देने की प्रणाली अपनाई जा रही है ; और

(ग) क्या निगम ने किसानों द्वारा काटे जाने वाले अनाज के लिए अग्रिम भुगतान करने का निश्चय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)--(खाद्य तथा कृषि मंत्री की ओर से) : (क) से (ग). भारत का खाद्य निगम कृषकों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं देने के प्रश्न की जांच कर रहा है और इस उद्देश्य के लिये, एक समिति जिसमें अध्यक्ष, कृषि, खाद्य तथा सहकारिता विभाग और रिजर्व बैंक का एक एक प्रतिनिधि है, गठित की है।

बिहार में गन्ने की पिराई

*935. **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार के चम्पारन जिले में 10 लाख मन गन्ना बिना पिरा पड़ा है; और

(ख) मांग की कमी से उत्पन्न इस संकटपूर्ण स्थिति में फंसे हुए संबंधित किसानों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). बिहार सरकार ने सूचित किया है कि जिला चम्पारन के कुछ कारखाना क्षेत्रों में कुछ गन्ना फालतू है और वह गन्ना पास-पड़ौस के अन्य शर्करा कारखानों को भिजवा दिया गया है। राज्य सरकार यह आशा करती है कि इस सीजन में शर्करा कारखानों के बन्द होने से पहले सारा गन्ना पेरा जाएगा ।

चीनी का उत्पादन

*936. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में चीनी के उत्पादन की अन्तिम स्थिति क्या थी ;

(ख) देश में कितनी चीनी मिलें अब भी काम कर रही हैं; और

(ग) मिलों, सरकार तथा व्यापारियों के पास इस समय चीनी का कितना स्टाक है और उसके निर्यात किये जाने की क्या सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 1964-65 में 7 अप्रैल तक 27.19 लाख मीट्रिक टन शर्करा का उत्पादन हुआ ।

(ख) 15 अप्रैल, 1965 को 132 ।

(ग) 7 अप्रैल, 1965 को फैक्ट्रियों के पास 17.43 लाख मीट्रिक टन शर्करा का स्टाक था । सरकार अपने पास कोई स्टाक नहीं रखती है । शर्करा वितरण पर नियंत्रण होने के कारण व्यापारियों के पास वही स्टाक होता है जो कि राज्य सरकार उनको तुरन्त वितरण करने के लिए एलाट करती है। 1965 में 2.5 लाख मीट्रिक टन शर्करा निर्यात करने का अनुमान है ।

अनाज के भाव

*937. **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कपूर सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मोहसिन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं तथा अन्य अनाजों के भाव बढ़ने आरम्भ हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भावों को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भावों के बढ़ने का कारण आयातित गेहूं का न मिलना बताया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो आयात किया हुआ गेहूं उपभोक्ताओं को कब तक दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी—खाद्य तथा कृषि मंत्री की ओर से) : (क) और (ख). जनवरी, 1965 से गेहूं के भावों में बराबर कुछ कुछ गिरावट आने के बाद फिर बढ़ोतरी का रूख आया है और हाल ही के सप्ताहों में गेहूं और कुछ मोटे अनाजों के भावों में कुछ वृद्धि हुई है। यह एक अस्थायी दौर है और आगामी कुछ सप्ताहों में मंडियों में नई फसल के आने से गेहूं के भावों में गिरावट आने की सम्भावना है ।

(ग) और (घ). अमरीकी बन्दरगाहों पर हड़ताल होने के कारण फरवरी और मार्च में आयातित गेहूं की आमद अपेक्षाकृत कम रही थी । तथापि, अब से आगे भारी मात्रा में आयातित गेहूं के आने की आशा है और कमी वाले राज्यों की उपयुक्त आवश्यकताएं पूरी करने में कोई कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है।

Impact of Food Zones on prices

*938. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the question of impact of food zones on prices has been studied;

(b) if so, the result thereof ; and

(c) if not, when the arrangements would be made to study the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan) : (a) to (c). The effect of the zonal arrangements on supply to deficit areas and price levels both in deficit and surplus areas is being reviewed from time to time. The creation of food zones helps in conserving supplies in more or less self-sufficient zones and therefore in stabilising prices in those zones. In surplus States the zonal arrangements help the Government in procuring foodgrains at reasonable prices for distribution in the deficit States. Although the zonal arrangements restrict the flow of foodgrains from surplus to deficit areas resulting in slightly higher prices than under free trade conditions the balance of advantage lies in maintaining suitable food zones so long as the supply of foodgrains lags behind the demand.

पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय प्रबन्ध

*939. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचायती राज संस्थाओं के लेखे रखने तथा वित्तीय प्रबन्ध की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने वित्तीय मामलों में इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो दल की टिप्पणियां तथा उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) सरकार का विचार इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की जांच सम्बन्धी अध्ययन टोली की महत्वपूर्ण सिफारिशों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । अध्ययन टोली की रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं । **[देखिए संख्या एल० टी० 4214-65]** ।

(ग) अध्ययन टोली की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

बम्बई के नाविकों द्वारा हड़ताल की धमकी

*940. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के 5000 नाविकों ने धमकी दी है कि यदि उनकी वेतन में वृद्धि करने की मांग स्वीकार नहीं की गई तो वे हड़ताल करेंगे, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनाज की वसूली

*941. **श्री मलाइछामी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 6 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 747 के उत्तर के समबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस प्रेस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अनाज के भाव निर्धारित करने से स्फीति बढ़ सकती है; और

(ख) यदि हां, तो स्फीति बढ़ाये बिना अनाज की वसूली बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) खाद्य तथा कृषि मंत्री की ओर से : (क) और (ख). माननीय सदस्य ने सम्भवतया कुछ खाद्यान्नों के लिये निर्धारित अधिकतम भावों के सम्बन्ध में कुछ समाचार पत्रों में हुई आलोचना की ओर ध्यान दिलाया है। सरकार इस आलोचना को उचित नहीं समझती है।

दिल्ली में राशन व्यवस्था

*942. **श्री प्र. चं. बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने हाल में यह अनुरोध किया है कि दिल्ली में, जो अपनी खाद्य आवश्यकता के लिए मुख्यतया उस राज्य पर निर्भर है, राशन व्यवस्था लागू की जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण का पुनर्गठन

*943. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **विधि** मंत्री आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरणों के पुनर्गठन संबंधी 1 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 291 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मामला अभी विचाराधीन है ।

चीनी मूल्य जांच आयोग

*944. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री विभूति मिश्र :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 15 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 513 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच चीनी मूल्य जांच आयोग ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है ·

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

उचित मूल्य की दुकानों का लूटा जाना

*945. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में देश में, राज्यवार, उचित मूल्य की दुकानों को लूटने की कितनी घटनाएं हुईं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) केरल में दो और सूर तथा उत्तर प्रदेश में तीन-तीन दुकानें लूटी गयीं ।

(ख) इन लूटी गयी दुकानों में से एक दुकान दुकानदार के बुरे बरताव और एक दूसरी दुकान खाद्यान्नों के देने में देरी हो जाने के कारण लूटी गयीं। अन्य मामले अस्थायी रूप से कम सप्लाई की स्थिति का लाभ उठाकर, कुछ शरारती या समाज विरोधी व्यक्तियों के उकसाने के कारण हुये थे। पुलिस ने अधिकांश मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार किया और सम्बन्धित न्यायालय के सम्मुख आरोप पत्र पेश किये।

बागवानी का विकास

2366. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में बागवानी के विकास के लिये राजस्थान सरकार को राज सहायता व अनुदान के रूप में कितनी राशि मंजूर की गयी तथा दी गई ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कितनी राशि दी जा चुकी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). पूछी गई जानकारी निम्न प्रकार है :–

वर्ष	ऋण	अनुदान	कुल
	रुपये	रुपये	रुपये
1961–62	3,22,000	8,387	3,30,387
1962–63	2,23,000	29,643	2,52,643
1963–64	1,24,000	69,548	1,93,548
1964–65	2,20,000	36,750	2,56,750
कुल	8,89,000	1,44,328	10,33,328

राजस्थान में स्थानीय विकास कार्य

2367. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में स्थानीय विकास कार्यों के लिये राजस्थान सरकार को कुल कितनी राशि दी गई; और

(ख) 1965–66 में इसी प्रयोजन के लिये राज्य को कितनी राशि देने की विचार है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) 1964 में स्थानीय विकास कार्यों के कार्यक्रम के लिये राजस्थान सरकार को 25.60 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय अनुदान के रूप में दी गई थी।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का व्यावसायिक प्रशिक्षन

2368. **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री उइके :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये देश में कितनी व्यावसायिक संस्थाएं काम कर रही हैं; और

(ख) क्या सरकार इन लोगों में बढ़ती हुई जागति को ध्यान में रखते हुए उक्त संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी विभिन्न राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है तथा मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

छोटे पत्तनों का सर्वेक्षण

2369. **श्री धर्मलिंगम:** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) छोटे पत्तन तलकषण तथा सर्वेक्षण संस्था ने तृतीय योजना में अब तक जिन छोटे पत्तनों का सर्वेक्षण किया है उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इस संस्था के पर्याप्त प्रगति न करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4215/65]।**

सरकारी क्षेत्र में होटल

2370. **श्री धर्मलिंगम :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटक होटल निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र में कितने होटलों के निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) वे कहां-कहां खोले जायेगे; और

(ग) वे कब खोले जायेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत पर्यटन होटल निगम पर्यटक रुचि के स्थानों पर संभवत: 17 होटल स्थापित करेगा।

(ख) पर्यटन रुचि के वे स्थान जहां भारत पर्यटन होटल निगम होटल बनायेगा :

1—बम्बई
2—कलकत्ता
3—औरंगाबाद
4—दिल्ली
5—मद्रास
6—मदुराई
7—जिमकारबेट पार्क
8—भुवनश्बेर
9—आगरा
10—हैदराबाद
11—बाराणसी
12—कोणार्क
13—मनाली

(ग) 1968 तक होटल स्थापित कर दिये जायेंगे। किसी भी स्थान पर होटल निर्माण करने का निश्चय करने के पूर्व उसके आकार प्रकार तथा औचित्यता के संबंध में भारत पर्यटन होटल निगम शक्यता अध्ययन करेगा।

होटल वालों तथा टैक्सी चालकों को ऋण

2371. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के होटल वालों तथा पर्यटक टैक्सी चालकों ने ऋण के लिये कोई प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों ने; और

(ग) कितने आवेदन पत्रों पर अनुकूल रूप से विचार किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मद्रास राज्य के टैक्सी चालकों से ऋण देने के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक होटल वालों का प्रश्न है मद्रास राज्य के होटल वालों से भी ऋण देने के लिये कोई विशिष्ट प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु उस स्रोत के बारे में अकसर पूछ ताछ की जाती है जिनमें होटल उद्योग को देने के लिये ऋण उपलब्ध है। चूंकि पर्यटक विभाग ऋण नहीं देता है इसलिये होटल वालों को राज्य वित्त निगम या औद्योगिक वित्त निगम को आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

दूध के संभरण के लिए धातु के टोकन

2372. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना का विचार राजधानी में दूध के उपभोक्ताओं के प्रयोग लिये कार्डों के स्थान पर धातु के टोकन चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) परिवर्तन के कब तक लागू होने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) धातुके टोकन चालू होने से कार्डों के समय-समय पर नवीकरण की आवश्यकता न रहेगी और इससे अनाधिकृत कार्डों के जारी होने या अधिकृत कार्डों में अनाधिकृत परिवर्तन किये जाने की संभावना समाप्त हो जायेगी।

(ग) लगभग 4-5 मास तक।

Khadi-Gramodyog Bhawan

2373. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Social Security** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 515 on the 15th December, 1964 and state :

(a) whether the Enquiry Committee appointed to investigate into the cpmplaints made against the Manager, Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi has submitted its report ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the action taken by the Khadi and Village Industries Commission on that basis ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Shri Jaganathan Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The matter is under consideration. The Manager has, however, been transferred.

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

2374. **श्री लखमू भवानी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि:

(क) क्या 1961 की जनगणना में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रत्येक समुदाय की जनसंख्या दी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक समुदाय की जनसंख्या कितनी है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) समुदाय-वार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या के दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4216/65]**

मध्य प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग

2375. **श्री लखमू भवानी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में मध्य प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं का स्वरूप क्या है; और

(ख) राज्य में इन योजनाओं को कहां तक कार्यान्वित किया गया है और वे कहां-कहां है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) केन्द्रीय सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग के विभाग की योजनाओं को स्वीकार नहीं किया है। परन्तु खादी तथा ग्रामोद्योग की कार्यन्वयन एजेंसियों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन, उत्पादन तथा, अथवा बिक्री, अनुसंधान, प्रचार, मशीनों की खरीद तथा भवन निर्माण आदि के लिये ऋण अथवा अनुदान के रूप में योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता दी गई है। खादी की खुदरा बिक्री पर छूट (जिसके स्थान पर 6-4-1964 से सूती खादी पर मुफ्त बुनाई सहायता पर दी गई है) तथा खादी की बिक्री और उत्पादन पर तथा कुछ ग्रामोद्योगों को उनकी बिक्री तथा उत्पादन पर सहायता भी दी गई है। कुछ अच्छे औजारों के लिये भी सहायता दी गई है।

(ख) मध्य प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी। परन्तु 1964-65 में जिन संस्थायों को सहायता दी गई है उनको दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4217/65]**।

Old Age Pensions in U.P.

2376. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) the amounts allotted to the State of U.P. during the Third Five Year Plan for giving old age pensions ;

(b) whether the U.P. Government have asked for additional amounts under this head ; and

(c) if so, the amount asked for ?

The Deputy Minister in the Ministry of Social Security (Shri Jaganatha Rao) : (a) Nil.

(b) No.

(c) Does not arise.

Development of Fisheries

2377. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total amount granted to Uttar Pradesh for fisheries since 1961 ;

(b) whether the entire grant has been utilized ; and

(c) if so, the progress so far achieved in the development of fisheries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan) : (a) During the period from 1961 to 1963, the State Government was given Central assistance to the extent of Rs. 61·70 lakhs under 'Loan' and Rs. 63·75 lakhs under 'Grant' in connection with schemes relating to Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. Since 1963, an amount of Rs. 4·70 lakhs has been made available in the form of 'Grant' on account of fisheries only.

(b) The release of Central assistance is made after the expenditure has actually been incurred by the State Government.

(c) During the period 1961-65, water area under fish culture was extended from 0·52 lakh acres to 2·0 lakh acres. Seven major irrigation reservoirs with an operational area of 7,000 acres have been stocked with 56 lakh fingerlings while 12 medium water reservoirs have been stocked with 29 lakh fingerlings.

Reclamation of Waste Land

2378. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the total amount granted to Uttar Pradesh during the Third Plan period so far for the reclamation of waste land ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : Under the revised procedure for rendering financial assistance to State Governments, introduced from the year 1958-59. Central assistance admissible to various State Governments is sanctioned in bulk for schemes under the head "Agricultural Production". As such, it is not possible to indicate the amount of Central assistance given to the Government of Uttar Pradesh separately for the reclamation of waste land.

Welfare of S.C. and S.T. in U.P.

2379. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) the total amount given since 1961 by the Central Government to non-official organisations of Uttar Pradesh for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(b) the names of organisations referred to in part (a) above ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (a) and (b). During 1961-62 to 1964-65 an amount of Rs. 8,73,392 has been released as grants to (1) Iswar Saran Ashram, Allahabad, (2) Allahabad University, Allahabad, and (3) Kumar Ashram, Meerut.

2. Grants have also been paid to certain organisations of all India character like the Servants of India Society, Bhartiya Depressed Classes League, Harijan Sevak Sangh and the Indian Red Cross Society for welfare schemes either exclu. sively in Uttar Pradesh or in a number of States including Uttar Pradesh.

चूहों द्वारा फसल को हानि

2380. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चूहों द्वारा अनाज को पहुंचाई गई हानि का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका तथा जो सर्वेक्षण किया गया है उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चूहों के कारण होने वाली हानि से किसानों को संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्यतथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). भारत में चूहों द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि के बारे में कोई ठीक मूल्यांकन नहीं हुआ है । परन्तु अनुमान लगाया गया है कि कुल उपज के पांच प्रतिशत भाग को खेतों और गोदामों में चूहे हानि पहुंचाते हैं ।

(ग) चूहों द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि के बचाव के लिए कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) चूहों को मारने वाली औषधियों का सस्ते दामों पर वितरण करना;

(2) कृषकों के सहयोग से चहों के विरुद्ध अभियान जारी करना;

(3) चूहों पर काबू पाने के तरीकों के बारे में प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का आयोजन करना;

(4) चहों पर काबू पाने के विषय में जानकारी तथा साहित्य का वितरण करना; और

(5) भण्डारण के ऐसे उन्नत ढांचों के अपनाने के बारे में प्रचार करना जिन पर चहों का प्रभाव न पड़ सके ।

बायनाड बस्तीकरण योजना

2381. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वायनाड बस्तीकरण योजना के अन्तर्गत सड़क बनाने के प्रस्ताव में धन की कमी के कारण विलम्ब हुआ है;

(ख) इस कार्य की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) 1965–66 में इसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : वायनाड बस्तीकरण योजना एक राज्य परियोजना है । इसलिए मुख्यत: इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है । उन्होंने बताया है कि वायनाड बस्ती क्षेत्र में कोई नई सड़क बनाने का प्रस्ताव नहीं है । इसलिए संभवतया प्रश्न वायुवंचाल से चुन्डेल–मैसूर फ्रन्टियर रोड तक 57/2 मील की काली सतह वाली सड़क बनाने के बारे में है । अनुमानत: 2 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है । काम शुरू हो गया है और 31 मार्च, 1965 तक 61,418 रुपया व्यय हुआ है । 1965–66 वर्ष के आवंटन के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है ।

Adivasis of Bastar Area

2382. **Shri Lakhmu Bhawani :**
Shri Wadiwa :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether any scheme for providing improved agricultural facilities to the Adivasis of Bastar area is under consideration of Government ; and

(b) if so, the amount allocated for the purpose during the current year ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (a) and (b). The information has been called for from the State Government and the same will be laid on the table of the House, as soon as it becomes available.

Adivasis of Bastar Area

2383. **Shri Wadiwa :**
Shri Lakhmu Bhawani :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether any health schemes are being formulated by Government for the Adivasis of Bastar area ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether any hospital is proposed to be opened in the said area in near future ; and

(d) if so, its proposed location and the expenditure to be involved ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (a) to (d). The information has been called for from the State Government and the same will be laid on the Table of the House, as soon as it becomes available.

खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ

2384. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ तकनीकी तथा संगठनात्मक सहायता दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे यह सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को भी देंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) खाद्य एवं कृषि संगठन के विशेषज्ञों की एक तदर्थ टोली ने राज्य के नीचान वाले समस्यात्मक क्षेत्रों में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए दिसम्बर, 1964 में केरल का दौरा किया। केरल सरकार उसकी सिफारिशों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से तकनीकी तथा आर्थिक सहायता लेने के लिए एक योजना तैयार कर रही है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही खाद्य एवं कृषि संगठन से प्रार्थना करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

Translation of Laws

2385. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether translation of the laws in force during the British regime and prior to Independence, were published in various Indian languages ; and

(b) if so, the names of Indian languages in which translations of the Central Acts are available ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) and (b). Acts passed by Imperial Legislative Council were required to be translated in Bengali, Gujarati, Marathi, Telugu Kannada, Tamil and Malayalam through the local Governments concerned. Attempts were made some time ago to collect translations of Acts, so made and published but the State Governments were not able to do anything effective in the matter as copies of such translations were not generally available.

नालागढ़ समिति

2386. **श्रीमती सावित्री निगम:**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 8 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ज़िला प्रशासन तथा ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण व शिक्षा के बारे में नालागढ़ समिति की सिफारिशों को किन राज्यों में क्रियान्वित कर दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : आन्ध्र प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और गुजरात के सिवाय समस्त राज्यों द्वारा ज़िला स्तर प्रशासन के सम्बन्ध में नालागढ़ समिति की सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर की सरकारों ने इस सिफारिश को स्वीकार न करने के कोई कारण नहीं बताये हैं। गुजरात सरकार ने बताया है कि यह इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि ज़िलों की तरह बहुत से तालुका में भी अब उनके खण्ड हैं।

गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर और मैसूर के सिवाय समस्त राज्यों द्वारा ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा शिक्षा के सम्बन्ध में नालागढ़ समिति की सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया गया है। इस सिफारिश को स्वीकार न करने के लिए इन तीनों राज्यों ने कोई कारण नहीं बताये हैं।

उपरोक्त सिफारिश के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार के उत्तर का अभी तक इन्तज़ार किया जा रहा है।

New Bridge in Delhi

2387. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri H. C. Heda:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) the progress made in connection with the construction of a bridge over the Jamuna near Humayun Tomb, Delhi ; and

(b) when it is likely to be opened for traffic ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) The work of sinking 20 wells out of 28 wells is in hand. The sinking of some of these wells is nearing completion.

(b) The target date for the completion of the bridge is June 1966 and it is likely to be opened to traffic by that time.

राकेट यात्रा

2388. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका में संसार के बड़े नगरों के बीच राकेट द्वारा यात्रा करने की सम्भावना का अध्ययन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय यह बता सकता है कि क्या भारत में इस यान का कभी असैनिक परिवहन के लिए उपयोग किया जा सकेगा ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । फिर भी, इस समय सुपरसानिक विमान द्वारा यात्रा करने में कई समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं और उनका हल निकालना अभी बाकी है । राकेट-यात्रा के युग में प्रवेश करने के लिये हमें बहुत बहुत समय लगेगा ।

विस्तार कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण

2389. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन जिलों में सघन कृषि कार्यक्रम लागू किया जा रहा है क्या वहां विस्तार कार्यकर्ताओं तथा किसानों के लिये भारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कब आरम्भ होगा; और

(ग) इस कार्यक्रम पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). सघन कृषि क्षेत्रों में विस्तार कार्यकर्ताओं तथा किसानों के लिये विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है । इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कोई अतिरिक्त धन नहीं दिया गया । कार्यक्रम की रूपरेखा सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4218/65]**

Wells for drinking water

2390. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tewary :

Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have issued directions to the State Governments not to collect any contribution from people for the construction of wells for drinking water in the villages ; and

(b) if so, their reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) : (a) No such directions have been issued to the State Governments.

(b) Does not arise.

Places of Pilgrimage

2391. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme under which places of pilgrimage of all-India importance would be brought under the direct supervision of the Central Government ;

(b) whether Government also propose to make arrangements for propagating the eradication of provincialism at all the places of pilgrimage ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) There is no such scheme to bring the places of pilgrimage of all-India importance under the direct supervision of the Central Government.

(b) and (c) : The question does not arise.

कोयला खान भविष्य निधि

2392. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में समाप्त होने वाली अवधि के लिये कोयला खान भविष्य निधि में कितनी धनराशि जमा की गई;

(ख) निधि में कितने कर्मचारी पैसा जमा कराते हैं; और

(ग) यह धन किस प्रकार विनियोजित किया गया ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 45,70,49,406 रुपये (30 सितम्बर, 1964 तक)।

(ख) 4,18,791 (1963–64 तक जमा कराने वाले)।

(ग) निम्नलिखित ढांचे के अनुसार केन्द्रीय सरकारी सिक्योरिटी में धन लगाया गया है :–

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रमाणपत्र तथा प्रतिरक्षा निक्षेप प्रमाणपत्र	20 प्रतिशत
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बौंडों समेत अन्य भारत सरकार की प्रतिभूतियां	80 प्रतिशत

सहकारी आन्दोलन

2393. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने 1964–65 में उड़ीसा सरकार को सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने के लिए कोई ऋण या सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1965–66 में उस राज्य को कुल कितनी राशि देने का विचार है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4219/65]**।

(ग) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य बजट में शामिल किये गये उपबन्धों के ब्यौरे प्राप्त होने पर यह राशि निश्चित की जायेगी।

New Variety of Rice

2394. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Rice Research Institute, Cuttack (Orissa) has invented a variety of rice which is very useful for Diabetic patients ; and

(b) whether any experiments on its use have been conducted and if so, the results achieved thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). In some of the rice strains, developed by the Central Rice Research Institute, Cuttack, the grains were found to have a higher protein content of 11 to 13 per cent as against an average of 7 per cent in ordinary rice varieties. Since rice protein is more easily assimible than wheat protein, the new vareity of rice is likely to be more acceptable for the diabetic patients. The new strains of rice are still in the experimental stage and have not been released for general cultivation.

दस्तकारी उद्योग उड़ीसा

2395. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उड़ीसा राज्य में दस्तकारी उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा कितनी राशि दी गई; और

(ख) 1965–66 में इसी प्रयोजन के लिए उस राज्य को कितनी राशि देने का विचार है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 5.30 लाख रुपये।

(ख) 1965–66 में दस्तकारी उद्योग के विकास के लिए उड़ीसा सरकार को दी जाने वाली केन्द्रीय सरकार की धनराशि वर्ष के अन्त तक निकाल ली जायेगी। परन्तु राज्य सरकार का अंश समेत 4.56 लाख रुपया आवंटित किया गया है। इसमें से केन्द्रीय सरकार का अंश 3.50 लाख रुपया है।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए बस्तियां

2396. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए बस्तियां बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां । केवल अनुसूचित आदिम जातियों के लिए ।

(ख) 1964–65 में 200 मकानों के निर्माण के लिए प्रबन्ध किया गया है ।

(ग) 2.50 लाख रुपये ।

अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

2397. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उड़ीसा में कितने अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए गये ;

(ख) इनमें कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया ; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) 80 (फरवरी 1965 तक) ।

(ख) दाखिल—1247, प्रशिक्षित—913 (अप्रैल, 1964 से फरवरी, 1965 तक) ।

(ग) 55,851 रुपये (अप्रैल 1964 से फरवरी 1965 तक) ।

सोवियत संघ से भेड़ें

2398. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माउंट आबू (राजस्थान) में कुछ रूसी मैरिनों भेड़ें पहुंच गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी भेड़ें प्राप्त हुई हैं और उन पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 27,000 रुपये के व्यय से राजस्थान सरकार के लिए 25 भेड़ें प्राप्त की गईं ।

भारतीय जहाज "विश्व ज्योति"

2399. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 मार्च, 1965 को 9173 टन के विश्व ज्योति नामक भारतीय मौटर जहाज की ब्रिटेन के टेंकर एसोवार्ड् सवर्थ के साथ दक्षिण पूर्व इंगलैंड में ग्रेवसैंड के पास टेमसू नदी में टक्कर हुई थी और उसको बहुत क्षति पहुंची ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का विवरण क्या है और कितनी हानि हुई ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी हां ।

भारतीय पोत "विश्व ज्योति" 10 मार्च, 1965 को थेम्स नदी में ग्रेवसैंड से लन्दन की ओर वहाव से ऊपर जा रहा था । पोत नदी पाइलट के नियंत्रण में था । उस समय कोहरे के कारण कम दिखाई पड़ रहा था किन्तु नदी नौचालन योग्य थी । उसने एक छोटा पोत नदी में नीचे की ओर आते हुये देखा । इस छोटे पोत को बचाने के प्रयास में, वह नदी में दक्षिण की ओर बहुत दूर चला गया और "एसोवोर्ड् सवर्थ" के पार्श्व से टकरा गया, जो लिटिलबुक पावर स्टेशन पर ठहरा हुआ था और एसौ-वोर्ड् सवर्थ के नदी की ओर के बाजू पर लंगर डाले हुये कर्ष पोत" सन 17 के बाजू से भी टकरा गया किन्तु इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई और न जहाज के अनल्प क्षति हुई । पोत यू० के० से अनुसूची के अनुसार और पूर्वी यात्रा योग्य दशा में चल चुका है और वह बम्बई में इस महीने के लगभग अन्त तक पहुंच जायेगा ।

भेड़ विकास फार्म

2400. **श्री वें० वेंकटासुब्बया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों में भेड़ विकास फार्म खोलने की योजना बनाने का है जो शुष्क अथवा अर्ध शुष्क हैं और खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या ऐसे कुछ क्षेत्र चुन लिए गए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) ऐसे कुछ क्षेत्रों में पहले ही कुछ भेड़ विकास केन्द्र मौजूद हैं । अभी तक नए फार्म स्थापित करने की कोई योजना तैयार नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

Muslim League in Kerala

2401. **Shri R. S. Tiwary**: Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Muslim League has not received 4 per cent

of the total votes polled in the elections for the Kerala Legislative Assembly held recently ; and

(b) if so, whether the Muslim League will be given recognition as a political party in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) Yes Sir.

(b) The Election Commission has not yet taken up the question whether the Muslim League should or should not continue to be 'recognised' for the purpose of alloting a reserved symbol to its candidates in future. It intends doing so after the statistics have been collected, checked and analysed in regard to all parties which contested the elections.

कार्ड धारियों को दुग्ध सम्भरण

2402. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :
श्री लखमू भवानी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली गर्मियों में दिल्ली दुग्ध योजना ने कार्ड धारियों के दूध की मात्रा में जो कटौती की थी वह अभी तक पूरी नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) दिल्ली के नागरिकों को दिये जाने वाले दूध के सम्भरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) कटौती कब तक पूरी की जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) इतना दूध प्राप्त करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है कि कटौती को पूरा किया जा सके ।

(ग) दूध की प्राप्ति के लिए पंजाब और उत्तर प्रदेश में नये क्षेत्र स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(घ) 1965 की सर्दी के मौसम तक कटौती को पूरा करना सम्भव नहीं है ।

सहकारी समितियां

2403. **श्री मलाइच्छामी :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 16 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 453 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-बस्तियां बसाने के लिए सहकारी समितियां बनाना, जिन के सदस्य भूमिहीन मजदूर हों, एक नीति-निर्णय है और राज्यों को इस बारे में बता दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने खेती बाड़ी करने तथा बसाने के लिए सहकारी समितियां बनाई हैं ; और

(ग) इन समितियों द्वारा कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में नई बस्तियां बसाने वाली सहकारी समितियां गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों में भूमिहीन मजदूरों को सामूहिक खेती समितियों को सरकारी बेकार भूमि दी गई है ।

(ग) उपलब्ध जानकारी 8 राज्योंतथा 2 संघ क्षेत्रों की सदस्यता के बारे में है। 30-6-1964 को नई बस्तियां बसाने वाली सहकारी समितियों तथा सामूहिक खेती समितियों के 44,886 सदस्य थे ।

अनाज का संभरण

2404. **श्री कपूर सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों अथवा आटा मिलों को सीधे बन्दरगाहों से अनाज का स्टाक देने की नई नीति बनाई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस नीति के अनुसरण में सभी गोदामों को उनके मालिकों को वापस दे दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या संस्थानों को अन्य डिपुओं में मिला दिया गया है ;

(घ) इस पर कितना व्यय होगा ; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा उत्तर भारत के लिये 1956 में लागू की गई प्रादेशिक योजना को जारी रखने के औचित्य की जांच करने का भी सरकार का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) कोई नई नीति नहीं बनायी गयी है। जैसे ही आवश्यक या वांछनीय समझा जाता है, वैसे ही खाद्यान्न गोदी या डिपों से सीधे जारी किये जाते हैं ।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) क्षेत्रीय योजना न केवल उत्तरी भारत में बल्कि सारे देश में लागू की गयी थी। यह योजना सन्तोषजनक कार्य कर रही है ।

केन्द्रीय संग्रह डिपो

2405. **श्री कपूर सिंह**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964–65 में देश में विभिन्न केन्द्रीय संग्रह डिपुओं में उप-क्षेत्रीय योजना चालू की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो योजना चालू करने का क्या उद्देश्य था ;

(ग) क्या हापुड़, जयपुर और दिल्ली उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के उप-क्षेत्र हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन की स्थापना और उन्हें जारी रखने पर कितना खर्च होगा ; और

(ङ) 1964–65 में प्रत्येक उप-क्षेत्र में पृथक पृथक कितने स्टाक का लेन देन हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) यह अनुभव किया गया कि चारों प्रादेशिक कार्यालयों में काम और स्टाफ का बहुत अधिक केन्द्रीयकरण था और क्षेत्र सम्बन्धी कार्य को पर्याप्त देख-भाल नहीं की जा रही थी । प्रभावी नियंत्रण रखने और अधिक दक्षता लाने के लिये यह निर्णय किया गया कि प्रादेशिक कार्यालयों की गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण और क्षेत्रों को उपक्षेत्रों और जोनों में प्रबन्ध किए जाने योग्य यूनिटों में विभाजित किया जाए ।

(ग) जी हां ।

(घ) हापुड़, जयपुर और दिल्ली के उपक्षेत्रीय कार्यालयों में 1–8–64 से 31–3–65 तक की अवधि में संस्थापन और आकस्मिकता पर हुआ वास्तविक खर्च क्रमशः रु० 31,122.15, रु० 55,580.32 और रु० 47,608.31 था ।

(ङ) 1964-65 में तीनों क्षेत्रों के अधीन डिपों में क्रमशः कुल 1,24,873, 3,66,914 और 2,78,706 मीट्रिक टन स्टाक का लेन-देन हुआ ।

Women's Cooperative Societies

2406. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Social Welfare Board has decided to give a special grant to women's cooperative societies;

(b) if so, the amount allocated for this purpose and the detials thereof; and

(c) the additional arrangements made by the Board for providing assistance in order that such cooperative societies may function properly ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Shri Jaganatha Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The usual terms and conditions governing the sanction of grants are applicable both to co-operative societies as well as to other registered voluntary institutions/organisations.

विदेशी पर्यटन यातायात

2407. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दो वैज्ञानिक अनुसंधान दलों—एक अमरीकी तथा एक आस्ट्रेलियाई—द्वारा भारत में विदेशी पर्यटन यातायात के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने विदेशी पर्यटक यातायात में शिथिलता के मुख्य कारण क्या बताये हैं ; और

(ग) उन के विचारों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां। इन दो सर्वेक्षणों में से केवल एक सर्वेक्षण जो यू. एस. ए. में स्टेंडफोर्ड अनुसंधान संस्थान, कैलिफोर्निया द्वारा, भारत में आने वाले यू० एस० पर्यटकों के अध्ययन के लिये किया गया था, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था।

(ख) इस अनुसंधान दल ने पर्यटक यातायात की तेज वृद्धि को रोकने वाली निम्नलिखित मुख्य बातें बतायी हैं :—

स्टेडफोर्ड अनुसंधान संस्थान (यू० एस० ए०)

1. निर्धनता तथा सामान्य अस्वास्थ्यकर दशाओं का प्रभाव ।
2. जलवायु और स्वास्थ्य सम्बन्धी दशाओं के बारे में पूर्वप्रत्ययन ।
3. भारत में आवास और हवाई यात्राओं के लिए आरक्षण प्राप्त करने की कठिनाइयां।
4. प्रचार और उत्थान कार्यक्रम की कमी का ख्याल ।

ब्रैकन अनुसंधान कम्पनी (आस्ट्रेलिया)

1. आस्ट्रेलिया में समाचारों और फिल्मों में मुख्यतः (भारत में होने वाली अनेक अच्छी बातों के बजाय) झगड़े, विपत्तियां आदि ही देखने में आती हैं ।
2. भारत को गरीबी से पैदा होने वाली परिस्थितियां, जैसे स्वास्थ्यकर स्थिति का अभाव, भ्रष्टाचार, इत्यादि ।
3. भारत में यात्रा सम्बन्धी कठिनाइयां जिस में अपर्याप्त परिवहन, कहां जाये और कैसे जाये के सम्बन्ध में जानकारी का प्राप्त न होना और अफसरशाही ।
4. रास्ते में फंस जाने का भय ।
5. जलवायु में लगातार या विकल्पित तौर से अति विषमता ।
6. मनोरंजन की कमी और यह ख्याल कि भारत में पर्यटकों की आवश्यकता के लिए कोई एजेन्सी जिम्मेदार नहीं है ।

(ग) सरकार ने इन सब बातों को नोट कर लिया है और उन्हें दूर करने तथा न्यूनतम करने के लिए कदम उठा रही है, किन्तु यह मालूम होना चाहिए कि यह दीर्घकालीन प्रक्रिया है, विदेशों में पब्लिक को जानकारी देना और यहां सुविधाओं की व्यवस्था करना। इस के लिए निरंतर और दीर्घकालिक प्रयत्न की आवश्यकता है ।

सहकारी फल परिरक्षण तथा डिब्बाबंदी एकक

2408. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर बिहार में तीन सहकारी फल परिरक्षण तथा डिब्बाबन्दी एकक स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जायगी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मीन क्षेत्र सम्बन्धी निगम

2409. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने प्रस्तावित मीन क्षेत्र सम्बन्धी निगम में शेयर लेने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) इस प्रश्न पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ पालन

2410. **श्री लखमू भवानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पहाड़ियों में भेड़ पालन सम्बन्धी किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) उन योजनाओं के अतिरिक्त जो पहले ही चालू हैं, कोई और योजना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

2411. **श्री लखमू भवानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था को अप्रैल, 1965 से एक स्वासी संस्था बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में यदि कोई व्यय अंतर्ग्रस्त है तो कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). देश में कृषि अनुसंधान के पुनर्गठन के प्रश्न पर, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को एक स्वशासी संस्था बनाना भी शामिल है, अनुसंधान पुनरीक्षण दल की सिफारिशों के आधार पर विचार किया गया है । ख्याल है कि पुनर्गठित ढांचे के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान में नेतृत्व तथा स्वतंत्र विचार-विमर्श की अधिक गुंजाइश होगी । इस समय पुनर्गठन के बारे में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

मद्रास में फल तथा अनुसन्धान केन्द्र

2412. श्री सेझियान :
श्री शिवशंकरन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने राज्य में एक प्रयोगात्मक फल तथा अनसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने योजना के लिए सहायता देने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). मद्रास राज्य के सेलम तथा उत्तरी अरकाट जिलों में फल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की एक योजना मद्रास सरकार से प्राप्त हुई है। यह योजना 5 वर्ष के लिए होगी और इस पर 2,62,576.00 रुपये खर्च होंगे। यह योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विचाराधीन है।

अन्तर्राज्यीय जल परिवहन निगम

2413. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल परिवहन निगम की स्थापना के लिए एक योजना सरकार की मंजूरी के लिए भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उस पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). वाणिज्य नदी-सेवाओं को चलाने के लिए बिहार सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

पशुओं के सघन विकास खण्ड

2414. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली दुग्ध योजना की अधिक मात्रा में दूध उपलब्ध करने के उद्देश्य से मेरठ तथा बुलन्दशहर के जिलों में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध शेड क्षेत्रों के चालों और पशुओं के सघन विकास खण्ड स्थापित करने के लिए एक योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कार्यरूप देने में कितना व्यय होगा ; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) भारत सरकार ने हाल ही में जो विशेष विकास कार्यक्रम तैयार किया है। उसके अन्तर्गत (1–2) उत्तर प्रदेश में कानपुर तथा लखनऊ के दूध शेडों में तथा (3) दिल्ली दुग्ध योजना के शेडों में उत्तर प्रदेश के मेरठ / बुलन्दशहर के ज़िलों में 3 सघन पशु विकास खण्डों की स्थापना के बारे में एक योजना स्वीकार की गई है।

(ख) 1964-65 तथा 1965-66 में मेरठ-बुलन्दशहर खण्ड का अनुमानित खर्च 15.26 लाख होगा। परन्तु राज्य सरकार के सुझावों के परिणामस्वरूप इसमें काफी कमी हो सकती है।

(ग) योजना का उद्देश्य चारा विकास तथा ग्रामीण विकास विस्तार कृत्यों से लाभ उठाकर नियन्त्रित प्रजनन, उचित पोषण, प्रभावशाली ढंग से रोग नियंत्रण तथा उचित प्रबन्ध तथा विपणन विधियों के माध्यम से पशुओं का विकास करना तथा दूध की मात्रा को बढ़ाना है। अनुमान है कि प्रत्येक खण्ड के अन्तर्गत लगभग एक लाख प्रजनन योग्य गाय / भैंसें होंगी। सकेन्द्रित वीर्य संचयन केन्द्रों तथा प्रादेशिक कृत्रिम वीर्य संचयन केन्द्रों तथा स्टाकमैन केन्द्रों के माध्यम से प्रजनन को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है।

Agricultural Farms

2415. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya
Shri Y.S. Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the period of agreement regarding agricultural farms concluded between India and Japan has been extended :

(b) if so, period for which it has been extended ; and

(c) the progress made during the period in respect of which the agreement was originally entered into ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). The Agreement with the Government of Japan for the establishment of four Japanese Demonstration Farms, at Ranaghat in West Bengal, Chakuli in Orissa, Arrah in Bihart and Surat in Gujarat, which was for a period of three years upto April, 1965, has been extended for a period of two years upto April, 1967.

Besides, a separate agreement for establishement of four more Japanese Demonstration Farms, at Bapatla in Andhra Pradesh, Changamanad in Kerala, Khopoli in Maharashtra and Mandya in Mysore was signed on the 17th Decemeber, 1964. The period of this agreement extends over four years upto 16th December, 1968.

(c) A statement is laid on the Table of the House, **[Placed in library. See. No. L.T—4220/65]**.

Sugar Mills

2416. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Y.D. Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up five sugar mills.

(b) if so, whether any sugar mill is proposed to be set up in Rajasthan ;

(c) whether it is also a fact that sugarcane in Kota-Bundi areas is rotting in the fields in the absence of any mill there ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food & Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) a About ten new sugar factories are proposed to be licensed during 1965 in different States. Their locations are under consideration.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

केरल विधान सभा के लिए चुनाव

2417. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में केरल विधान सभा के लिये चुनाव कराने पर केरल सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया ;

(ख) अधिकारियों को यात्रा भत्ते तथा दैनिक-भत्ते के रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) परिवहन पर कितना व्यय हुआ ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) केरल विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के संचालन में केरल सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय (31–3–65 तक यथा-अंकित) 11,63,900.00 रुपये है। निर्वाचक नामावलियों की तैयारी पर किया गया व्यय इसमें सम्मिलित नहीं है ।

(ख) आफिसरों को 31 मार्च, 1965 तक यात्रा-भत्ते और दैनिक-भत्ते के रूप में 5,93,00·00 रुपये की धनराशि दी गई है ।

(ग) 31 मार्च, 1965 तक परिवहन पर व्यय की गई रकम 2,15,000.00 रुपये है ।

Hindi version of the Constitution

2418. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the date of publication of the latest Hindi version of the Constitution of India ; and

(b) if any latest edition of the same has not been published after the first one, whether Government propose to publish the latest Hindi version of the constitution of India incorporating all the amendments made therein up-to-date, if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) and (b). The Hindi version of the Constitution was first published in 1950. A diglot edition of the Constitution as modified upto December, 1957 was published in 1959 incorporating therein the first seven amendments of the Constitution. There is a large stock of this diglot edition with the Manager of Publications and, therefore, the question of printing a fresh edition did not arise. Two supplementary volumes containing all the other amendments to the Constitution have, however, been published.

कलकत्ता-गोहाटी मालवाहक सेवा

2419. **श्री प्र. चं. बरुआ :** क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1965 से कलकत्ता से त्रिपुरा, सिलचर, इम्फाल और गोहाटी तक इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन मालवाहक सेवा बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रभावित क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या वैकल्पिक प्रयन्ध किया गया है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क)से (ग). 1-4-1965 से उड़ान के समय/काम के समय की पाबन्दियों के लागू करने के कारण, इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन भारवाही सेवा चलाने के लिये पर्याप्त संख्या में कारुक (क्रू) का निर्धारण करने में बहुत कठिनाई अनुभव कर रहा है। त्रिपुरा, सिलचर, अगरतला, इम्फाल और गोहाटी की भारवाही सेवा बन्द नहीं की गई है, किन्तु चालन सम्बन्धी कारणों से, यातायात सम्बन्धी कुल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, कारपोरेशन पर्याप्त संख्या में सेवाएं नहीं चला सकी है । फिर भी, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी उपाय किये जा रहे हैं ।

Seed Multiplication Farms

2420. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the existing, State-wise, number of Seed Multiplication Farms at block level ;

(b) the State-wise, expenditure incurred thereon during the last two financial years ; and

(c) the production of various types of seeds in those farms during the same period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c). The required information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received from them.

संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं का आयात

2421. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के सचिव ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका का इसलिये दौरा किया था कि वह पी० एल० 480 के अधीन भारत को गेहूं भेजने के सम्बन्ध में अमरीकी प्राधिकारियों से बातचीत कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो खाद्य सचिव ने जो वहां सलाह-मश्विरा किया था उसका क्या नतीजा निकला ; और

(ग) पी० एल० 480 कार्यक्रम के अधीन 1964 में अमरीका से कुल कितने गेहूं का आयात किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). सचिव, खाद्य विभाग हाल ही में अमरीका गये थे। उनके वहां जाने का उद्देश्य यह था कि अमरीकी अधिकारियों, जहाज मालिकों के प्रतिनिधियों और भारतीय सप्लाईमिशन वाशिंगटन से परामर्श कर पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमेरिका से खाद्यान्न लाने वाले कुछ जहाजों को स्थगित करने अथवा उनके गमन की तारीखों में अधिक अन्तर डालने की चेष्टा की जाये, क्योंकि अमरीकी बन्दरगाहों के जहाज पर माल चढ़ाने और उतारने वाले मजदूरों की हड़ताल की समाप्ति के उपरान्त बहुत अधिक जहाजों के इकट्ठे चलने से भारतीय बन्दरगाहों पर, विशेषतः बम्बई व काण्डला, अत्यधिक भीड़भाड़ होने की बहुत अधिक आशंका थी। उनके अमेरिका जाने के फलस्वरूप, 3 गेहूं के टैंकर मई में रवाना होंगे और एक टैंकर को बम्बई से मद्रास की ओर मोड़ दिया गया। इन सभी उपायों से बम्बई और काण्डला के बन्दरगाहों को बहुत राहत मिलेगी ।

(ग) लगभग 52.5 लाख मीट्रिक टन ।

केरल सड़क परिवहन निगम

2422. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव स्थापित केरल सड़क परिवहन निगम ने राज्य परिवहन विभाग की सभी आस्तियां और दायित्व ले लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निगम इससे पहले के राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वर्तमान सभी अधिकारी तथा विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिये वचनबद्ध है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी हां।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

2423. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कोयला खान भविष्य निधि के प्रादेशिक कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण करने के हेतु कोयला खान भविष्य निधि संगठन को रामावरम् में 5 एकड़ भूमि इस बीच पट्टे पर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्वार्टरों का निर्माण कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथराव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Warehousing Corporation

2424. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the question of utilisation of the facilities provided by the Central Warehousing Corporation and State Warehousing Corporation has been studied ;

(b) if so, when, by whom, as also the results thereof ; and

(c) whether the question of conducting a detailed study of the same has been considered in case the said study is inadequate ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan) : (a) No. There has been no study made by an external agency so far.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

आसाम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

2425. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 और 1964-65 में आसाम सरकार को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी योजना की क्रियान्विति के लिये कितना धन मंजूर किया गया ; और

(ख) क्या उक्त वर्षों के लिये दी गई राशि का उचित उपयोग किया गया ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

1963-64	. . .	288.28 लाख रुपये
1964-65	. . .	352.72 लाख रुपये ।

(ख) जी हां ।

राष्ट्रीय समुद्रीय प्रौद्योगिकी संस्था

2426. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन सम्बन्धी विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय समुद्रीय प्रौद्योगिकी संस्था स्थापित करने की व्यवहारिकता पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). 4 अप्रैल, 1965 को दिल्ली में द्वितीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस का उद्घाटन करते हुये प्रधान मंत्री ने यह इच्छा प्रकट की कि नौपरिवहन से सम्बन्धित सभी विषयों का समन्वय करने के लिए समुद्री टेक्नोलोजी के एक राष्ट्रीय संस्थान के स्थापित करने की शक्यता के प्रश्न की जांच की जानी चाहिए। इस प्रश्न पर राष्ट्रीय नौपरिवहन बोर्ड मई, 1965 में होने वाली अपनी बैठक में विचार करेगा। इस सम्बन्ध में उसकी सिफारिशों के प्राप्त होने पर इस विषय पर सरकार द्वारा आगे विचार किया जायेगा।

S. C. & S.T. Employees of Food and Agriculture Ministry

2427. Shri Veerappa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Class I and Class II employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes working at present in his Ministry ; and

(b) whether this number is more or less than the posts reserved for in these two classes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b). A statement is laid on the table of the House. [*Placed in Library. See No. L.T. 4221/65*].

कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

2428. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग सम्बन्धी गोष्ठी में यह सिफारिश की गई थी कि ऋण न देने वाले छोटे राष्ट्रों का संघ प्रशिक्षकों तथा प्रोत्साहकों के रूप में योग्य प्रबन्धकों की व्यवस्था करके कृषि कार्यक्रमों में तकनीकी सहायता दें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)जी हां।

(ख) इस सुझाव पर विचार हो रहा है।

तुना मछली का पकड़ाना

2429. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजना से सम्बद्ध एक जापानी विशेषज्ञ ने हमारे तट के पास के समुद्र में तुना मछली पकड़ने की संभावनाओं के बारे में एक प्रतिवेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें तथा प्रस्ताव क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) नहीं। कोचीन में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की प्रायोजना से सम्बद्ध जापानी विशेषज्ञ ने हमारे तट के पास के समुद्र में तुना मछली पकड़ने की सम्भावनाओं के बारे में अभी तक कोई अन्तिम प्रतिवेदन नहीं दिया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूध के कार्डों की पुनः अवधि बढ़ाना

2430. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिये गये दूध के बहुत से कार्डों की अवधि नहीं बढ़ाई गई है क्योंकि योजना के पास उनका रिकार्ड नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के कार्डों का नवीनीकरण न किये जाने के कारण कार्ड होल्डरों को बड़ी कठिनाई हो रही है ; और

(ग) जिन कार्ड होल्डरों के कार्डों का नवीनीकरण नहीं किया गया है उनको दूध देने के लिये क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). सितम्बर-अक्टूबर, 1964 में ग्राहकों तथा उनके कोटे के बारे में जो सूची प्रयुक्त हो रही थी उसके आधार पर समस्त दुग्ध कार्डों का नवीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उन कार्डों का भी नवीकरण किया जा रहा है जो कि उसके पश्चात् दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार जारी किए गए थे। परन्तु बहुत से मामलों में ग्राहकों ने स्वयं ही अनधिकृत रूप से अपने कार्डों में दूध की मात्रा को बढ़ा लिया। कुछ अनधिकृत कार्डों का भी पता चला है। यही कारण है कि यद्यपि दिल्ली दुग्ध योजना डिपुओं को कोटा सप्लाई करती रही है फिर भी वास्तविक ग्राहकों को अपने कोटे का दूध प्राप्त करने में कठिनाइयां अनुभव हुई। उन समस्त कार्डों को जो अनधिकृत रूप से जारी हुए हैं तथा उन कार्डों को जिनमें दूग्ध की मात्रा अनधिकृत रूप से बढ़ाई हुई है, अलग करने के बारे में कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना को आशा है कि वह समस्त अधिकृत कार्डों के दूध की मांग को पूरा कर सकेगी परन्तु योजना जाली या अनधिकृत कार्डों पर दूध सप्लाई करने में असमर्थ है।

स्टेनलैस स्टील मिल्क बार

2431. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया ने एक 20 फुट लम्बी स्टेनलैस स्टील मिल्क बार भारत को भेंट की है ; और

(ख) यदि हां, तो यहां उसका किस प्रकार प्रयोग किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

दमदम हवाई अड्डा

2432. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दमदम हवाई अड्डे पर नवनिर्मित यात्री कक्ष की खिड़कियां हाल में कैरावेल विमान से हुए जेट विस्फोट से नष्ट हो गईं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी असाधारण घटना के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). यह सच है कि कैरावैल विमान की सफाई करते समय अधिक बिजली इस्तेमाल करने के कारण दमदम हवाई अड्डे पर नवनिर्मित यात्रीकक्ष के दो दरवाजों की खिड़कियों के शीशे टूट गये थे। दुर्घटना की जांच की जा चुकी है। गत वर्ष भी हवाई अड्डे के दूसरे भाग में इसी प्रकार का विस्फोट हुआ था। इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को बताया गया है कि वह अपने विमान चालकों से कहे कि ऐसी घटनायें न होने दें।

समुद्री इंजीनियरी पाठ्यक्रम

2433. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड ने सिफारिश की है कि वाणिज्यिक बेड़े के कर्मचारियों को समुद्रीय इंजीनियरी पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्रशिक्षण की सुविधायें देने के लिये नौसेना प्राधिकारियों से सहयोग मांगा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उसका क्या परिणाम रहा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) आगे कार्यवाही करने के लिये जहाजरानी महानिदेशालय के तकनीकी अधिकारी नौसेना संस्थापनों में उपलब्ध सुविधाओं का अब अध्ययन कर र हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

प्रधान मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा का मुल्तवी किया जाना

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं **वैदेशिक कार्य** मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाती हूं और निवदन करती हूं कि वह इस सम्बन्ध मे एक वक्तव्य दें :—

प्रधान मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा का मुल्तवी किया जाना"

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत में संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूत ने कई मौकों पर प्रधान मंत्री से कहा था कि अमरीका के राष्ट्रपति भारत के प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के लिए बड़े उत्सुक हैं और यह पूछा कि इस यात्रा का सुविधापूर्वक समय कब हो सकेगा। प्रधान मंत्री ने संकेत दिया कि उन्हें अमरीका की यात्रा से प्रसन्नता होगी लेकिन वह संसद् का बजट सत्र समाप्त होने तक भारत छोड़ कर जाने में समर्थ न होंगे।

[श्री स्वर्ण सिंह]

18 जनवरी, 1965 को राजदूत चेस्टर बाउल्स ने राष्ट्रपति के निदशानुसार प्रधान मंत्री को पत्र लिखा जिसमें 15 मई के आसपास यात्रा करने का सुझाव था। कोई निश्चित तारीख बताने से पहले, प्रधान मंत्री को अपने अन्य कार्यक्रमों का भी ख्याल रखना था, जो ये हैं : सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की यात्रा, जहां से पहले निमंत्रण प्राप्त हुआ था ; अल्जीयर्स की अफ्रो-एशियाई काफ्रेन्स और लन्दन में राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों की मीटिंग। इन यात्राओं की तारीखों को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री ने बताया कि यात्रा की तारीखें मई के आखीर में और जून के शुरू में किन्हीं दिनों में हो सकेंगी। 23 मार्च को राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री को निमंत्रण-पत्र लिख कर भेजा कि वह 2 और 3 जून को वाशिंगटन पधारें। प्रधान मंत्री ने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस पत्र का उत्तर दिया। उसके बाद, प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के बारे में राजनैयिक सूत्रों के ज़रिये बातचीत हुई।

शुक्रवार, 16 अप्रैल को, अमरीका के राजदूत ने प्रधान मंत्री के सचिव को एक संदेश दिया, जो राष्ट्रपति के पास से केबिल के ज़रिये प्राप्त हुआ था, और जिसमें राष्ट्रपति ने यह कारण बता कर प्रधान मंत्री की यात्रा को शुरू सर्दियों तक स्थगित करने का सुझाव दिया था कि अगले दो महीनों में वे वियतनाम की स्थिति और अमरीकी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठकों में व्यस्त रहेंगे। प्रधान मंत्री ने संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा रद्द कर दी है।

वाशिंगटन-स्थित हमारे राजदूत ने अमरीका के विदेश मंत्री को पहले ही यह बता दिया है कि जिस असाधारण तरीके से यह क़दम उठाया गया है उससे भारत में ग़लतफहमी पैदा हो सकती है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जबकि अन्य देशों के प्रमुखों को अमरीका द्वारा निमंत्रित किया गया है, क्या अमरीका के राष्ट्रपति ने भारत का अपमान इसलिए किया है कि भारत ने वियतनाम में अमरीका द्वारा बमबारी किये जाने की निन्दा की है तथा पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अमरीकी हथियारों के प्रयोग के बारे में अमरीका से विरोध प्रकट किया है ? क्या सरकार किसी भी परिस्थिति में बिना झुके वियतनाम में अमरीका द्वारा बमों का प्रयोग बन्द करने तथा आक्रामक कार्यवाहियों को शीघ्र रोकने के लिए संघर्ष करती रहेगी तथा क्या इस अपमान का उचित उत्तर दिया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : वियतनाम के बारे में हमारा दृष्टिकोण सदा यही रहा है और अमरीका को इस सम्बन्ध में पहले से ही पता है। हमारा इस सम्बन्ध में यही दृष्टिकोण रहेगा कि वियतनाम की समस्या सैनिक शक्ति से हल नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि अमरीका ने वियतनाम के मामले के कारण नहीं अपितु उन्होंने पत्र में जो कारण बताये हैं उनके कारण यात्रा स्थगित करने को कहा है।

Shri Naval Prabhakar (Delhi—Karol Bagh) : May I know whether it is a fact that America has equated India with Pakistan due to our stand on Viet Nam ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति की अमरीका यात्रा रद्द की गई है। किन्तु मैं नहीं समझता कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तोला गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण-पश्चिम) : क्या यह सच है कि अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधान मंत्री को, यात्रा स्थगित करने के सम्बन्ध में भेजे गये पत्र में इस बात का संकेत था कि प्रधान मंत्री कनाडा की अपनी प्रस्तावित यात्रा न करें क्योंकि यह अमरीका के लिए अपमान-जनक होगा और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या दृष्टिकोण अपना रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसा कोई सुझाव नहीं था ।

श्री वाजी (इन्दौर) : क्या उत्पन्न हुई असाधारण स्थिति को देखते हुए प्रधान मंत्री का विचार श्री ऊ थान्ट से मुलाकात के कार्यक्रम को, जिसके लिए उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, रद्द करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मेरा विचार न्यूयार्क जाने का नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : May I know whether the postponement of the Prime Minister's visit to U.S. will affect the programme of Prime Minister's visits to other countries ?

Shri Lal Bahadur Shastri : I will go to Canada which has already been stated. There might be a change in the dates of visit.

श्री पें. वेंकटासुब्बया (अडोनी) : जिस प्रकार अमरीका ने प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा स्थगित की है उसकी दृष्टि से क्या सरकार का विचार अमरीकनों का यह भ्रम दूर करने का है कि हम उन के आश्रित हैं और वे इसी कारण हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जोकि हमारे प्रति रूस के व्यवहार से विपरीत है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : The humiliating attitude shown by U.S.A. is due to the fact that U.S.A. is proud of her position as we are dependents on them in the matters of wheat and dollars. Keeping in view this fact may I know whether the Prime Minister proposes to speak something against China and its allies in the affairs of South Asia, or he will keep silent.

Mr. Speaker : I think this question needs a silent reply .

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): while this Government does not recognise East Germany out of the fear of West Germany, do not establish diplomatic relation with Israel with a view to keep the Arab Nations pleased and do not recognise Farmosa due to the fear of Peaking, what are the reasons that we are speaking against America in an irresponsible manner in matters of Viet Nam instead of condemning China ?

Mr. Speaker : It is only an argument and not a question.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : The U.S.A. has withdrawn the invitation extended to the President of Pakistan and the Prime Minister of India. Pakistan's friendship with China and India's Policy towards South Viet-Nam are mainly responsible for this. May I know whether the Prime Minister proposes to revise our Foreign Policy in the light of the above facts ?

Shri Lal Bahadur Shastri : No Sir, our policy is not to be affected by such incidents because it has been adopted after a good deal of thought and consideration.

Shri Vishram Prasad (Lalganj) : It is really humiliating that the invitation has been withdrawn specially when the Prime Ministers of other countries are visiting that Country. May I know whether it will affect our relation with U.S.A. and whether it will also have any effect on the assistance being given etc. by U.S.A. ?

Mr. Speaker : It is not a relevant question.

श्री वारियर (त्रिचूर) : चूंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा भी स्थगित की गई है अतः क्या इसका काश्मीर की समस्या, हमारे इस दावे पर, कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अमरीका के दृष्टिकोण और पाकिस्तान द्वारा खड़े किये गये विवाद से कोई सम्बन्ध है?

अध्यक्ष महोदय : यह अमरीका को बताया जाना चाहिए न कि भारत के प्रधान मंत्री को ।

श्री वासुदेवन नायर : (अम्बलपुजा) : विवरण में कहा गया है कि अमरीकी राष्ट्रपति ने पतझड़ तक यात्रा स्थगित करने के लिये कहा है । क्या प्रधान मंत्री अमरीकी राष्ट्रपति के फिर निमंत्रण दिये जाने पर अमरीका जायेंगे अथवा प्रस्तावित यात्रा को रद्द करने का निर्णय किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रधान मंत्री किसी निमंत्रण को स्वीकार करने से पहले अपनी सुविधा देखेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): May I know whether Sino-Pak friendship has any hearing on the cancellation of the visit to America or the misunderstanding created by some officials has lead to this situation ?

Shri Swaran Singh : Sino-Pakistan friendship has nothing to do with cancellation of this invitation. No Officer has created any misunderstanding.

श्री प्र० के० देव (कालाहंडी) : परिवर्तित परिस्थितियों को देखते हुए क्या प्रधान मंत्री निश्चित कार्यक्रम के अनुसार अन्य देशों की यात्रा करेंगे और यदि हां, तो किन किन देशों में जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में वह बता चुके हैं ?

Shri Bagri (Hissar) : May I know the reaction of America on the cancellation of the visit to America by our Prime Minister; and if the reaction is adverse, whether Government propose to make our Foreign Policy clear to them ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं विवरण में बता चुका हूं कि हम ने अपनी विदेश नीति बहुत सोच विचार करने के बाद अपनाई है । अतः हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं चाहे कोई देश इसे पसन्द करे अथवा न करे ।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : राजनीतिक पत्रकारों के इस विचारानुसार कि अमरीका यात्रा हमारी नीति न मानने के कारण या हमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति के समान समझने के कारण रद्द की गई और इस दृष्टि से कि वैदेशिक कार्य मंत्री ने यह कहा था कि हम अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रखेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नीति के बारे यह घोषणा करेगी कि भारत की विदेश नीति हर तरह की परिस्थितियों में स्वतंत्र रहेगी ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी नीति सदा स्वतंत्र रही है और आशा है भविष्य में भी स्वतंत्र रहेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या यह सच है कि पिछले दो-तीन सप्ताह में, जब से भारत सरकार ने वियतनाम के बारे में अमरीकी सरकार के सामने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है, अमरीकी सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से अथवा वाशिंगटन में हमारे राजदूत के द्वारा इस बात का संकेत दिया है कि यदि दुर्भाग्यवश दक्षिण वियतनाम साम्यवादी बन गया तो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की स्वतंत्रता नष्ट हो जायेगी और शीघ्र ही भारत पर भी चीन का प्रभुत्व हो जायेगा ।

श्री स्वर्ण सिंह : इस का निमंत्रण से कोई सम्बन्ध नहीं है । निमंत्रण रद्द करते समय इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या भारत को अमरीका का यह रवैया पसन्द है कि वह भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तोलना चाहता है और यदि नहीं, तो क्या उसे यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अमरीका द्वारा प्रधान मंत्री की यात्रा रद्द करने से भारत की जनता अप्रसन्न है और भविष्य में अमरीका के राष्ट्रपति को भारत के प्रधान मंत्री से मिलने के लिए यहां आना चाहिए न कि प्रधान मंत्री अमरीका जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल भिन्न बात है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : किसी देश द्वारा एक देश के प्रधान मंत्री की यात्रा का इस प्रकार एकतरफा रद्द किया जाना गत 75 वर्षों के राजनयिक इतिहास में एक अपूर्व घटना है। क्या यह प्रश्न अफ्रीकी -एशियाई सम्मेलन में उठाया जायेगा ताकि यह हमारी सरकार तथा जनता के लिए ही नहीं अपितु गुटों से अलग रहने वाले राष्ट्रों के लिए अपमान जनक बात न रहे ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसे अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन में उठाना आवश्यक नहीं है ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : पाकिस्तान की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पाकिस्तान को भारत के स्तर पर रखना है और यदि संभव हो तो उस से आगे निकलने का है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार यह नहीं समझती कि अमरीका, भारत के प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की अमरीका की यात्रा रद्द कर के, पाकिस्तान के हाथों में खिलौना रहा है और यदि हां, तो सरकार को, विशषेता, प्रधान मंत्री को, इस सम्बन्ध में कुछ विशेष बात कहनी है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । माननीय सदस्य स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं । हमें पाकिस्तान के सम्बन्ध में अमरीका के रवैये के बारे में कुछ नहीं कहना है । यह मामला दोनों सरकार के बीच तय किया जाना चाहिये ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): May I know the reasons of postponement of Mr. Shastri's visit to America whereas the visits of leaders to Italy and South Korea were not postponed by President Johnson on the ground of the situation in Viet Nam ?

Shri Swaran Singh : It s true that their visits have not been cancelled but we are not concerned with that.

Shri Vishwanath Pandey (Salempur) : It has been reported in the press that the view of our Prime Minister regarding the postponement of visit has been made clear to the Secretary of States, Mr. Dean Rusk and he has clarified the position on behalf of his Government. May I know whether the Government of India are satisfied with the clarification given by Mr. Dean Rusk ?

Shri Swaran Singh : I have already made it clear in my statement that our Ambassador in Washington has conveyed our view to Mr. Dean Rusk. According to them this programme does not suit to American President.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्यवाही का शिकार बनने और अन्तर्राष्ट्रीय परेशानी से बचाने की दृष्टि से क्या प्रधान मंत्री का विचार उन्हें ओटावा में भारतीय उच्च आयोग में भोजन पर आमंत्रित करने का है ?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री नि० चं० चटर्जी : क्या राष्ट्रपति जानसन ने अशिष्टता की पूर्ण हद से प्रधान मंत्री की यात्रा इस कारण रद्द की है कि हमारे प्रधान मंत्री ने वियतनाम के सम्बन्ध ब्रिटेन प्रधान मंत्री के दब्बूपने के दृष्टिकोण का अनुकरण नहीं किया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं बता चुका हूं कि हमने बहुत सोच विचार कर ही वियतनाम के सम्बन्ध में नीति अपनाई है। हम इसी का अनुसरण करेंगे चाहे इस से कोई देश नाराज हो अथवा खुश।

Shri Daljit Singh (Una) : Pakistan is using the arms against India on our border, supplied by America and China and our Government have already protested against it. May I know whether Pakistan has started propaganda in America against the attitude adopted by India on Viet Nam issue and whether there has been any effect of this propaganda ?

Shri Swaran Singh : I do not think so because President Ayub's visit has also been cancelled.

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में
RE: MOTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री बागड़ी तथा श्री रामसेवक यादव से श्री नन्दा तथा श्री मुरारका के बीच अन्य सदस्यों की उपस्थिति में हुई उसी बात के सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में सूचना मिली है जिसका उल्लेख श्री कृपालानी ने किया था । मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में किन शब्दों का प्रयोग किया गया था। जिन शब्दों के बारे में श्री कृपालानी ने कहा था उनका उल्लेख श्री बागड़ी तथा श्री यादव ने नहीं किया है। मैं इस सम्बन्ध में कागजात तथा श्री कृपालानी का वक्तव्य देखकर कल इस मामले को लूंगा।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

Shri Bagri (Hissar) : I have tabled a Calling attention notice regarding the strike of Punjab Traders.

Mr. Speaker : The Secretariat will inform you about it.

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग का वार्षिक प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग का वर्ष 1964 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 4212/65]

प्राक्कलन-समिति

ESTIMATES COMMITTEE

अस्सीवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)—भारतीय चरागाह तथा चारा अनुसन्धान संस्था, झांसी और भूमि संरक्षण अनुसन्धान, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के केन्द्र के बारे में प्राक्कलन समिति का अस्सीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री पें० वें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : मैं वाणिज्य, खाद्य तथा कृषि, स्वास्थ्य, गृह-कार्य और उद्योग मंत्रालयों से सम्बन्धित विनियोग लेखे (असैनिक), 1962–63 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), 1964 के बारे में लोक लेखा समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

पांचवां प्रतिवेदन

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम) : मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग देहरादून के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

स्वास्थ्य मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी।

Shri Himatsingka (Godda) : Much can be achieved in respect of the health of the people if concentrated and organised efforts are made to educate the people in the ways of health which will prevent the occurrence of diseases. Booklets should be published in easy and understandable language, laying down the principles of health and hygiene, to be taught to children from the school stage. Adults should also be similarly educated at the adult education centres. Particular attention should be paid in this regard in the rural areas. It will make a great deal of difference if done in a big way.

Many of the diseases in the villages occur due to impure drinking water. People in many areas are so poor that it is not possible for them to contribute 50 per cent for the construction of wells in their areas. In such areas, the whole cost should be borne by the Ministry.

Severe punishment should be given to adulterators of foodstuffs. People should also be told as to how they can discriminate between pure and adulterated stuffs.

Family planning made very little impact in rural areas. Special efforts should be made to carry the programme to the contryside.

Several Voluntary institutions are doing valuable service in the field of T.B. and leprosy. They should be given more grants. Emphasis should be laid on the domiciliary treatment of these diseases. There is voluntary institution for domiciliary treatment of T.B. at Mathura which should be helped and encouraged in order to have better service from the institution. At present, the district authorities are coming in its way. Government should look into the matter.

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इसका महत्व बढ़ता जा रहा है किन्तु समझ नहीं आता कि इसे उचित प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में 35 से भी कम मेडिकल कालेज थे, इस समय उनकी संख्या 84 है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह संख्या 114 हो जायेगी। अतः मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य प्रशासन का पुनर्गठन किया जाये और मंत्रालय के स्तर को उठाया जाये। हमारी योजनाओं को दक्षता तथा सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान के लिए एक पृथक निदेशालय बनाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूं।

उन्नत देशों की तुलना में भारत में बहुत कम डाक्टर हैं। इस समय 84 मेडिकल कालेजों में 11000 विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 14000 विद्यार्थियों को स्नातक स्तर तक शिक्षा देने की योजना है। हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की कमी की है। अध्यापकों की कमी

को पूरा करने के लिए हमें आल इंडिया इस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइन्सेज तथा 50 पुराने मेडिकल कालेजों में 250 रुपए से 300 रुपए तक की 2000 छात्रवृत्तियां देने की एक योजना बनानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो अन्य किसी माननीय सदस्य को अध्यक्षपीठ तथा बोल रहे माननीय सदस्य के बीच से होकर नहीं जाना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय स्वास्थ्य मंत्री को भी इसी प्रकार के नियम का पालन करने को कहें।

अध्यक्ष महोनदय : मैं उन्हें कह चुका हूं।

डा० चन्द्रभान सिंह : मैं अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात कर रहा था। योजना के अन्तर्गत मुख्यत: प्रत्येक स्नातक को एक विषय दिया जाये और उसे विभाग में जूनियर अध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता के रूप में काम पर लगाया जाये। नाम तथा विषय का निर्धारण आवश्यकता तथा अध्यापक की योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिए। इन तीन वर्षों की अवधि में छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने तथा अनुसन्धान करने का अनुभव हो जायेगा और उन्हें स्नाकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा मिल जायेगा। इस प्रकार चौथी योजना के तीसरे वर्ष में 2,000 अध्यापक प्रतिवर्ष प्रशिक्षण पा सकेंगे। और अगले पांच वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की कमी पूरी हो जायेगी। इस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को तीन वर्ष तक अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। अध्यापकों की कमी के कारण इस समय एक अध्यापक को बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप पढ़ाने का स्तर गिर रहा है। अध्यापकों की संख्या पर्याप्त हो जाने पर पढ़ाई के स्तर में सुधार हो जायेगा।

यह दु:ख की बात है कि योग्य व्यक्ति प्राय: चिकित्सा व्यवसाय में नहीं आना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें अध्ययन पाठ्यक्रम बहुत लम्बा है और अन्य पाठ्यक्रयों की अपेक्षा बहुत अधिक धन व्यय होता है किन्तु अध्ययन पूरा करने के बाद डाक्टर को उसके श्रम तथा व्यय की तुलना में प्राप्ति बहुत कम होती है। यदि सरकार चाहती है कि इस व्यवसाय में योग्य व्यक्ति आयें तो व्यवसाय को आकर्षित बनाना आवश्यक है। इसके लिए चिकित्सा व्यवसाय अपनाने वाले लोगों को वही वेतन-क्रम, सुविधायें तथा विशेषाधिकार दिए जाने चाहिएं जो प्रशासनिक, न्यायिक, इंजीनियरी तथा लेखा सेवाओं के अधिकारियों को दी जाती हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि इस प्रकार की सुविधायें दी जाने पर यह व्यवसाय आकर्षक हो जायेगा और मानवता की सेवा के लिए अधिक योग्य व्यवित मिल सकेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हाल में जो समिति नियुक्ति की गई थी उसकी सिफारिशों को सभी राज्यों में पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। अन्य चिकित्सा कर्मचारियों, अर्थात्, स्वास्थ्य बीमा डाक्टरों, रेलवे डाक्टरों, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों आदि की सेवा की शर्तों की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय स्थापित किया जाना चाहिए जो तीन-चार महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन दे दे। केन्द्र को स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकारों को आवश्यकता पड़ने पर शत प्रतिशत सहायता देनी चाहिए।

[डा० चन्द्रभान सिंह]

सभी यह चाहते हैं कि डाक्टर लोग गांवों में जाकर सेवा करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि मेडिकल कालेजों में दाखले के समय तथा नौकरी में आते समय वे ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से सेवा करने के लिए बांड भरें। मैं समझता हूं कि समस्या का हल यह नहीं है। यदि डाक्टरों की वास्तव में गांवों में जाकर सेवा करनी है तो गांवों में पीने के स्वच्छ पानी, स्वच्छता, शिक्षा आदि सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वहां पर डाक्टर सुविधापूर्वक रह सकें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : स्वास्थ्य मंत्रालय पर एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है किंतु इस मंत्रालय द्वारा अपने उत्तरदायित्व को पर्याप्त महत्व न दिए जाने के कारण बहुत से कार्य नहीं हो पाये हैं। यह कहना निराधार है कि ये कार्य राज्य सरकारों से सहयोग न मिलने के कारण पूरे नहीं हुए। केन्द्रीय सरकार को यह उत्तरदायित्व अपना समझ कर कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य, स्वच्छता विज्ञान तथा चिकित्सा सेवा में पूरा समन्वय करने के लिए कुछ ठोस उपाय किए जाने चाहिएं।

यह खेद की बात है कि डाक्टरों तथा नर्सों की सेवा की शर्तें उनके व्यवसार को देखते हुए बिल्कुल अपर्याप्त हैं, उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है और न ही समाज में यह स्थान प्राप्त है जो उन्हें होना चाहिए। डाक्टरों तथा नर्सों को समाज में मानव सेवी के रूप में सम्मान मिलना चाहिए। मंत्रालय को उनकी मांगों तथा आवश्यकताओं की ओर स्वयं ध्यान देकर उन्हें पूरा करने का यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। इससे वे संतुष्ट रहेंगे और अधिक अच्छे ढंग से राष्ट्र की सेवा करेंगे। नर्सिंग व्यवसाय की सदैव उपेक्षा की गई है। परिचारिका के रूप में कोई भी उनकी सेवा के महत्व को नहीं समझता है। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय को उनके कार्य के महत्व को समझकर उनके लिए उचित सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। स्नातक तथा प्रशिक्षण प्राप्त नर्सों के सम्बन्ध में हमारी आवश्यकताओं के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक निकाय स्थापित किया जाना चाहिए। उनके वेतन तथा सेवा की शर्तों के पूरे प्रश्न पर विचार करके उचित कार्यवाही की जानी चाहिए, नर्सों की शिकायतें बिल्कुल उचित हैं अतः उन्हें शीघ्र दूर किया जाना चाहिए। यह सोचना गलत है कि जब तक उनकी सेवा की शर्तों में सुधार न किया जाये तब तक वे मन लगा कर कार्य कर सकती हैं। उनके लिए उचित सुविधाओं की व्यवस्था करना न केवल देश में प्रशिक्षण प्राप्त नर्सों के अभाव की दृष्टि से ही अपितु सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यन्त आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में डाक्टरों की कमी है। रोगी को औषधालयों में काफी समय बर्बाद करना पड़ता है। वहां पर अधिक समय लगने का दूसरा कारण यह भी है कि वहां पर अपनाई जाने वाली वर्तमान प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। अतः मंत्री महोदया को पूरे मामले की जांच करके प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए ताकि सरकारी कर्मचारियों के समय की बचत हो सके।

सरकार को डाक्टरी शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्र की आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर समूची विचारधारा पर पुनर्विचार करके पुनर्गठन करना चाहिए। हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित वर्तमान लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। आशा है स्वास्थ्य मंत्री महोदया इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगी।

यह अत्यन्त दुख की बात है कि स्वतंत्रता के 17 वर्ष बाद भी गांवों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। मंत्रालय भी इस तथ्य से अवगत होगा कि भारत के कई गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी 16 मील तक की दूरी से लाना पड़ता है। मंत्रालय को इन गांवों में रहने वाले लोगों की कठिनाई समझनी चाहिए और वहां पीने के पानी के संभरण के मामले में अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए।

नगर योजना के सम्बन्ध में बहुत कम काम किया गया है। हमें इस दिशा में तेजी से कार्य करना चाहिए।

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : A doctor spends as much time, money and labour on his training as an engineer. Moreover, while an engineer has to deal with the building materials, the doctor has to deal with the human beings. But the attitude of the Government to the medical profession is not at all satisfactory. It is necessary to improve their economic condition and give the encouragement. Like the engineering and other services there should be an All India Medical Service. It will not only open avenues for the doctors but will also make the execution of the health projects easier. They are at present often delayed as they have to be worked through the State Governments.

Something should also be done to see that the differences in pay scales and conditions of service of doctors and nurses in hospitals in different States are eliminated, barring a few big cities where allowances have to be bigger. This will generate a sense of equality among the medical personnel in different States.

Some voluntary institutions have been doing very good service in the field of leprosy. They should be given more assistance by the Government.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur) : Mr. Deputy-Speaker, Government has not paid due attention to the preventive aspects of the diseases. Thus, if pure drinking water is made available to the country side, many of the water borne diseases can be eradicated. Even after seventeen years of indipendence the problem of drinking water remains far from being solved.

As most of our people are poor, we require a cheap medical system of treatment. Allopathy is very expensive. It is regrettable that Government have ignored the Ayurvedic, Unani and Homoeopathic systems of treatment. Grants given to them are meagre and no arrangements for research exists for them.

No statistics have been given in regard to the prosecutions launched against adulterators of food stuffs and medicines. Our laws appear to be weak and are also not properly implemented. Severest possible punishment should be provided for the adulterators, for they played with the life of the people.

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : There has been deterioration in the health of the nation during the last seventeen years of our independence. A radical change is required in the set up of the Ministry. Just as Railways and Posts and Telegraphs services etc. are essential services, so also the me-

[Shri Mohan Swarup]

dical services should be declared as essential service. There should be a board that should look into the problems of national health. The medical services should be a Central subject and should be nationalised. Medical services in Railways etc. should also be integrated with the new set up.

The subject of veterinary services should be taken over from the Ministry of Food and Agriculture and put under the Ministry of Health. Arrangements for cheap antibiotics for animals should be made.

One of the reasons of shortage of doctors in the country is insufficient emoluments paid to them. That is why large number of them has migrated to abroad.

Special attention should be paid to manufacture of pure and cheap medicines. Although the use of antibiotics and sulfa drugs is increasing day by day, there are no research arrangements. There should be a national institute of research in antibiotics. Besides, Pimpri factory, other arrangements should also be made for their manufacture in order to meet the requirements of the country.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिये ।

Shri Mohan Swarup : So many Hon. Members have spoken on Family Planning. I want to say that the funds allotted for this purpose in tv o plans have not been utilised. In third five year plan Government have allotted Rs. 27 crores but out of it only Rs. 9 or 10 crores have been spent. It is evident from it that Government does not want to go ahead with this plan.

I have read in the newspapers today that Intra-luterine device is cent percent successful. Then why not propagate it. I am happy that a factory for its manufacture is going to the established in Etah and want that the method should be propagated in the whole of India.

श्री गोकुलानन्द महन्ती (बालासोर) : एक कल्याणकारी राज्य वही होता है जिसमें सभी जनता स्वस्थ हो । इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह जनता के स्वास्थ्य में सुधार करे । इस संबंध में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और यही वह समय है जब हमें इस पर विचार करना चाहिए कि वह धन जो इसके लिए निर्धारित है उसको ठीक प्रकार से खर्च किया गया है अथवा नहीं ।

प्रतिवेदन पढ़ने पर मालूम होता है कि पहली योजना में इसके लिए 140 करोड़ रुपया रखा गया था जिसमें से 101 करोड़ रुपया खर्च हुआ । दूसरी योजना में 225 करोड़ रुपया रखा गया जिसमें से 216 करोड़ रुपया व्यय हुआ । तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों में 341 करोड़ रुपया रखा गया परन्तु व्यय केवल 191 करोड़ रुपया किया गया । इसी प्रकार परिवार नियोजन के लिए पहली योजना में 70 लाख रुपया रखा गया परन्तु व्यय 14 लाख रुपया किया गया । दूसरी योजना में 300 लाख रुपया रखा गया परन्तु व्यय 215 लाख रुपया किया गया । तीसरी योजना में 27 करोड़ रुपया रखा गया परन्तु अब तक तीन वर्षों में 8 करोड़ रुपया व्यय किया गया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा बजट गलत तरीके से बनाया जाता है । हम बजट बनाकर कर दाता से अपनी योजना में

के लिए धन इकट्ठा कर लेते हैं परन्तु उसे ठीक प्रकार से तथा पूरा पूरा व्यय नहीं करते हैं। खाद्यान्नों में अपमिश्रण के बारे में बहुत से कदम उठाये गये हैं परन्तु खेद है कि हम इसको आज तक नहीं रोक पाये हैं।

पीने के पानी के लिए एक पीने के पानी का बोर्ड बनाया गया है। उसने कुछ सिफारिशों भी की थीं इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है। परन्तु खेद है कि अभी तक यह समस्या हल नहीं हो सकी है। बीमारियों को रोकने के लिए उठाये गये कदमों में सरकार को अवश्य सफलता मिली है क्योंकि अब पहले की तुलना में कम लोग मरते हैं।

कुष्ठ रोग निवारण के लिए बहुत से काम किए गए हैं परन्तु मेरे राज्य में उसके लिए उतनी डिसपैंसरियां नहीं बनाई गयी हैं जितनी बनाई जानी चाहिए थीं। सरकार को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I find that there is much profiteering in the country in regard to medicines. This view was expressed by Senetor Kerifaver also. For example, I want to draw the attention towards the price of Gripe Water. Gripe Water is being manufactured by Gripe Water Anglo-Thain Corporation.

In this Company there is participation of T.T.K. and Co. also. They have fixed their Gripe Water at Rs. 2-10 ps. per bottle whereas it cost them only 30 Paise. If we fix 3 Paise as profit and other charges then only comes to 47 Paise. But they are making a profit of Rs. 1 and 21 Paise per bottle, which is too much.

Take the case of Patents. The Hon. Minister has replied to my question that the medicine which has librium costs Rs. 5,000 per Kilogramme while this very medicine is being sold in Italy in open market at the rate of Rs. 312 Kilogramme. This is the condition in regard to patents. Therefore we should take steps to remove those anomalies.

So many Hon. Members have spoken in regard to the pitiable condition of the nurses. I want to draw the attention of the Government that in the United Kingdom and other civilised countries we find that the ratio between Doctors and Nurses is 1:3. The Bhore Committee has also suggested that the ratio between Doctors and Nurses should be 1:4. But we find that in our country this ratio between Doctors and Nurses is 1:2. I think that the reason for this is that we do not have so many nurses. Why should we not open more institutions for the training of nurses? We have got eighty medical colleges in our country but we do not have sufficient number of nursing institutions. I want that the number of these institutions should be increased and we should also increase the pay and allowances of the nurses so that we can have more nurses.

Shri Shiv Charan Gupta (Delhi Sadar) : I congratulate the Health Minister for the work her ministry has so done. This ministry has almost achieved the target, fixed for it in third five year plan. But I am sorry to say that even then there are some schemes in which this ministry has not achieved the target. It has not done anything worthwhile. Take the case of the health of children. Education ministry is also responsible for this. If the health of the children is not maintained on proper lines I think our future generation will be very weak and it will harm our social life.

[Shri Shiv Cuaran Gupta]

Health Minister should also see that all those works meant for the development of Backward areas and Hilly tracts should also be executed. My hon. friend Dr. Singhvi said about the demands of nurses. I also sympathise with them and appeal that every thing should be done for them.

In the campus of Irwin Hospital of Delhi we find Maulana Azad Medical Hospital and G. V. Pant Hospital. I suggest that there should be co-ordination in all these Hospitals.

I find that Rs. 27 Crores has been provided in third five year plan for family planning. But uptil now only Rs. 14 crores has been spent and Rs. 12 crores still lying with the Government. I suggest that Hon. Minister should give more attention towards this in fourth five year plan.

In the Third five year Plan about Rs. three crores has been allotted for indigenous system of medicine but up to 10 Dec. 1964 only Rs. 28 lakh and 32 thousands has been spent. I want that we should give more attention towards this system.

We all know that during last fifteen years urban population of India has increased. If we will not give any attention towards this then we will face more problem due to slums. Therefore we should provide more money for town planning so that slums may not grow up.

We know that there is a central council for local-self Government. It has suggested so many schemes for the urban population. I am of the view that we should implement those schemes immediately. The same thing is in regard to Mechanical Composting Plants. I also suggest that we should take steps to convert all the dry laterines into flush immediate ly.

स्वास्थ्यमंत्री (डा० सुशीला नायर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा की आभारी हूं कि इस मंत्रालय का यहां पर बड़ी प्रशंसा हुई है। सदस्यों ने यहां पर इस बात पर काफी जोर दिया है कि धन की कमी के कारण मेरे मंत्रालय के बहुत से काम रुके पड़े हैं। मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं।

मैं सदस्यों को बताना चाहती हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रकार के अपने कार्यों को अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत पूरा करने की कोशिश की है। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को रेलवे बोर्ड के समान ही केन्द्रीय विषय बनाना चाहिए। मेरा इस संबंध में यह कहना है कि ऐसा करना हमारी नीति के विरुद्ध होगा क्योंकि हमारी नीति विकेन्द्रीकरण की है। हमने राज्य सरकारों को तथा उसके बाद जिला पंचायतों, खण्ड स्तरों पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों की क्रियान्वित की जिम्मेदारी सौंप दी है। हमारे मंत्रालय में एक केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् है जो विभिन्न कार्यक्रम बनाती है और इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी गयी है। समय-समय पर हमारे अधिकारी राज्यों में जाते हैं तथा वहां पर कार्यक्रमों आदि की क्रियान्विति के बारे में आई कठिनाइयों को यथासंभव दूर करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु फिर भी पूरे देश में कार्यक्रम की क्रियान्विति समानरूप से नहीं हो पा रही है। कुछ राज्य सरकारों ने कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखाई है तथा कुछ ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए हम प्रयत्न करते रहे हैं कि ये सभी कार्यक्रम आशानुकूल सभी राज्यों में क्रियान्वित हों। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रयत्नों से लाभ होने लगा है।

हमने कार्यक्रमों की क्रियान्वित के लिए केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासन संस्था बनाई थी। इस संस्था में हमने राज्य सरकारों के उच्च प्रशासकों को बुलाया था। उन्होंने मिल जुलकर योजना की विभिन्न बातों पर विचार किया तथा हमने इसके बारे में उनको भलीभांति समझाया। इसके बाद जब ये लोग अपने-अपने राज्यों में गये और वहां पर उन्होंने काम किया तो हमें उनके बारे में मालूम हुआ कि उन्होंने वहां पर बड़ा ही अच्छा काम किया है। इसी आधार पर हमें आशा है कि चौथी योजना में हमें तीसरी योजना से अधिक धन मिलेगा।

यह बताया गया कि दूसरी योजना में 225 करोड़ रुपये दिए गए थे परन्तु व्यय केवल 216 करोड़ रुपये किए गए। मैं समझती हूं कि हमने इस सम्बन्ध में पहली योजना की तुलना में पर्याप्त प्रगति की है। पहली योजना में 140 करोड़ रुपये में से 101 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। मैं इस संबंध में यह भी बताना चाहती हूं कि जितना धन हमें आवंटित किया गया वास्तव में हमें उतना धन खर्च करने के लिए नहीं मिला। बजट प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है तथा जो भी धन दिया जाता है हमें उसी में संतोष करना पड़ता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी धन हमें मिलेगा हम उसका अच्छा उपयोग करेंगे और अपने कार्यक्रमों को अच्छी तरह से कार्यान्वित करेंगे।

इसी प्रकार एक माननीय सदस्य ने परिवार नियोजन के बारे में कहा कि 30 करोड़ रुपये में से 10 करोड़ रुपये ही केवल खर्च किए गए हैं। सच यह है कि प्रत्येक वर्ष जो भी धन परिवार नियोजन के लिए रखा जाता है उसमें से अधिकांशतः व्यय कर दिया जाता है। उदाहरणतः पहली योजना में कुल व्यय 14 लाख रुपया व्यय हुआ था। दूसरी योजना में 2.15 करोड़ रुपया व्यय हुआ था। तीसरी योजना में पहले वर्ष 1961–62 में 1.38 करोड़ रुपया; 1962–63 में 2.68 करोड़ रुपया; 1963–64 में 3.97 करोड़ रुपया तथा 1964–65 में 6.05 करोड़ रुपया हमने व्यय किया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि जो भी धन हमें मिल रहा है हम उसको धीरे-धीरे परन्तु प्रभावपूर्ण ढंग से व्यय कर रहे हैं। मुझे राष्ट्रपिता ने समझाया था कि सरकारी धन का धीरे-धीरे सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं उन्हीं के उपदेश के अनुसार धीरे-धीरे प्रभावाशाली ढंग से धन का इस्तेमाल कर रही हूं।

(डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*)

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि परिवार नियोजन का काम नगरों में गांवों की तुलना में अधिक हो रहा है। मैं बताना चाहती हूं कि आज देश में 10964 परिवार कल्याण आयोजन केन्द्र हैं। इनमें से 9,246 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की है।

जहां तक बन्ध्यकरण आपरेशनों का संबंध है मैं बताना चाहती हूं कि तीसरी योजना में 8,27,280 ऐसे आपरेशन हुए हैं। सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त हमने गैर-सरकारी डाक्टरों को भी ऐसे आपरेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

[डा० सुशीला नायर]

इसके अतिरिक्त हमने परिवार नियोजन के लिए 'इन्टरा यूटरीन डिवाइस' नामक एक और उपकरण तैयार किया है । यह प्लास्टिक का एक छल्ला होता है । इसको गर्भाशय के मुंह पर लगा दिया जाता है । जब तक इससे गर्भाशय का मुंह बन्द रहेगा तब तक गर्भाधान नहीं होगा । जब किसी स्त्री की इच्छा होगी कि वह मां बने तब वह इस छल्ले को निकलवाकर ऐसा करने में पुनः समर्थ हो सकती है । हमारा विचार चालू वर्ष में 10 लाख उपकरण बनाने का है । हमने इनको बनाने का कारखाना इटावा में लगाया है । मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमें परिवार नियोजन में बहुत सहायता मिलेगी ।

इस उपकरण के बारे में हमने बड़ी सावधानी से प्रयोग किए हैं । हमने 2,389 महिलाओं के यह छल्ला लगाया । इन में से 5.27 प्रतिशत महिलाओं के दर्द तथा रक्त बहने के कारण छल्ला हटाना पड़ा । लगभग 4.89 प्रतिशत महिलाओं ने स्वयं छल्ला निकाल दिया और केवल 0.46 प्रतिशत महिलाओं के छल्ला लगा रहने पर भी गर्भाधान हो गया । इन आंकड़ों से मालूम होता है कि हमें काफी सफलता मिली है । इसी कारण हमने एक पुस्तिका तैयार की है तथा महिला डाक्टरों को प्रशिक्षण दिया है । हमारा विचार पहले पहल प्रसूति ग्रहों, अस्पतालों में इस छल्ले को देने का है जिससे वह वहां पर आने वाली महिलाओं को इसकी जानकारी करा सकें ।

हम रासायनिक गर्भ निरोध वस्तुयें तथा रबड़ की गर्भ निरोध वस्तुएं भी बना रहे हैं । एक माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या इन वस्तुओं के इस्तेमाल से बच्चे कम पैदा होने लगे हैं । मैं बताना चाहती हूं कि जहां कहीं भी हमने इसके बारे में आंकड़े तैयार किए हैं वहां पर हमको यही मालूम हुआ है कि बच्चे वास्तव में पहले की तुलना में कम हुए हैं । मैंने राज्य सरकारों को इस बारे में तार भी भेजा था कि वह हमको इसके बारे में बतायें ।मेरे पास राज्य सरकारों से उत्तर आ गये हैं । मैं उन उत्तरों को अभी बताने को तैयार नहीं हूं । मैं उनको तब बताऊंगी जब मैं उनकी अपने विभाग द्वारा जांच भी करा लूंगी ।

स्वामी रामेश्वरानन्द जी ने परिवार नियोजन की बड़ी भर्त्सना की तथा कहा कि हमें आत्मसंयम तथा ब्रह्मचर्य का प्रचार जनता में करना चाहिए । मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं तथा चाहती हूं कि समस्त देश में ऐसी भावना फैले । इसके साथ-साथ मैं स्वामी जी से यह कहना चाहूंगी कि स्वामी जी तथा अन्य धार्मिक संगठनों को ब्रह्मचर्य तथा आत्मसंयम आदि का प्रचार करना चाहिए । सरकार किस प्रकार किसी को बाध्य कर सकती है कि वह किसी विशिष्ट तरीके को अपनाये । हम तो कई तरीके बता सकते हैं और यह जनता पर है कि वह जिस तरीके को चाहे इस्तेमाल करे ।

कुछ माननीय सदस्यों ने औषधियों के उत्पादन तथा उनके मूल्य के बारे में कहा । मैं बताना चाहती हूं कि इसकी मुख्यतः जिम्मेदारी उद्योग मंत्रालय पर है । मेरी तो इतनी जिम्मेदारी है कि देश की जनता को अच्छी तथा कम मूल्य पर दवाइयां मिलें । इसीलिये दवाइयां बनाने के कारखाने लगाने पर हमने बहुत ज़ोर दिया है । कारखाने लगाने के कारण ही पैनिसिलिन के मूल्य अब इतने कम हो गये हैं । मैं आशा करती हूं कि सरकारी क्षेत्र में कारखाने लग जाने पर दवाइयों के मूल्य कम हो जायेंगे ।

एक माननीय सदस्य ने पेटेंट के बारे में बताया । सरकार को मालूम है कि पेटेंट के कारण कुछ कठिनाइयां होती हैं और इसीलिए सरकार का विचार पेटेंट कानून में संशोधन करने का है ।

मैं आशा करती हूं कि हमारे उद्योग मंत्री शीघ्र ही इसके बारे में विधेयक पेश कर देंगे। मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी अवश्य है कि देश में दवाइयों की किस्मों पर हमारा नियंत्रण रहे तथा अच्छी किस्म की दवाइयां यहां बनें। मुझे प्रसन्नता है कि संसद् की दोनों सभाओं ने मुझे यह अधिकार पूर्णतया दे दिया है कि मैं दवाइयों में मिलावट करने वालों पर अधिक जुर्माने करूं। हमने इंस्पैक्टरों की संख्या बढ़ा दी है तथा विचार यह है कि इनकी संख्या और बढ़े। कुछ राज्यों में इन्सपैक्टरों के वेतन बढ़ा दिए गए हैं। लेबोरेटरियां लगा दी गयी हैं। हमारा विचार चौथी योजना में और भी अच्छी व्यवस्था करने का है।

यह पूछा गया कि हाल में ही हमने लोगों पर इस सम्बन्ध में अभियोग लगाये हैं। मैं आंकड़े बताती हूं। 1963–64 में 264 लोगों पर अभियोग लगाये गये थे। 1964–65 में दिसम्बर, 1964 तक 143 लोगों पर अभियोग लगाये गये थे। गत वर्ष नकली दवाइयां बनाने वाले 30 लोगों को दण्ड दिए गए थे। ये सभी लोग ऐसे थे जो बिना लाइसेंस के दवाइयां बनाते थे। इसीलिए औषधि-नियंत्रण प्रशासन ने सभी लाइसेंसशुदा निर्माताओं की सूची तैयार की है। हम इन सभी निर्माताओं के कारखानों का निरीक्षण कर रहे हैं। नियमों में परिवर्तन किए जा रहे हैं जिससे नकली दवाइयां बेचना अपराध घोषित हो जाये। इन सभी उपायों से हमें आशा है कि हम इस बुराई को दूर कर सकेंगे। 1964–65 में 18 मामले मिस ब्रान्ड के तथा 12 मामले बिना लाइसेंसशुदा दवाइयां बनाने के थे जिन पर मुकदमे चलाये गये। 1963–64 में 137 मामले निबटाये गये, 1964–65 में 77 मामले निबटाये गये। 1963–64 में 126 मामलों में दण्ड दिया गया तथा 1964–65 के दिसम्बर तक 63 मामलों में दण्ड दिया गया। 1963–64 में 11 मामलों में कारावास का दण्ड दिया गया। 1964–65 में 12 मामलों में कारावास का दण्ड दिया गया। 1963–64 में 115 मामलों तथा 1964–65 में 51 मामलों में जुर्माने किए गए।

इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने निश्चय कर लिया है कि औषधि निर्माण की इन बुराइयों को अवश्य दूर करेगी। मैं बताना चाहती हूं कि इन कार्यों के कारण 1963–64 में 80 प्रतिशत दवाइयां ठीक थीं और 1964–65 में 83 प्रतिशत दवाइयां ठीक पाई गईं। इससे मालूम हो जाता है कि हमें सफलता मिल रही है।

मैं सदस्यों की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि खाद्यान्नों में मिलावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जनता का स्वास्थ्य अच्छे भोजन पर अधिक निर्भर करता है। यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है तथा इसको तभी हल किया जा सकता है जब सारे भारतीय ऐसा न करने के बारे में अपनी जिम्मेदारी समझें। परन्तु फिर भी इस सभा ने खाद्य अपमिश्रण के बारे में जो कठोर दण्ड की व्यवस्था की है हम उनको कार्यान्वित कर रहे हैं। परन्तु केवल दण्ड व्यवस्था से ही इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। यह समस्या मेरे विचार से तभी हल हो पायेगी जब भारतीय अर्थात पूरी भारतीय जनता ऐसा न करने की जिम्मेदारी अपनी समझेगी और मिलावट करने में स्वयं लज्जा अनुभव करेगी।

एक माननीय सदस्य, श्री शिवचरण गुप्त ने स्थानीय निकायों के महत्व तथा इस बात पर बल दिया कि इन्हें अपना कार्य सुचारू रूप से करना चाहिये। इस बारे में, मैं यह बता देना चाहती हूं कि हम एक संस्था की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं जिसमें लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा तथा शिक्षा गोष्ठियों का आयोजन किया जा सकेगा और लोग आपस में बैठ कर विभिन्न मामलों पर विचार कर सकेंगे। इस प्रकार उनमें कार्यकुशलता बढ़ेगी। यह बात

[डा० सुशीला नायर]

गलत है कि सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं सभा के समक्ष कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती हूं जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार पूरी तरह सावधान है। वर्ष 1963 में कुल 43,800 अभियोग चलाये गये, जिन में से 35,016 मामलों में दोष सिद्ध हुआ। 930 मामलों में कारावास का दण्ड दिया गया तथा 31,26,190 रुपये अर्थदण्ड के रूप में इकट्ठे किये गये।

मैं माननीय सदस्यों से इस बात में पूर्णरूप से सहमत हूं कि हमारे देश में चिकित्सा सुविधायें अपर्याप्त हैं। एक हज़ार व्यक्तियों के पीछे हमारे पास अस्पतालों में 0.4 स्थान हैं। वैसे राज्य सरकारों तथा अन्य उत्तरदायी नेताओं ने चिकित्सकों को यह अनुदेश दे रखे हैं कि गम्भीर अवस्था वाले रोगियों को अस्पतालों में दाखिल करने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिये। इसके फल-स्वरूप अस्पतालों में 50 से 100 प्रतिशत भीड़भाड़ रहती है जिससे चिकित्सक रोगियों की देख-भाल ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी यह सुविधायें हैं वह सब स्थानों पर एक जैसी नहीं हैं; कहीं-कहीं तो बहुत ही कम हैं। दिल्ली में एक हज़ार व्यक्तियों की जनसंख्या के पीछे अस्पतालों में 2.4 स्थान है, इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश में 0.58; असम में 0.43; बिहार में 0.25 और जम्मू तथा काश्मीर में 0.37 स्थान हैं। इन सुविधाओं को सुधारने के लिए एक कार्यक्रम बनाया था और इसके लिये हमने योजना आयोग से चौथी योजना काल में 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के लिये कहा था। हमारा अनुमान था कि हम प्रत्येक 1,000 व्यक्तियों के पीछे एक शय्या का प्रबन्ध कर सकेंगे। परन्तु योजना आयोग ने केवल 1,090 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। स्पष्ट है कि इस राशि से हम प्रत्येक 1,000 व्यक्तियों की जनसंख्या के पीछे एक शय्या की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। हां, जो भी अब सुविधायें उपलब्ध हैं उनमें सुधार लाने के लिये भरसक प्रयत्न अवश्य किये जायेंगे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमारा विचार प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की ओर पूरा ध्यान देने का है। प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के अधीन 6 से आठ उप-केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जिससे लोगों को अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा ज़िला अस्पताल के बीच एक प्रकार की ऐम्बुलैंस सेवा की व्यवस्था भी करना चाहते हैं जिससे पेचीदा मामलों को इन केन्द्रों से गाड़ी द्वारा ज़िला अस्पतालों में भेजा जा सके। हमने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि वह विशेषज्ञों को समय-समय पर इन केन्द्रों में भेजा करे जिससे वहां पर चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हो सके। 31-12-1964 तक स्थापित किये गये प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की संख्या 4,373 थी। हमारा विचार है कि चालू वर्ष में 823 और ऐसे केन्द्र खोले जायें। पिछले वर्ष हमारे 15 प्रतिशत केन्द्र बिना चिकित्सकों के थे, यह एक बहुत गम्भीर स्थिति है, परन्तु मैं यह कह सकती हूं कि इस स्थिति में पहले से सुधार हो रहा है। बिना चिकित्सकों के केन्द्रों की संख्या में कमी होती जा रही है। चिकित्सकों की कमी का कारण यह है कि लोग गांवों में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पर मकान, शिक्षा आदि की सुविधायें नहीं होती हैं। इस बारे में हमने राज्य सरकारों से अच्छे स्तर के मकान बनाने के लिये कहा है। केन्द्रों में निर्माण-कार्य के लिये अधिक राशि की व्यवस्था की जा रही है। हमने यह भी सुझाव दिया है कि चिकित्सकों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता मिलना चाहिये क्योंकि वे वहां पर प्रैक्टिस तो कर ही नहीं पाते हैं। उनको विशेष ग्रामीण भत्ता भी दिया जाना चाहिये। हमने राज्य सरकारों को यह भी सुझाव दिया है कि चिकित्सकों को आरम्भ में तीन वर्ष, जब उनके बच्चे स्कूल जाने योग्य नहीं होते, ग्रामों, पहाड़ी इलाकों तथा अन्य कठिन स्थानों पर रखा जाना चाहिये

और उसके पश्चात् उनको स्थायी घोषित किया जाना चाहिये । इन स्थानों पर पुनः उनको तब भेजा जाना चाहिये जब उनके बच्चे बहुत बड़े हो जायें और उन्हें इनकी शिक्षा के लिये चिन्ता न हो। इस प्रकार हम ग्रामीण रोगियों की सुविधाओं तथा चिकित्सकों के हितों का भी ध्यान रख सकेंगे ।

केन्द्रीय सरकार चिकित्सा सेवा में पहले से पर्याप्त सुधार हुआ है । विभिन्न वर्ग इस सेवा से लाभ उठाना चाहते हैं । हम इस का विस्तार अब सामान्य जनता के लिये भी कर रहे हैं । डिस्पैंसरियों पर नैदानिक सेवा (डाइग्नोस्टिक सर्विस) चालू करने के अतिरिक्त विशेषज्ञों को डिस्पैंसरियों में भेजा जाता है जिससे लोगों की आवश्यकताओं को यथासम्भव जल्दी पूरा किया जा सके और उनको असुविधा भी न हो। चिकित्सकों के लिये नवीकर पाठ्यक्रम भी चालू किये हैं जिससे चिकित्सकों को समय-समय पर नये आविष्कारों से अवगत कराया जा सके और वे आपस में बैठ कर उन विभिन्न कठिनाइयों पर विचार कर सकें जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है ।

नर्सों के वेतनक्रमों में वृद्धि की गई है। हम चाहते हैं कि उनको अच्छा वेतन मिले । नर्सों के दाखिला में भी वृद्धि हुई है । पिछले वर्ष लगभग 16,600 नर्सों, 9,075 सहायक नर्स दाईयों तथा 1055 स्वास्थ्यचरों को प्रशिक्षण संस्थाओं में दाखिल किया गया । तीसरी योजना के अन्त तक हम 45,000 नर्सों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं और लगभग इतनी ही चौथी योजना के अन्त तक ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : एक प्रशिक्षित नर्स से अधिक वेतन तो एक तकनीशियन ही पाता है जोकि 10वीं पास भी नहीं होता है ।

डा० सुशीला नायर : यह बिल्कुल सही नहीं है । दिल्ली, मैसूर और कुछ अन्य स्थानों पर नर्सों के वेतन अभी बढ़ाये गये हैं अब इस बारे में कोई चिंता अथवा अप्रसन्नता की बात नहीं रही । दिल्ली में मैट्रन को पहले 320–400 रुपये मिलते थे, अब उन को 500–900 रुपये मिलते हैं । सहायक मैट्रनों को पहले 200 से 300 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 250–380 रुपये मिलते हैं । सार्वजनिक चिकित्सा नर्सों को 150–230 रुपये मिलते थे, अब उनको 210–320 रुपये मिलते हैं । इसी प्रकार नीचे तक वेतनमानों में वृद्धि की गई है । पदस्थ उपचारिका को पहले 100–150 रुपये मिलते थे अब उन्हें 150–380 रुपये दिये जाते हैं । इसी प्रकार स्वास्थ्यचरों को पहले 175 से 205 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 150 से 380 रुपये मिलते हैं । दाईयों को जहां पहले 55 से 110 रुपये मिलते थे अब उन्हें 110 से 155 रुपये मिलते हैं ।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : The city compensatory allowance is being paid to nurses @ 4% whereas to others it is paid @ 8 %.

डा० सुशीला नायर : ऐसा इसलिये है क्योंकि नर्सों को भोजन, वर्दी और कुछ अन्य चीजों के लिये भी भत्ते मिलते हैं अत : वित्त मंत्रालय ने नर्सों के नगरप्रतिकरात्मक भत्ते में कुछ कटौती कर रखी है । इस कटौती को भी हम कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि 81 मेडिकल कालेजों के मुकाबले में केवल 7 अथवा 8 उपचर्या महाविद्यालय हैं । इस का कारण यह है कि ये नई संस्थायें हैं । पहले नर्सों को केवल अस्पतालों में ही प्रशिक्षित किया जाता था । इस समय हमारे देश में 230 उपचर्या स्कूल हैं और 270 स्कूल सहायक नर्सों/दाईयों को प्रशिक्षण देने के लिये हैं । हम प्रशिक्षण-सुविधाओं को और बढ़ा रहे हैं । चौथी योजना के अन्त तक हम कम से कम एक लाख नर्सों और सहायक-नर्सों/दाईयों को प्रशिक्षण दे सकते हैं जोकि हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी ।

[डा० सुशीला नायर]

चिकित्सकों के बारे में कहा गया कि इन को बाहर जाने से रोकना चाहिये । जहां तक केन्द्रीय सरकार चिकित्सा सेवा के चिकित्सकों का सम्बन्ध है, मुझे उन से पूरी सहानुभूति है और मैं उन सदस्यों से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि इनको भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को मिलने वाले वेतन से कम वेतन नहीं मिलना चाहिये । हम इस बारे में अन्य मंत्रालयों से विचार विमर्श कर रहे हैं और मुझे आशा है कि कुछ संतोषजनक हल निकल आयेगा और चिकित्सकों की कठिनाइयां दूर हो जायेंगी । मैंने अगले दिन लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज में भाषण देते हुए चिकित्सा पेशा वालों से कहा था कि उन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिये । हमारे रोगी हमारे देवता हैं अतः हमें उनकी देखभाल हर सूरत में करनी चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि चिकित्सकों ने मेरी उक्त सलाह से व्यवहार रूप में सहमति प्रकट की है ।

चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने कहा कि देश में 11,000 विद्यार्थियों की शिक्षा का जो प्रबन्ध है वह अपर्याप्त है । योजना आयोग द्वारा निर्धारित 8000 विद्यार्थियों को शिक्षित करने तथा 61 चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का लक्ष्य था, जबकि हमने 81 महाविद्यालय खोले और 11277 विद्यार्थियों को दाखिल किया है ।

Shri Kishen Pattnayak : What was the target fixed by the Bhore Committee in this respect ?

Dr. Sushila Nayar : The target fixed by the Bhore Committee was less than that ?

चौथी योजना में हमारा विचार 25 से 30 और चिकित्सा महाविद्यालय भी खोलने का है ।

जहां कुछ सदस्यों ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिये, वहां कुछ अन्य सदस्यों ने इस बात पर बल दिया कि ग्रामों में अच्छे चिकित्सक भेजे जाने चाहियें, क्योंकि ग्रामों में एक ही चिकित्सक होता है जिससे ग्रामवासी सलाह ले सकते हैं ।

आंकड़ों के आधार पर मैं यह कह सकती हूं कि यह गलत है कि लाइसैंसधारी चिकित्सक गांवों में जाने के लिये तैयार हैं । लाइसैंसधारी चिकित्सक तो बहुत अप्रसन्न हैं कि उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है । हम ऐसे युवकों के जीवन से नहीं खेलना चाहते । औषधि तथा शल्य-क्रिया में स्नातक सम्बन्धी पाठ्यक्रम में जहां $5\frac{1}{2}$ वर्ष लगते हैं, वहां लाइसैंसधारी सम्बन्धी पाठ्यक्रम में 5 वर्ष लगते हैं । इस प्रकार इस में केवल 6 मास के समय की बचत होती है । अतः देश में चिकित्सकों की दो श्रेणियां बनाना आवश्यक नहीं है । केवल एक प्रकार का ही पाठ्यक्रम रखा जायेगा, परन्तु ऐसे लोगोंके लिये जिन्होंने आर० एम० पी० प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनको संघनित लाइसैंसधारी पाठ्यक्रम के लिये इजाज़त दी जायेगी । इसी प्रकार वे युवक और युवतियां जिन्होंने आयुर्वेद सम्बन्धी एकीकृत पाठ्यक्रम किया है, भी अब चाहते हैं कि उन के लिये कोई संघनित पाठ्यक्रम होना चाहिये जिससे वे पूर्णरूपेण चिकित्सक बन सकें । इस बारे में हमने यह मामला भारत चिकित्सा परिषद् से उठाया है कि ऐसे लोगों की किस प्रकार सहायता की जा सकती है । परन्तु भविष्य में हमें ऐसे पाठ्यक्रमों को बन्द करना पड़ेगा अन्यथा यह एक बहुत भारी समस्या खड़ी हो जायेगी जिसको हल करना बहुत कठिन हो जायगा इसी कारण से ही तो हमने शुद्ध आयुर्वेदिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू करने का निर्णय किया है । एक माननीय सदस्य तो आयुर्वेद की परिषद स्थापित करने के लिये एक विधेयक लाना चाहते हैं । जब तक हम यह पहले फैसला न कर लें कि प्रशिक्षण किस प्रकार का होना चाहिये, तब तक इस परिषद को कैसे स्थापित किया जा

सकता है। इसी कारण से तो केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने शुद्ध आयुर्वेदिक समिति स्थापित की है जो देश का भ्रमण करेगी और पता लगायेगी कि किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है हमने आयुर्वेद पर अनुसंधान कार्य आरम्भ किया है और इस के लिये हमने कुछ अनुसंधान संस्थायें स्थापित की हैं। वाराणसी में बहुत अच्छा अनुसंधान कार्य हो रहा है। आयुर्वेदिक औषधियों पर नियंत्रण रखने के लिये हमने एक तकनीकी बोर्ड स्थापित किया है और वह इस दिशा में अपना कार्य कर रहा है। इस के अतिरिक्त हमने सर्वेक्षण एकक तथा जड़ी बूटियों के लिये कृषि फार्म स्थापित किये हैं। औषधियों का परीक्षण करने के लिये कई परियोजनायें चालू की हैं। मुझे पूर्ण आशा कि इस प्रकार की विभिन्न अनुसंधान योजनायें जो हमने चालू की हैं इस से कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे।

एक माननीय सदस्य : होम्योपैथी के बारे में क्या स्थिति है।

डा० सुशीला नायर : होम्योपैथिक औषधियों पर भी नियंत्रण का विस्तार कर दिया गया है होम्योपैथिक परिषद् प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रमापीकरण कर रही है।

मलेरिया का उन्मूलन करने में हमें 90 प्रतिशत से भी अधिक सफलता प्राप्त हुई है और चेचक में 70 प्रतिशत से भी अधिक सफलता प्राप्त हुई है।

जहां तक पेय जल के सम्भरण का सम्बन्ध है, हम तो चाहते हैं कि लोगों को अच्छा जल दिया जा सके। परन्तु समस्या यह है कि हमारे पास धन की कमी है। चौथी योजना के लिये हमने 850 करोड़ रुपये के लिये कहा था, परन्तु मंजूरी केवल 340 करोड़ रुपये की मिली है। स्पष्ट है कि हम इन रुपयों से उतना ही कर पायेंगे जो हो सकेगा। हमने प्रत्येक राज्य में उन क्षेत्रों में समस्या की जांच करने के लिये एकक स्थापित किये हैं, जहां पानी की कमी है। ऐसा यह पहली बार किया गया है। अब हमारे पास यथार्थ जानकारी है और यदि हमें सीमेंट, पाईप और विभिन्न अन्य अपेक्षित वस्तुएं दी जायें, तो हम इस दिशा में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना धन और बिना इन सुविधाओं के तो कोई कार्य नहीं हो सकता। फिर भी जो कुछ राशि भी हमें दी गई है हमने उसका सदोपयोग किया है और आशा है, आगे भी करते रहेंगे।

श्री शिवचरण गुप्त ने ठीक ही कहा है कि नगर आयोजन में अभी से सुधार किया जाना चाहिये अन्यथा बाद में गन्दी बस्तियों को हटाना कठिन हो जायेगा। हमने राज्य सरकारों को आदर्श देश तथा नगर आयोजन अधिनियम की एक एक प्रति भेजी है और उनसे आग्रह किया है कि वे इसको क्रियान्वित करें। कुछ राज्यों ने इसको क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया है, अन्य राज्यों का ध्यान इसकी महत्ता की ओर निरन्तर दिलाया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण योजनायें पूरी हो चकी हैं; कुछ पूरी होने वाली हैं। कई अन्य नगरों विशेषतया राजधानियों, औद्योगिक नगरों तथा तीर्थ क्षेत्रों के बारे में वृहित योजनायें बनाई जा रही हैं। आशा है कि चौथी योजना में प्रत्येक ऐसे नगर के लिये वृहित योजना चालू की जायेगी जिनकी जनसंख्या एक लाख और इस से अधिक है। जब तक हम उपनगरों में गन्दी बस्तियों को फैलने से नहीं रोकेंगे, तब तक हम अपना यह कार्य पूरा नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं को पूरा करने के लिये धन का भी बहुत महत्व है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : पहले दिल्ली में से गन्दी बस्तियों को हटाया जाना चाहिये।

डा० सुशीला नायर : दिल्ली विकास प्राधिकारी ने इस सम्बन्ध म बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने 35 करोड़ रुपये के प्लाटों का विकास किया है, जबकि उनको केवल 5 करोड़ रुपये की

[डा० सुशीला नायर]

आवर्तक निधि दी गई है । 3800 औद्योगिक प्लाटों तथा 10,000 निवास-प्लाटों का विकास किया जा रहा है । इस के अतिरिक्त उन्होंने कई महत्वपूर्ण सड़कों तथा अन्य विकास कार्यक्रमों को अपने हाथ में ले रखा है । एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गृह-निर्माण-एंव-बीमा योजना जो दिल्ली विकास प्राधिकारी ने बनाई है उस के अन्तर्गत 10,000 मकान बनाये जायेंगे, इन में से 180 मकान तो बन कर भी तैयार हो गये हैं । इस योजना के अन्तर्गत खरीदने वाले को कुछ बीमा-किस्त देनी पड़ा करेगी । यदि वह व्यक्ति इस बीच में मर भी जायेगा तो बीमा वाले शेष राशि का भुगतान करेंगे जिससे वह मकान उसके बच्चों और उसकी विधवा को मिल जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है अथवा अभी यह विचाराधीन है ?

डा० सुशीला नायर : इस को न केवल अन्तिम रूप ही दिया गया है बल्कि इस के अन्तर्गत 180 मकान बन भी चुके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये पृथक रूप से रखा जाना है ?

श्री नरेंद्रसिंह महीड़ा (आनन्द) : जी, हां । मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 34 से 39 अलग से रखे जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ३४ से ३९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut motions Nos. 34 to 39 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the remaining cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :–

The following Demands in respect of Ministry of Health were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
48	स्वास्थ्य मंत्रालय . .	20,97,000
49	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य .	13,45,10,000
50	स्वास्थ्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	83,93,000
131	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	8,21,33,000

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय

वर्ष 1965-66 के लिये उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय की अनुदानों [की [निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
64	उद्योग तथा संभरण मंत्रालय . .	87,14,000
65	उद्योग . .	4,06,44,000
66	नमक	50,77,000
67	संभरण और निपटान	3,13,45,000
68	उद्योग तथा संभरण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	37,48,000
133	उद्योग तथा संभरण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	54,09,61,000

श्री दाजी (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, योजना में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध मे निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का कार्य बहुत धीमी चाल से किया जा रहा है। सरकार के लिये यह कह देना काफी नहीं है कि हम लक्ष्य को इस लिये पूरा नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा अथवा कच्चे माल की कमी पड़ गई थी। इसी कारण तो योजनायें बनाई जाती हैं ताकि सारा कार्यक्रम ठीक रूप से चलाया जा सके। सरकार के ऐसे स्पष्टीकरण से तो यह स्पष्ट होता है कि कोई आयोजन नहीं किया गया, अन्यथा विदेशी मुद्रा अथवा कच्चे माल की कमी का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये।

पिछले छः महीनों के आंकड़े देखने से पता चलता है कि औद्योगिक-वृद्धि की दर फिर से कम होती जा रही है। हम इसके कारण जानना चाहेंगे क्योंकि 11 प्रतिशत की निर्धारित दर अधिक नहीं है। यदि हमें वियति की चुनौती का सामना करना है तो हम इस दर से भी 1975 अथवा पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक स्थिति का सामना करने के समर्थ नहीं होंगे।

(**डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुईं
Dr. Sarojini Mahishi *in the Chair*)

उद्योगपति सारे देश में शोर मचाते फिरते हैं कि यहां विनियोजन के अनुकूल वातावरण नहीं है जबकि वास्तव में न केवल विनियोजन तथा उद्योगों में वृद्धि हुई है बल्कि लाभ की दर भी अत्यधिक बढ़ गई है। रिज़र्व बैंक ने हाल ही में 251 विदेशी कम्पनियों तथा विदेशी-नियंत्रण में 169 रुपये वाली कम्पनियों के लाभों का अध्ययन किया था, विदेशी कम्पनियों के लाभों में कर देने के पश्चात् 15 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जिसका अभिप्राय है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 31 प्रतिशत वृद्धि हुई। विदेशी-नियंत्रण में कम्पनियों के लाभ में कर देने के पश्चात् 34 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक का निष्कर्ष यह है कि भारतीय कम्पनियों की तुलना में विदेशी-नियंत्रण में चल रही कम्पनियों में लाभ का अनुपात अधिक रहा है। एक अमरीकी अध्ययन से पता चला है कि

[श्री दाजी]

भारत में विनियोजन पाकिस्तान अथवा पश्चिमी योरूप अथवा दक्षिण अमरीकी की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है। यह आश्चर्यजनक बात है कि इस अनुकूल वातावरण के बावजूद विदेशी पूंजी को और अधिक रियायतें दी जा रही हैं।

'इकोनोमिक टाइम्स' ने 51 बड़े औद्योगिक उपक्रमों का हाल ही में अध्ययन किया था। इसके अनुसार कुल पूंजी की प्रतिशतता के रूप में सकल लाभ 1962-63 में 10.8 प्रतिशत से बढ़कर 1963-64 में 11.4 प्रतिशत हो गया, शुद्ध ब्याज अर्थात् कर देने के पश्चात् लाभ 1962-63 में 9.9 प्रतिशत से बढ़कर 10.7 प्रतिशत हो गया तथा सामान्य पूंजी पर वितरित लाभांश 31.66 करोड़ से बढ़कर 34.84 करोड़ हो गया। इससे स्पष्ट है कि उद्योग बहुत फल-फूल रहे हैं। इनमें से कुछ बड़ी कम्पनियों की पूंजी की प्रतिशतता के रूप में लाभ निम्नलिखित हैं :—

बर्न एण्ड कम्पनी	24.6 प्रतिशत
न्यू सेन्ट्रल जूट्स	21.5 प्रतिशत
टैक्समाको	19.9 प्रतिशत
इंडियन एल्यूमीनियम	16.1 प्रतिशत
यूनियन कारबाइड . . .	15.6 प्रतिशत
डनलप .	14.8 प्रतिशत
इंडियन केबल .	14.4 प्रतिशत
ग्वालियर रेयन . .	14.3 प्रतिशत
टाटा हाइड्रोस	13.5 प्रतिशत
टाटा पावर कम्पनी	13.4 प्रतिशत
टाटा स्टील्स	13.4 प्रतिशत

इसका अभिप्राय यह हुआ कि कर देने के बाद इन कम्पनियों को इतना लाभ होता है कि छः साल में लगाई गई सारी पूंजी वसूल हो जाती है और फिर भी यह पूरी बाकी रह जाती है। यदि इसके बाद भी उद्योगपतियों को शिकायत है तो यह आपत्तिजनक बात है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि सरकारी प्रवक्ता उनके हाथ का खिलौना बने हुए हैं और उद्योगों के लिये उनको और रियायतें देने के लिये कहते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़े व्यापारी व्यवस्थित रूप में सरकार को ब्लैक-मेल कर रहे हैं। यह देखकर दुःख होता है कि सरकार इस ब्लैक-मेल का सामना करने की अपेक्षा धीरे-धीरे किन्तु निश्चय ही निर्धारित राष्ट्रीय नीतियों से पीछे हटती जा रही है। हमें यह याद आता है कि उत्तरदायित्वपूर्ण उद्योगपति श्री बिड़ला ने कलकत्ता में धमकी दी कि यदि सरकार काले धन के बारे में इसी प्रकार छानबीन करती रही तो अनेक राजनीतिज्ञों की कुर्सियां हिल जायेंगी। श्री स० का० पाटिल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्री बिड़ला ने कांग्रेस को करोड़ों रुपये दिये। मुझे दुःख होता है कि वे स्वतंत्रता संग्राम में आम आदमी के खून, पसीने

और सर्वस्व बलिदान करने की बात भूल गये और उन्हें केवल श्री बिड़ला के करोड़ों रुपये याद रहे। उद्योग मंत्री की कौन परवाह करता है, वे तो कठपुतली मात्र हैं। नीति सम्बन्धी निर्णय तो अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं, वे तो वहां केवल हस्ताक्षर करने के लिये हैं। बिड़ला जी की पत्रिका 'ईस्टर्न इकानोमिस्ट'के मुख-पृष्ठ पर चित्रित एक व्यंग्य-चित्र में सरकार द्वारा उद्योगपतियों के सामने घुटने टेकने का भाव दिखाया गया है। पत्रिका में नेहरू जी की आलोचना करते हुए उनके मार्ग से विमुख होने का स्वागत किया गया है। इस पत्रिका में दिये गये बिड़ला जी के भाषण में कहा गया है कि साम्यवादियों के अतिरिक्त अन्य किसी दल के सत्तारूढ़ होने की कोई सम्भावना नहीं है और साम्यवादी सबसे पहले उद्योगपतियों का गला काटेंगे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उन्होंने अपने साथी व्यापारियों से कांग्रेस को दान देते रहने का अनुरोध किया है। आगे श्री सत्य नारायण सिंह, संचार मंत्री, के बारे में कहा गया है कि उन्हें समाजवाद की बात को बहुत आगे बढ़ाना पसन्द नहीं और यह उस समय कहा जबकि सदाचार की बात करने वाले श्री नन्दा उनकी बगल में बैठे थे। श्री सिंह ने आगे कहा कि "कांग्रेस सबसे अच्छा दल है और यदि हमारे हाथ से (कांग्रेस) सत्ता जाती है तो संभवत: उससे पहले आप तबाह होंगे, इसलिये हमारा समर्थन करो"। हमारी औद्योगिक नीति इस स्थिति को पहुंच गई है। बिड़ला समुदाय सरकार को शाबाशी देता है और नेहरू जी के मार्ग से विपरीत कार्य करने के लिये कहता है। मैं कहता हूं कि औद्योगिक नीति संकल्प को धीरे धीरे लेकिन निश्चय ही नष्ट किया जा रहा है। श्री गोयनका, जो वित्त मंत्री के मित्र हैं, उनके मतानुसार भी इस संकल्प को नष्टप्राय किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में समाचार में कहा गया है कि औद्योगिक नीति संकल्प के सीमा-बन्धन के दृष्टिकोण को त्याग दिया जायेगा जिससे उद्योग अयथार्थवादी रूप में सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। आगे कहा गया है कि औद्योगिक नीति संकल्प की उदार व्याख्या से सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रतिरक्षा उत्पादन में अधिक भाग लेने दे सकती है।

हमें अच्छी तरह मालूम है कि आयुध कारखानों के आर्डरों को गैर-सरकारी कम्पनियों को देने से लगभग 2000 प्रतिरक्षा कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है और कर्मचारी इसके विरुद्ध आन्दोलन करेंगे। एक नई बात यह की गई है कि अब विदेशी विनियोजक को आशय-पत्र (लैटर आफ इन्टेंट) दिया जायेगा, जिसका अखिल भारतीय निर्माता संघ के प्रधान श्री वैद्य ने भी विरोध किया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि विदेशी विनियोजक भारतीय सहयोगी का चुनाव करेगा। महलनोबिस समिति ने पहले ही बता दिया है कि इसका एक परिणाम यह होगा कि बड़े उद्योगों में विदेशी सहयोगियों का जमाव हो जायेगा और छोटे और मध्यम उद्योग भूखे मर जायेंगे तथा देशी उद्योगों को हानि होगी। श्री बिड़ला को ग्रेसिम-नागदा कारखाने के लिये एक लाख रुपये का आयात करने के लिये लाइसेंस दिया गया है। यह हमारी औद्योगिक नीति कि देश में उपलब्ध सामान भी आयात किया जाता है।

जहां तक लाइसेंस देने की नीति का सम्बन्ध है, आर्थिक केन्द्रीकरण रोकने के लिये सरकार की घोषित नीति का कोई उदाहरण नहीं मिलता। लाइसेंस प्राप्त करने में छोटे तथा मध्यमवर्गीय उद्योगपति बड़े उद्योगपतियों का मुकाबला नहीं कर सकते, जो रिटायर सरकारी सचिवों को सम्पर्क अधिकारी (पब्लिक रिलेशन्स आफिसर) नियुक्त कर लेते हैं। ये अधिकारी लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। चौथी योजना में एक हानिकारक सिद्धान्त को लाइसेंस-नीति का आधार बनाया जा रहा है। निचोड़ यह है कि उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास के लिये न होकर उद्योगपतियों के अपने विकास का मंत्रालय है। छोटी कार परियोजना के बारे में सरकार कभी कहती है कि यह गैर-

[श्री दाजी]

सरकारी क्षेत्र में होगी और कभी कहती है कि सरकारी क्षेत्र में होगी । ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये अनेक आवेदन-पत्र एक साल से भी अधिक समय से पड़े हुए हैं । इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग के बावजूद उद्योग मंत्रालय पेटेन्ट्स के मामले में साम्राज्यवाद व विदेशी-एकाधिकार को समाप्त करने के लिये पेटेन्ट्स कानून में संशोधन के मार्ग में रोड़े अटका रहा है ।

सरकार बड़े उद्योगपतियों के कुकर्मों पर पर्दा डाल रही है । अनेक उद्योगपतियों सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन--जैसे भोपाल टैक्सटाइल्स के बारे में प्रतिवेदन और थैकरसे समूह के बारे में प्रतिवेदन--प्रकाशित नहीं किये गये हैं । जब कोई व्यक्ति बड़े उद्योग समूहों का भण्डा फोड़ने का प्रयत्न करता है तो सरकार अपने अधिकार में दस्तावेजों, प्रतिवेदनों को उपलब्ध करने के सम्बन्ध में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करती है । यही कारण है कि थैकरसे समूह के विरुद्ध अभियोग सिद्ध नहीं हुये और इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने ऐसा करने का साहस किया उसको सजा दी गई । इस प्रकार सरकार अपने अधिकार में ऐसे कागज़ात न देकर, जिससे अपराध सिद्ध होता हो, बड़े व्यापारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होने देती ।

रांची अग्निकांड के बारे में न्यायाधिपति मुखर्जी ने नियंत्रण तथा देख-रेख न करने का उल्लेख किया है, शीघ्र ही एक और अदालती जांच होनी चाहिए । हम जानना चाहते हैं कि जिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था उसने क्या अपराध स्वीकार किया था । सारे मामले को क्यों दबाया जा रहा है । नियंत्रण और देख-रेख में इस आपराधिक भूल के लिये कौन उत्तरदायी है और सम्बद्ध व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में पहले ही बहुत से अंग्रेज तकनीशन हैं और ब्रिटिश सलाहकार और ब्रिटिश तकनीशियन रखने के लिये कहते हैं । सारी परियोजना गलत बनी है और समझौता बेकार तथा राष्ट्र के हितों के विरुद्ध है । जब तक इस मामले में कड़े कदम नहीं उठाये जाते इस परियोजना से लाभ की आशा नहीं की जा सकती । श्री शास्त्री की नीति सम्बन्धी इस घोषणा का क्या हुआ कि सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक उपक्रम होने चाहिए बल्कि इस क्षेत्र में कपड़ा, चीनी, सीमेंट आदि उपभोक्ता वस्तु उद्योग भी होने चाहिए ताकि बड़े व्यापारी समूह का उत्पादन व वितरण में अधिकार कम हो जाये । उपभोक्ता उद्योगों के लिये सरकारी क्षेत्र में न केवल नये उद्योग स्थापित किये जायें बल्कि विद्यमान ऐसे उद्योगों को भी, जिनमें लगाई गई पूंजी से चार गुना धन कमाया जा चुका है, राष्ट्रीय हित में अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है ताकि जनता जीवन की आवश्यक वस्तुओं से वंचित न हो ।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा एक बड़ी जनसंख्या वाला विशाल देश है जहां 18 वर्ष पहले तक शासन की बागडोर ऐसी सत्ता के हाथ में थी जो औद्योगिक विकास में रुचि नहीं रखती थी । मैं सभी राज्यों में घूमा हूं, मुझे तो स्थिति अत्यधिक आशाजनक प्रतीत हुई है । बड़े व बीच के पैमाने के, लघु व कुटीर उद्योगों तथा हस्तशिल्पों के सम्बन्ध में अनेक सर्वेक्षण करने के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

1952 से लघु उद्योगों की गति सारे देश में बहुत तेज़ रही है । केन्द्रीय मंत्रालय के मार्गदर्शन से हज़ारों उद्योग स्थापित हुए हैं । मेरे विचार में मंत्रालय को अब रुक कर स्थापित किये गये उद्योगों को सुदृढ़ बनाने की ओर ध्यान देना चाहिये । मेरी इच्छा है कि श्री दाजी पंजाब की यात्रा करें ।

विभाजन के बाद कृषि और उद्योगों से सम्पन्न भाग पाकिस्तान में चला गया और पिछड़ा हुआ क्षेत्र भारत में रहा। लेकिन अब यदि अम्बाला, लुधियाना, अमतसर आदि स्थानों पर जायें तो आश्चर्यजनक प्रगति देखने को मिलेगी। यदि कोई कमी है तो धन और कच्चे माल की है।

मैंने अनेक बार लाइसेंसों का प्रश्न उठाया है। निश्चय ही लाइसेंस अन्धाधुंध तरीके से जारी किये गये जिसके कारण देश में बहुत सी क्षमता बेकार पड़ी है। इसलिये सरकार का यह प्रथम कार्य होना चाहिए कि ऐसी कार्यवाही की जाये जिससे बेकार क्षमता का पूर्ण उपयोग हो। लाइसेंस जारी करते समय उद्योगपतियों को दिये गये वचन नहीं निभाये गये। चार कठिनाइयां रही हैं, योग्य तकनीशियनों का न मिलना, कच्चे माल की कमी, विदेशों से आवश्यक उपकरण मंगाने में कठिनाई तथा पूंजी व सहयोगियों की कमी। लाइसेंस जारी करते समय सरकार ने उद्योगों को जगह-जगह फलाने की ओर ध्यान नहीं दिया जो देश के औद्योगीकरण के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। 1962 में मैं त्रिवेन्द्रम गया तो देखा कि यह औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। हमें ऐसे स्थानों पर उद्योग बढ़ाने चाहियें थे जहां अनेक सुविधायें उपलब्ध हैं। वित्त मंत्री महोदय ने उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाने के लिये कुछ प्रोत्साहन दिया है लेकिन यह बात माननी पड़ती है कि बहुत कम लोग ही उन स्थानों को छोड़ने को तैयार हैं जहां वे जम चुके हैं। अपने उत्तरदायित्व को पूर्णतः समझते हुए मेरे अपने विचार में सरकार स्वीकृत औद्योगिक नीति संकल्प से पीछे नहीं हटी है। यदि रचनात्मक आलोचना हो तो मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन मेरे माननीय मित्र लोगों को गुमराह करते हैं।

पिछले कई वर्षों से सरकार ने उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय के साथ सौतेली मां की तरह व्यवहार किया है। कभी इसका कुछ भाग अलग कर दिया, कभी कुछ काम हस्तांतरित कर दिया तथा कभी कुछ जोड़-तोड़ कर दी। इसको उचित स्थान मिलना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जहां देश के भावी औद्योगीकरण के लिये औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करने के लिये कच्चे माल का आयात आवश्यक हो, वहां सरकार को विदेशी मुद्रा देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिये। औद्योगिक बस्तियों (इंडस्ट्रियल एस्टेट) की स्थापना में कहीं न कहीं कुछ गोलमाल है। इलाहाबाद में मैंने एक औद्योगिक बस्ती देखी जहां मुश्किल से 4 या 5 इकाइयां स्थापित हुई थीं; आज वे 'या' हों। इसलिये इस ओर ध्यान देना चाहिये।

1964 के आंकड़ों से पता चलता है कि हमारी औद्योगिक विकास की दर 7 प्रतिशत से अधिक नहीं है जो संसार के बहुत से पिछड़े देशों से भी बहुत कम है। हमें विदेशी सहयोगियों का स्वागत करना चाहिये। लेकिन यदि यहां के राष्ट्रजन उद्योगों की स्थापना करें तो हम समवाय विधि विभाग आदि द्वारा उन पर निगरानी रख सकते हैं। इन उद्योगपतियों को सरकार की शर्तों पर काम करना होता है। इसलिये हम इन शर्तों पर उद्योग स्थापित करने में श्री बिड़ला या किसी अन्य का स्वागत क्यों न करें? हमें उनकी पूंजी और उनके ज्ञान से पूर्ण लाभ उठाना चाहिये। यही समय है कि हम विदेशों के लोगों का स्वागत करने की अपेक्षा उनसे सहायता करने के लिये कहें। विकास की वर्तमान स्थिति में हमें तकनीकी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले में हमें चयन करना चाहिये और चुने गये सहयोगी को अपने भागीदार का चुनाव करने का अधिकार होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री म० प० स्वामी (टंकासी) : सभापति जी, इस मंत्रालय का सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के द्वारा देश का औद्योगिक विकास करने का विशेष उत्तरदायित्व है। भारत सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार हमारे उद्योग बहुत प्रगति कर रहे हैं।

[श्री म० प० स्वामी]

हमें यह देख कर प्रसन्नता होती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हम पिन से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाने लगे हैं जो हम स्वतंत्र होने से पहले आयात कर रहे थे। सरकार की उत्पादन परिषदों द्वारा चलाये गये उत्पादन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप वस्तुओं के उत्पादन में दुगनी और चौगुनी वृद्धि हुई है। यही कारण है कि इस्पात उत्पादन में चौगुनी और बिजली की मशीनों में छः गुनी वृद्धि हुई है। हम अब विदेशों को सिलाई की मशीनें तथा बिजली का सामान निर्यात करते हैं। इस सामान के टिकाऊपन की पश्चिम के देशों में बने माल से तुलना की जा सकती है।

इस पृष्ठभूमि में मैं सीमेंट उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सीमेंट राष्ट्रीय परियोजनाओं और भवनों के निर्माण के लिये अत्यन्त आवश्यक है। यह दुर्भाग्य की बात है कि देश में सीमेंट की भारी कमी है। मैं समझता हूं कि इस कमी को दूर करने के लिये मंत्रालय ने विद्यमान कारखानों की क्षमता बढ़ा दी है तथा नये कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये हैं। लेकिन फिर भी प्रति वर्ष 20 या 30 लाख टन की कमी होगी। इस कमी को दूर करने के लिये भारतीय सीमेंट निगम स्थापित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एक बोरी सीमेन्ट भी नहीं मिलती। राज्य सरकारों को अधिक सीमेंट मिलना चाहिये ताकि गांव वालों को मकान बनाने के लिये थोड़ी और सीमेंट मिल सके। किसानों को विशेष कठिनाई होती है और उन्हें दो तीन महीनों के बाद एक आधी बोरी मिल पाती है।

आगे मैं माचिस उद्योग का उल्लेख करूंगा जिसमें लाखों आदमी और स्त्रियों को काम मिला हुआ है। माचिस उद्योग में यन्त्रीकृत तथा कुटीर कारखानों में परस्पर कड़ी प्रतियोगिता है। यंत्रीकृत उत्पादन करने में 'विमको' को एकाधिकार प्राप्त है। मेरी सूचना के अनुसार शुल्क आयोग के साथ किये गये एक करार के द्वारा इस कारखाने ने देश के कुल उत्पादन का आधा उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, कुटीर उद्योगों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह यह देखें कि वे स्वीकृत सीमा से उत्पादन न बढ़ायें और जिससे कुटीर उद्योगों के सीमित उत्पादन पर बुरा प्रभाव न पड़े।

रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि दियासलाई उद्योग में उत्पादन कम हो रहा है। मेरे विचार से इस का कारण कच्चे माल की कमी है। इसके लिये वन विभाग को ऐसी हिदायतें दी जानी चाहियें कि व नरम लकड़ी का उत्पादन बढ़ाये जिस से यह उद्योग भली प्रकार से चल सके।

उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश सरकारों ने कुछ पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं जिन में उन्होंने लिखा है कि वन के उत्पादन पर आधारित बहुत से उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। इस के लिये मेरे विचार से केरल, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर आदि राज्यों में जहां बहुत वन हैं सम्बद्ध प्राधिकारियों को कह देना चाहिये कि वे ऐसे उद्योगों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करे ताकि देहातों में औद्योगीकरण का विकास किया जा सके।

सभी बड़े बड़े उद्योग एक ही स्थान पर स्थित होते हैं । यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम तो देहातों में अधिक उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। देहातों में उद्योगों को स्थापित करने से हमें दो लाभ होते हैं। एक तो यह कि शहरों में जन संख्या कम हो जाती है तथा दूसरा यह कि देहातों के लोगों को नौकरी मिल जाती है । हमारे वित्त मंत्री ने भी बजट पर बोलते हुए कहा था कि हम उद्योगों को देहाती क्षेत्रों में ले जाने के लिये रियायतें दे रहे हैं । परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि रियायत देने से कितने उद्योग देहातों में जा पायेंगे । इसलिये मुझे विश्वास है कि भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री एक वक्तव्य देंगे जिस में वे बतायेंगे कि इस घोषणा के बाद यह लाभ उठा कर कितने उद्योग शहरों से ग्रामों में चले गये हैं ।

अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान देश में ट्रैक्टरों के निर्माण की ओर दिलाना चाहता हूं । एक प्रश्न के उत्तर में खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कहा था कि लगभग 20,000 ट्रैक्टर पुर्जों के न मिलने के कारण पूरी तरह से नहीं बन पाये हैं । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कि देश में अनाज की कमी है और हमें कृषि का उत्पादन बढ़ाना है तो फिर इस प्रकार से इतने ट्रैक्टरों को बेकार पड़े रहने देना बहुत बुरी बात है ।

हमें ट्रैक्टरों का आयात भी नहीं करना चाहिये । हम उन्हें देश में ही बना सकते हैं । यदि आवश्यकता हो तो हम दूसरे देशों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं । इस के अलावा हमें सस्ता ट्रैक्टर बनाने चाहियें । हमें ट्रैक्टरों की बहुत आवश्यकता है । इसलिये हमें बेबी ट्रेक्टरों का भी अधिक से अधिक संख्या में निर्माण करना चाहिये । इस से यह लाभ होगा कि किसान बैलों को छोड़ कर इन ट्रैक्टरों का प्रयोग करने लग जायेंगे । मेरा विचार है कि इस ओर ध्यान दिया जायेगा ।

अब मैं आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं । यह बोर्ड तकनीक जानने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिये बनाया गया था । यदि वे किसी नई चीज़ का आविष्कार करते हैं तो उस के लिये उन्हें पुरस्कार दिया जाता है । इस वर्ष की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि पंद्रह व्यक्तियों को 8,400 रुपये दिये गये हैं । परन्तु हमें पता नहीं चलता कि कौन-कौन सी चीजें आविष्कार की गई हैं । इससे हमें यह नहीं पता चलता कि नया आविष्कार हुआ है या कि किसी की नकल ही की गई है । मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि वे हमें इस बात की जानकारी दें कि कितने नये आविष्कार हुए हैं ।

अब मैं अपनी अन्तिम बात पर आता हूं । राज्य-सभा के सदस्य श्री संथानम की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने सिफारिश की है कि उद्योगों के प्रतिनिधियों को खरीद अधिकारी को मिलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । इन व्यक्तियों का काम उद्योग-पतियों की सेवा करना है परन्तु सेवा तो छोड़िये वे तो उन के काम में भी बाधा डालते हैं । वे मंत्रालय के अधिकारियों को मिल लेते हैं और लाइसेंस जारी करवाने में देरी करवाते हैं ।

अन्त में मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि उद्योगों को ऐसे स्थानों पर ही स्थापित किया जाना चाहिये जहां उनकी आवश्यकता हो । मद्रास जैसे बड़े-बड़े शहरों में ही उनको स्थापित नहीं कर दिया जाना चाहिये । देश में बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र

[श्री म० प० स्वामी]

हैं जहां उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। विकसित राज्यों में जहां बहुत बिजली होती है ये उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। कई पिछड़े हुए क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चूना अधिक मात्रा में उपलब्ध है वहां पर सीमेंट उद्योग स्थापित किया जा सकता है। ऐसे स्थानों पर तो सरकार को स्वयं ही उद्योग स्थापित कर लेने चाहियें। इस तरह से इन पिछड़े हुए क्षेत्रों का भी विकास हो जायेगा।

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : I support the demands of this Ministry. We are satisfied with the way the concerned Ministers are working.

I want to draw the attention of the Ministry towards the agro-industries. There is no doubt that development has taken place in the big cities of the country. But about eighty per cent of our population live in the villages. Their main occupation is agriculture. They remain without employment for about six months in a year. Their employment problem can be solved in case the small scale and medium scale industries are developed in the villages. This will also encourage them to stick to the villages.

Our blacksmiths are so skilful that in case they are given the samples of the equipments manufactured in the factories of Bombay, Calcutta and other big cities of the country they can manufacture them in the villages. It will also save the transportation charges because for the manufacture of these equipments, raw material is first sent to these cities and then the finished goods reach the villages and in this way these agricultural equipments also become costly.

Moreover there are raw materials which cannot be sent out of the villages. In case they are sent they are spoilt in the way. Thus we should set up such industiries where this sort of raw material can be utilised. This will also give employment to the villages.

I welcome the stand taken by Government to encourage both the public sector as well as the private sector industries. In a developing country both the sectors hould get encouragement. Our demands should be met, may be from the public sector or from the private sector. I hope that Government will not yield to the opinions expressed by different persons and will stick to the stand taken in this respect.

The tractors of less horse power are being manufactured in the country. Some tractors are of three hourse power, four horse power or eight horse power. But they are not of much use. The tractors of twenty horse power should be manufactured so that they can be best utilised. Also such tractors should be manufactured in large numbers.

Most of the tractors also remain idle in the country because of the non-availability of the spare-parts. This is an appalling condition. As long as there is scarcity of food in the country this idle capacity of the tractors must be set right and the tractors must be put to use. We must spend even the foreign exchange on the spare-parts for these tractors and these tractors must be made to plough the lands so that more food could be produced. Some training should also be inparted so that these tractors could be repaired in the villages itself.

The difficulties that stand in the way of small scale and medium scale industries in the villages should be removed iron handedly. In case there is shortage of raw material, it should be provided to them without delay. Government should also see if the banks can provide loans to them. It is the duty of Government to see that the rural people do not suffer on any account.

The main reason why industries are not set up in the villages is that there is no electricity in most of the villages. In a well-developed State where electricity is available in plenty, an industry can be started at any place, but unfortunately the industries are concentrated in the cities alone. In my state the electricity has not reached in most of the villages. The percentage of villages electrified in my State is very less as compared to villages electrified in other States. Moreover the electricity is available at high rates. This sort of discrimination should be done away with. It is only then that the industries can be established in the villages.

Government should expand old industries *e.g.* sugar industry rather than setting up the new ones because a huge amount is required to set up new plant. Your department has started, no doubt, to take steps towards it but difficulty of finances comes in the way. Our cane production has become surplus, so every facility for expansion should be given so that our surplus production may not get waste and may be utilised.

Lastly I want to say that our production should not be hampered at any cost. The defaulter should be punished immaterial of the fact whether he belonegs to the public sector or private sector. There cannot be two opinions in this connection.

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मूल्य नियंत्रित वस्तुओं के सम्बन्ध में मूल्य निर्धारित करने के लिए उचित नियम बनाने में सरकार असफल रही है ।

वर्तमान आर्थिक स्थिति की दो मुख्य बातें हैं। एक बात तो मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था का बहुत दबाया जाना है तथा दूसरी बात यह है कि औद्योगिक उत्पादन विशेषकर 1963 से आवश्यकता से बहुत कम हो रहा है । तीसरी योजना के चार वर्षों में हम प्रति वर्ष लगभग 8 प्रतिशत के हिसाब से वार्षिक विकास कर पाये हैं जब कि निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत से कहीं अधिक था ।

इस स्थिति में सुधार करने के लिये हमें तुरन्त ही औद्योगिक उत्पादन में वद्धि करनी चाहिये । परन्तु वास्तव में सब कुछ इस के विपरीत ही हो रहा है । कुछ उद्योगों में बेकार पड़ी क्षमता को तो बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है परन्तु अन्य उद्योगों में स्थापित क्षमता को तेजी से नहीं बढ़ाया जा रहा है ।

इस समय मैं बेकार पड़ी क्षमता के प्रश्न को नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उस के लिये विदेशी कच्चे माल, विदेशी पुर्जों आदि की आवश्यकता है जो कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयात नहीं किये जा सकते हैं। इसलिये अब मैं स्थापित क्षमता की उत्पादन दर में कमी के विषय में कुछ कहना चाहता हूं ।

इस समय मैं कुछ ऐसे उद्योगों का उल्लेख करूंगा जिन की स्थापित क्षमता में वृद्धि की दर बहुत कम रही है । उत्पादक उद्योगों में जिन को स्थापित क्षमता के उत्पादन दर में कमी हुई है उनके उदाहरण हैं सीमेन्ट, इस्पात, अल्यूमोनियम, इंजीनियरी, मशीनरी,

[श्री नारायण दांडेकर]

अन्य मशीनरी औज़ार, रसायन पदार्थ तथा उर्वरक उद्योग। उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में जिन की स्थापित क्षमता में उत्पादन दर में कमी हुई है उनके उदाहरण हैं सूती वस्त्र ऊनी वस्त्र, पटसन की वस्तुओं, चीनी, कागज़ आदि के उद्योग।

उत्पादन क्षमता की धीमी उत्पादन दर के बहुत से कारण हैं। उनमें से मुख्य कारण यह है कि नियन्त्रित वस्तुओं की मूल्य निर्धारित करने की नीति को सरकार न तो ठीक प्रकार से बना पाई है और न ही उसे दृढ़ता से लागू कर पाई है।

अब मैं आर्थिक ढांचे में मूल्य के महत्व पर कुछ कहना चाहता हूं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्य का महत्व मांग और पूर्ति को एक जैसा करना होता है। दूसरे शब्दों में विकासरहित अर्थव्यवस्था में—जैसे भारत की है—बढ़ती हुई मांग को रोकने के लिये मूल्य एक आवश्यक साधन बन रहा है तथा उत्क्रम, विनियोजन तथा तकनीकी और प्रबन्धक दक्षता के साधनों सम्बन्धित उद्योगों में अतिरिक्त सन्यन्त्र क्षमता स्थापित करने में आकर्षित करता है।

मूल्य नियन्त्रण से भ्रष्टाचार आदि बढ़ जाते हैं जिससे मूल्य नियन्त्रण का ध्येय ही समाप्त हो जाता है। परन्तु मूल्य नियन्त्रण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि जबकि नियन्त्रण की कोई आवश्यकता न भी हो तो भी उसे हटाया नहीं जा सकता क्योंकि उसमें निहित स्वार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो उसे हटाने नहीं देते। कोयला उद्योग में आजकल यही स्थिति हो रही है। कोयला उद्योग की स्थापित क्षमता इतनी बढ़ गई है कि उसमें आवश्यकता से अतिरिक्त उपादन होना शुरू हो गया है। अब स्थिति को देखते हुए मूल्य नियन्त्रण हटा दिया जाना चाहिये। परन्तु निहित स्वार्थ है जिसकी वजह से मूल्य नियन्त्रण हटाया नहीं जा रहा है।

मैं तकनीकी विस्तार में न जाकर कुछ ऐसे मुख्य तत्वों का उल्लेख करूंगा जिन पर मेरे ख्याल से विचार किया जाना चाहिये। वास्तव में विचार तो किया जाता है परन्तु उस पर उचित निर्णय नहीं किया जाता। मूल्य निर्धारित करने की नीति के तत्वों पर, जिनका मैं अभी उल्लेख करूंगा, सरकार द्वारा कई वर्षों तक विचार होता रहा। प्रशुल्क आयोग ने भी कई वर्षों तक विचार किया परन्तु आर्थिक दृष्टि से कोई उचित उत्तर न मिला। और यदि प्रशुल्क आयोग ने उचित उत्तर दिया भी तो उद्योग मन्त्रालय ने उसके रास्ते में बाधा डाल दी और राजनीतिक अथवा अंशतः राजनीतिक कारणों से उसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया।

मूल्य निर्धारण में पहला तत्व उस उद्योग में मूल्य निश्चित करने के लिये प्रतिनिधि एककों का चुनना है। सबसे पहले स्थापित एककों और नये एककों में जो भेदभाव है उसे समझ लिया जाना चाहिये। मेरे विचार से ऐसे सभी नये एककों पर, जो कुछ समय ही पहले बने हों, यानीकि जिन्हें काम करते हुए एक दो वर्षों से अधिक समय न हुआ हो, मूल्य नियन्त्रण नहीं होना चाहिये। यह इस लिये किया जाना चाहिये क्योंकि नया एकक स्थापित करने के लिये बहुत कठिनाइयां—जैसे विदेशी मुद्रा की कठिनाई तथा भूमि, जल, बिजली आदि लेने की कठिनाइयां रास्ते में आती हैं। जो भी उद्योगपति इन कठिनाइयों को सहन करते हुए नया एकक स्थापित करे उसके उद्योग में बनी वस्तुएं मूल्य नियन्त्रण से बिल्कुल मुक्त होनी चाहियें।

अब मैं स्थापित एककों को लेता हूं। ऐसे एककों में यदि हम बहुत अच्छे चल रहे एककों को लेकर मूल्य निर्धारित करते हैं या सबसे कम चलने वाले एककों को लेकर मूल्य निर्धारित करते हैं तो भी

बिल्कुल गलत बात है । एक ओर तो किसी एक उद्योग के लिये नियन्त्रित मूल्य होना ही चाहिये तथा दूसरी ओर इस समस्त उद्योग के औसत मूल्य के बराबर लाना ही होगा ।

अब मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात पर आता हूं जिस पर विचार किया जाना चाहिये, वह बात है कि मूल्य निर्धारित करने के लिये कितने उत्पादन को आधार माना जाना चाहिये । शत प्रतिशत उत्पादन तो बहुत अच्छे एककों में होता है । सामान्य उत्पादन 88 और 92 प्रतिशत के बीच होता है । हमें इस ओर विचार करना चाहिये कि जो उद्योगपति सामान्य उत्पादन से अधिक उत्पादन बढ़ाता है उसे विशेष लाभ कमाने दिया जाना चाहिये क्योंकि इसमें उसका समय नष्ट होता है तथा उसे बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं ।

तीसरी बात मूल्य अवक्षयण तथा सन्यन्त्र के प्रतिस्थापन की है । यह एक ऐसी कठिनाई है जिस का आजकल हर उद्योग को सामना करना पड़ता है । प्रत्येक उद्योग द्वारा जिस कीमत पर सन्यन्त्र खरीदा गया हो, उसका उस कीमत से बहुत फर्क होता है जिसको उसके स्थान पर स्थापित किया जाना है । इसलिये इस बात की आवश्यकता हो जाती है कि लाभ के तौर पर केवल सन्यन्त्र के अवक्षयण मूल्य का ही नहीं बल्कि मूल व्यय तथा उसके स्थान पर दूसरे सन्यन्त्र पर जो व्यय हो उसे भी साथ लिया जाना चाहिये । यदि इस प्रकार नहीं किया जायेगा तो ऐसे संयन्त्र को जिसका पहले ही अवक्षयण हो चुका है उसे और भी हानि होगी ।

अब मैं पूंजी पर प्राप्य आय पर आता हूं । पहली चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना चाहिये वह यह है कि पूंजी पर जो आमदनी गिनी जाये वह कर देने के बाद गिनी जानी चाहिये । दूसरे कर देने के बाद की आमदनी का सामान्य पूंजी तथा मुद्रा के बाजार भाव से भी कुछ सम्बन्ध होना चाहिये । आजकल बैंक दर 6 प्रतिशत है । सावधि निक्षेप के लिये बैंक $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत दे रही हैं । अधिमान पूंजी दर 10 प्रतिशत है । इसलिये 12 प्रतिशत या इससे कुछ कम राशि की प्रयाप्त आमदनी नहीं माना जा सकता ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मूल्यों का ढांचा ऐसा होना चाहिये जिससे कि उद्योगों के विस्तार में सुविधा मिले । सीमेंट उद्योग को ही ले लीजिये । इसका उल्लेख करते हुए किसी ने कहा था कि उसके उत्पादन में इतने लाख टन की कमी है । इसी प्रकार से चीनी उद्योग में भी इतने लाख टन की कमी हो रही है । परन्तु उसके लिये किसी मन्त्री महोदय ने नहीं कहा कि यदि उद्योग पूरा उत्पादन नहीं कर पायेंगे तो हम सरकारी क्षेत्र में इसे बढ़ायेंगे । एक ओर तो मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि उद्योगों में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, दूसरी ओर सब कह रहे हैं कि उद्योगपति बहुत लाभ कमा रहे हैं ।

मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हू कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये । वास्तव मे सरकार एवं प्रशुल्क आयोग इन पर विचार कर रहे हैं परन्तु इसका कोई हल नहीं निकाला गया है जो आर्थिक दृष्टि से ठीक हो । इसलिये जब तक सरकार उचित मूल्य नियन्त्रण नीति नहीं अपनाती है हम इस मूल्य नियन्त्रण के क्लेष से छुटकारा नहीं पा सकते हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
65	9	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	लाइसेंसों तथा विदेशी मुद्रा देने से सम्बन्धित प्रक्रिया का सरलीकरण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
65	10	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	इस्पात, विशेष इस्पात और कच्चे लोहे के उत्पादन में कमी ।	100 रुपये
65	11	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य नियन्त्रण हटाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
65	12	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	विदेशी सहायता करारों को व्यक्तिगत व्यापारियों के उद्यम पर छोड़ देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
65	13	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों की सप्लाई न करना ।	100 रुपये
65	14	श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा	योजना की सम्पूर्ण आवश्यकताओं तक सीमित नये कार्य नियम पूरी तरह से स्वीकृत करके औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	20	श्री नारायण दांडेकर	जिन वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रित हैं उनके सम्बन्ध में मूल्य निर्धारण के समुचित सिद्धान्त निश्चित न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।
64	21	श्री वारियर	स्कूटरों के आवंटन के लिए असमाजवादी शर्तें निर्धारित करके, सरकारी कोटे से सरकारी कर्मचारियों को स्कूटर देने के लिए बनाई गई प्रतीक्षा-सूची को पूरी तरह से और मनमाने ढंग से रद्द करना ।	100 रुपये
64	34	श्री मुहम्मद कोया	नेपा अखबारी कागज की किस्म में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
64	35	श्री मुहम्मद कोया	विदेशों से अखबारी कागज मंगाने के के लिए और 2 करोड़ रुपया देने की आवश्यकता।	100 रुपये
64	36	श्री मुहम्मद कोया	विदेशों से अखबारी कागज मंगाने के सम्बन्ध में अधिक उदार नीति अपनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
64	37	श्री मुहम्मद कोया	केरल राज्य में और अधिक सरकारी उद्योग चालू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
64	38	श्री मुहम्मद कोया	केरल के मलाबार क्षेत्र में एक सरकारी उद्योग चालू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
64	41	श्री श्रीकान्तन नायर	छोटी मोटरगाड़ी (कार) न बनाना	राशि घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
64	42	श्री श्रीकान्तन नायर	सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित करने में विभिन्न राज्यों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व न देना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
65	43	श्री श्रीकान्तन नायर	लघु उद्योग को कच्चा माल न देना।	100 रुपये
65	44	डा० मा० श्री अणे	लघु उद्योगों के उचित विकास की आवश्यकता।	100 रुपये
65	45	डा० मा० श्री अणे	औद्योगिक सहकारी समितियों को उपयुक्त अनुदान देने की आवश्यकता।	100 रुपये
68	46	डा० मा० श्री अणे	एकस्व और रूपांकन के नियन्त्रक के कार्यालय का कामकाज।	100 रुपये
133	47	डा० मा० श्री अणे	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना।	100 रुपये
133	8	डा० मा० श्री अणे	लघु उद्योगशाला का कामकाज।	100 रुपये
133	49	डा० मा० श्री अणे	शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजनाओं की कार्यान्विति।	100 रुपये
64	55	श्री वारियर	केरल राज्य में ट्रैक्टर तैयार करने का एक सरकारी कारखाना खोलने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
64	56	श्री वारियर	केरल राज्य में लघु उद्योग एककों के के लिए विदेशों से और अधिक लोहा और इस्पात मंगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	57	श्री वारियर	तांबा रोलिंग मिलों को अर्धनिर्मित सामान बनाने की अनुमति देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	58	श्री वारियर	मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन को इस समय सौंपे गये लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल के आयात और सम्भरण के लिए विस्तृत विशिष्ट विवरण तैयार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	59	श्री वारियर	सहकारी समितियों द्वारा चलायी जाने वाली औद्योगिक बस्तियों में विनियोजन के लिए जीवन बीमा निगम और सरकार की अन्य वित्तीय ऋण संस्थाओं से ब्याज की कम दरों पर धन प्राप्त करने के मार्गोपाय ढूंढ निकालने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	60	श्री वारियर	औद्योगिक बस्तियों में पट्टाधारियों द्वारा कारखानों की इमारतों का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए किस्तवार अदायगी की योजना तैयार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	61	श्री वारियर	रबड़ पैदा करने वाले किसी भी क्षेत्र के पास प्राकृतिक रबड़ पर आधारित कार्यात्मक औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता देने के लिए एक सुसज्जित परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
64	62	श्री वारियर	खाद्य परिष्करण, भूच्छिल्प, लकड़ी और नारियल पर आधारित कार्यात्मक औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता।	100 रुपये
64	63	श्री वारियर	लघु उद्योग सेवा-शाला, त्रिचूर, द्वारा तैयार की गई लघु उद्योग योजनाओं को कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
64	64	श्री वारियर	केरल राज्य में विशेषकर विदेशी सहयोग से आदिरूप उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
65	66	श्री दाजी	औद्योगिक नीति संकल्प से विमुख होना	100 रुपये
	67	श्री दाजी .	जनसाधारण के लिये कार न बनाना।	100 रुपये
	68	श्री दाजी .	हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड की कार्यप्रणाली।	100 रुपये
	69	श्री दाजी	स्पष्ट औद्योगिक नीति निर्धारित न करना।	100 रुपये
	70	श्री दाजी .	प्रबन्ध अभिकरण पद्धति की बुराइयों को रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये
	71	श्री दाजी .	लाइसेंस देने की त्रुटिपूर्ण पद्धति।	100 रुपये
	72	श्री दाजी .	विदेशी पूंजी को रियायतें	100 रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं।

श्री हेडा (निज़ामाबाद): उद्योग मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री के सराहनीय प्रयत्नों के परिणामस्वरूप आज देश में सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण बना हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व इस कार्य को विकास अनुभाग (विंग) कर रहा था जिसने सहयोग क्षेत्र में उद्योग तथा राष्ट्र की महान सेवा की है। अब उसे बन्द कर दिया गया है।

हर प्रकार के उद्योग के लिये हमें सहयोग के लिए आतुर नहीं होना चाहिए जिस उद्योग को चलाने के लिए हमारे पास अपने पर्याप्त संसाधन हैं और तकनीकी कर्मचारी भी हैं और जिसमें विदेशी सहयोग आवश्यक नहीं है, उसके लिए विदेशी सहयोग को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये।

[श्री हेडा]

आज स्थिति यह है कि हम साधारण उपभोक्ता उद्योगों तक के लिए विदेशी सहयोग ले रहे हैं। यहां तक कि हम सेवा-उद्योगों में भी, जिनका किसी विशेष तकनीकी जानकारी से सम्बन्ध नहीं है, विदेशी सहयोग ले रहे हैं। इस प्रकार देश का बहुत सा धन विदेश जा रहा है।

विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी साझीदारों को समान अंशों में साझीदार न बना कर उनसे ऋण लेना लाभ दायक है क्योंकि समान अंश-साझीदार होने पर उन्हें लाभांश के रूप में अधिक धन मिलता है जब कि ऋण लेने पर उनके पास इतना धन नहीं जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि समान-अंश साझीदारी में जोखिम रहता है और ऋण में कोई भी जोखिम नहीं है। किन्तु आज जब अर्थ व्यवस्था का विकास हो गया है और जब कि हर एक उद्योग में लाभ हो रहा है, तो जोखिम की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह ऋणों की अपेक्षा समान-अंश-साझेदारी को अधिक महत्व दे।

हम विभिन्न देशों से, यथा संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, जापान, फ्रान्स आदि कई देशों से सहयोग ले रहे हैं। हमें यह अध्ययन करना चाहिए कि किसी विशेष देश के सहयोग से चल रहे उद्योगों के क्या परिणाम निकले हैं। इस अध्ययन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से हमारे लिए किस देश का सहयोग अधिक लाभप्रद है। इससे हमें भविष्य में इस सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करने में सहायता मिलेगी।

श्री दाजी तथा श्री सर्राफ ने सरकार और उद्योग के बीच आपसी सम्बन्ध की चर्चा की। सरकार तथा उद्योग के बीच सद्भावपूर्ण सम्बन्ध रहना आवश्यक है। इसमें राष्ट्रीय हित निहित है। सरकार का काम श्रमिक और उद्योग दोनों को खुश रखना है। कुछ भी हो, गत कुछ वर्षों में सरकार तथा उद्योग के बीच आपसी सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं और वे काफी हद तक बिगड़ते गये। देश तथा उद्योग के विकास के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार और उद्योग एक दूसरे के दृष्टिकोण तथा कठिनाइयों को भली भांति समझें। अब मैं उद्योग का उत्पादन पहलू लेता हूं। समाजवाद के दो मुख्य पहलू हैं। एक पहलू यह है कि सम्पत्ति का सब लोगों में समान वितरण और दूसरा है—उत्पादन। हमारा देश निर्धन एवं विकासशील है अतः उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना परमावश्यक है। उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करते समय सरकार को इस बात पर पूरा विचार करना चाहिए कि उसकी स्थापना के बाद वह उद्योग कच्चे माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की मांग न करे। विदेशी मुद्रा पर प्रतिबन्ध रखते हुए, हमें उद्योगों की स्थापना के लिए हमें यथासंभव लाइसेंस जारी करने चाहिएं। अतः लाइसेंस देते समय उत्पादन क्षमता के बारे में भली भांति विचार करना आवश्यक है।

उत्पादन के लिये यह आवश्यक है कि हमारी उत्पादन क्षमता बेकार न जाये। लाइसेंसों पर रोक लगाने से ऐसा वातावरण पैदा हो गया है कि उन्हें मार्केट में बेचा जा सकता है। सरकार उस विशेष महत्वपूर्ण और जरूरी कच्चे माल का आयात करने की भी अनुमति नहीं देती जिसके आयात करने में बहुत कम विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। परिणामस्वरूप उद्योग को हानि उठानी पड़ती है। जैसा कि श्री सर्राफ ने कहा, कि हमारी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग न किये जाने के कारण हर जगह कई औद्योगिक बस्तियां खुल गई हैं। कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण औद्योगिक बस्तियों के कई कारखाने बन्द पड़े हैं। अतः लाइसेंस देते समय यह मालूम करना जरूरी है कि कारखानों की उत्पादन क्षमता के अनुसार आवेदनकर्ता के पास कच्चे माल की व्यवस्था है और उत्पादन कार्य में रुकावट नहीं आयेगी।

अब मैं व्यापार प्रबन्ध के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करूंगा। भारत में व्यापार प्रबन्ध का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। हमारे देश में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र हैं और समस्त आर्थिक विकास सरकार के हाथ में संचित हो गया है। सरकार उद्योग पर अपना प्रभाव डालती है। प्रबन्ध की वित्तीय स्वतन्त्रता सीमित है। अतः ऐसी स्थिति में हमारे देश में व्यापार प्रबन्ध और भी आवश्यक है। इसका उद्देश्य व्यापार प्रबन्ध में काम करने वाले लोगों के चरित्र-बल को सुधारना है। इसलिए इस समय व्यापार-प्रबन्ध पहलू का विकास करने की आवश्यकता है। हमें आर्थिक सेवा, एक नई श्रेणी का काम आरम्भ करना चाहिए जो सरकारी परियोजनाओं के काम की देख-रेख करे। इसी प्रकार हमें गैर-सरकारी क्षेत्र में भी व्यापार-प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे श्रमिकों की समस्याओं को और अच्छी तरह समझ सकें और उनके साथ अच्छे व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करके, और अधिक उत्पादन करने के प्रयत्न में सफल हो सकें।

अन्त में, मेरा एक यह सुझाव है कि उद्योग विभाग को एक पूर्ण मंत्रालय के रूप में परिवर्तित करके उसे एक केबिनेट मंत्री को सौंप देना चाहिए जिस दर्जे के लिए, मैं समझता हूं, उद्योग विभाग उपयुक्त पात्र है।

श्री सुब्बरामन (मदुरै) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ वर्ष पूर्व पारित किये गये उद्योग नीति संकल्प को सरकार कार्यान्वित कर रही है। सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को स्वीकार कर लिया है और निजी उद्योगपतियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया है। हमारे देश में मूल उद्योग, भारी उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग तथा कुटीर उद्योगों की आवश्यकता है और इन सभी उद्योगों का विकास हो रहा है।

विदेशी मुद्रा की कमी हमारे देश के औद्योगिक विकास के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। यदि हम अपने निर्यात में वृद्धि करें और आयात किये जाने वाले कच्चे माल के स्थान पर यदि अपने देश के किसी अन्य उपयुक्त कच्चे माल का उपयोग कर सकें, तो समस्या हल हो सकती है। हमारे उद्योगों के विकास में विदेशियों का भाग लेना बहुत अच्छा है किन्तु उसे सीमित रखना ही वांछनीय है। विदेशी सहयोग अथवा विदेशी साझेदारी से हमें सतर्क भी रहना है ताकि हमारी स्वतन्त्रता अथवा लक्ष्यों पर और हमारी सरकार की नीति तथा उद्देश्यों पर उसका असर न पड़े।

कच्चा लोहा, विशेष इस्पात और इस्पात की चादरों का उत्पादन महत्वपूर्ण है हमारे इस्पात कारखानों में विशेष किस्म के इस्पात के निर्माण के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। यह खुशी की बात है दुर्गापुर और भद्रावती में इस प्रकार के इस्पात के उत्पादन के लिए कुछ विशेष कदम उठाये गये हैं।

उद्योगों के विकास के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि निर्मित माल की किस्म अति सुन्दर हो। अच्छी किस्म का उत्पादन देशी तथा विदेशी, दोनों बाजारों के लिए आवश्यक है। मानक नियंत्रण के अन्तर्गत अधिकाधिक वस्तुएं, विशेषतः सूती वस्त्र तथा घरेलू उपयोग की वस्तुएं, लाई जानी चाहिए।

1960 में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मेन्युफैक्चरिंग स्थापित की गई थी किन्तु उसने अभी तक भी फिल्मों का निर्माण आरम्भ नहीं किया है। आज देश में फिल्मों की मांग भी बढ़ती जा रही है। अतः फिल्म बनाने का काम यथाशीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए। सरकार के पास

[श्री सुब्बरामन]

कुटीर उद्योगों के विकास तथा उसके लिए लोगों को प्रोत्साहन देने की बहुत सी योजनाएं हैं। इन्हीं योजनाओं के परिणामस्वरूप छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित हो रहे हैं ।

माचिस उद्योग एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग है जिसमें लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। मेरी राय में इस उद्योग को अलग रखा जा सकता है अथवा इसे कुटीर उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि कुटीर उद्योग हमारी आवश्यकता के अनुसार दियासलाइयों का उत्पादन कर सकता है ।

प्रतिवेदन से यह मालूम हुआ है कि रंग रोगन की पर्याप्त मात्रा में मांग न होने के कारण उसका काफी मात्रा में उत्पादन नहीं किया जा रहा है। मैं नहीं समझ पाता कि आज जब कि नगरों और गांवों में भवन निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहा है तो फिर इसके मांग में कमी क्यों है। मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह रंग-रोगन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए उपाय करे ।

प्रत्येक राज्य में चीनी के कारखाने हैं, चीनी के कारखानों से निकलने वाली खोई को केवल जलाने के काम में लाया जाता है। मेरा यह सुझाव है कि खोई से गूदा (पल्प) और कागज के निर्माण के लिए प्रत्येक राज्य में एक-एक कारखाना लगाया जाना चाहिए ।

जिन उद्योगों को विदेशी पूंजी की आवश्यकता नहीं है, उन पर लगाये गये नियंत्रण हटा देने चाहिएं ताकि उद्योगपति उद्योगों के विकास के लिए आगे आ सकें। यह हर्ष का विषय है कि तकनीकी विकास सम्बन्धी महानिदेशालय सराहनीय कार्य कर रहा है ।

जहां तक फालतू सामान का सम्बन्ध है, उसे केवल निश्चित अवधियों पर ही नीलाम किया जाता है अथवा बेचा जाता है। किन्तु उसके विक्रय के लिये निलामी अधिक बार होनी चाहिए और उसके लिए काफी प्रचार किया जाना चाहिए ताकि हमें उनके और अधिक अच्छे मूल्य मिल सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shri Bade (Khargaon) : Mr Deputy Speaker, Sir, we have not achieved a satisfactory industrial progress. The progress so far made in connection with the manufacture of basic articles is very slow and tardy. Today we find that Government are investing money in the manufacture of consumers' goods which runs quite contrary to the provision of the Industry Policy Resolution.

The main reason for inadequate number of industries in our country is the absence of encouragement on the part of the Government to industrialise and lack of proper atmosphere for investment. The Government should try to improve these conditions and adopt a more realistic attitude towards private entrepreneurs. The second reason is red-tapism. An industrialist has to go for pillar to post wasting many days and at last he is told to wait for some more time. They should be given all the facilities if we are to register substantial industrial output.

There is great imbalance between Agriculture and Industry. Unless this is removed we will continue to lag behind in both because they are inter-dependent. Agriculture should receive proper attention and all the facilities *viz.*

tractor and other implements should be provided. According to 'Yojna' this imbalance is mainly due to wrong emphasis put in either heavy industry or light industries. The hon. Minister should himself go to Ranchi and Bhopal and find out what is the cause of labour unrest there and then genuine difficulties should be removed.

Industrial Estates should be established only at such places where other facilities exist. In M.P. 766 out of 4320 sheds are lying vacant due to lack of proper facilities. We are wasting money on them.

Korba and Bastar areas are very rich in minerals. At Korba, a fertiliser factory proposed to be set up earlier has been abandoned midway after 1½ crore of rupees have been spent. Though limestone and coal are abandant here. A heavy-water plant could also be set up there.

The D.G.S.&D. whose working has been criticised by the Public Accounts Committee, is not working properly, This Department has been accused of burgling in many cases. There is wide-spread corruption I have high hopes from the hon. Minister and I am sure he will look into its working and remove the defacts therefrom.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The working of this ministry can be judged from the fact that whereas India was 8th in respect of major industries in the world during the British regime, its position has been reduced to 12th or 13th now. The other criterion of its working is that whereas tax on coarse cloth was reduced by 2 paise its price was raised by 3 paise per metre. For such a state of affairs, the Government is as much responsible as the producers.

Not even one Minister in the whole Cabinet can say that he has not increased his personal wealth or property and therefore to-day the Youth of the country does not heed the advice that they should lead a simple life. They have lost all perespective. They have to be told to be strong enough to dethrone the present Government and all those who are responsible for such a state of affairs. If I were in power, I would first put a stop to wastage of money by the big people and then put half of the Government employees, on production work. This will result in saving 1500 crore rupees which will be utilised to expand industries. Today in India the per capita investment is 500 rupees whereas in America it is 20,000 rupees. We cannot bridge this gulf unless, those who have the reins of power, do not serve their own ends. National progress and personal progress do not go together. The Government should see that the Ministers do not increase their assets for at least 20 to 30 years till the nation has not achieved full development progress.

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : यह आरोप लगाया गया है कि लघु उद्योग कच्चे माल के अभाव के कारण घटते जा रहे हैं । इस आरोप में कुछ सार तो है पर तु यह बात पूर्णतया सच नहीं है : क्योंकि लघु उद्योगों पर किसी प्रकार का नियंत्रण लागू नहीं किया गया इसलिये इनकी संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और इस समय जब कि विदेशी मुद्रा का विकट अभाव है और अधिकतर कच्चा माल आयात करना पड़ता है, सभी लघु उद्योगों को कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करना कठिन है । यह बात अलौह धातुओं के सम्बन्ध में विशेष रूप से लागू होती है । लगभग आधे उद्योग अलौह धातुओं पर आधारित हैं । लघु उद्योग बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक में यह चेतावनी दी थी कि अलौह धातुओं पर आधारित उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहन नहीं दिना जाना चाहिए क्योंकि विद्यमान उद्योगों को ही कच्चा माल

[श्री विभुधन्द्र मिश्र]

दे सकना कठिन हो रहा है। इस्पात सम्बन्धी स्थिति आशानुकूल नहीं है पर तु आशा है 3, 4 अथवा 5 वर्षों में स्थिति में सुधार हो जाएगा। गत 3, 4 वर्षों में लघु औद्योगिक क्षेत्र ने काफी प्रगति की है और जहां तक रासायनिक उद्योगों का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा बनाए गए क्रमबद्ध कार्यक्रम के फलस्वरूप इ हें कच्चे माल का संभरण सुनि चित किया गया है। श्री सर्राफ की जानकारी के लिये, 1965 में 172.3 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। लघु उद्योगों के क्षेत्र के लिए कच्चे लोहे की मात्रा 1964-65 के दौरान 1,67,000 टन रखी गई है। क्योंकि अब कच्चा माल देश के अन्दर ही तैया होता है इसलिये रसायन उद्योग के अतिरिक्त रबड़ की वस्तुएं बनाने वाले उद्योग प्लाईवुड, रेयन, जीव सम्बन्धी रसायन उद्योग आदि भी अब आयात पर कम निर्भर करते हैं रंगसाज़ी उद्योग ने भी 3, 4 वर्षों में ही अच्छी प्रगति कर ली है।

बड़े पैमाने तथा लघु उद्योगों में दुर्लभ कच्चे माल के वितरण की समस्या गत कुछ समय से विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में डा० पी० एस० लोकनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो इस बात की जांच करेगी कि क्या इन दोनों क्षेत्रों में कच्चे माल का वितरण समान रूप से होत है अथवा नहीं और इन के लिये निर्धारित कच्चे माल का उचित उपयोग भी होता है? हमें इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

यद्यपि सीमेंट का अभाव है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इसके उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। 1966-67 में उत्पादन 140.1 लाख टन होने की सम्भावना है। जब कि दस वर्ष पूर्व उत्पादन लगभग आधा था। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार आधा आधा सीमेंट बांट लेती हैं। परन्तु उपभोक्ताओं को सीमेंट नहीं मिल रहा इसलिये कई प्रयोगों के पश्चात् सरकार ने भारतीय सीमेंट निगम स्थापित करने का निश्चय किया है। मैं श्री दांडेकर की इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि अभाव के लिये मूल्य नियंत्रण ही जिम्मेदार है। परन्तु मेरे विचार से जब किसी वस्तु का अभाव होता है तो उपभोक्ता के हित में नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। यह कहना गलत है कि सीमेंट उद्योग को कोई लाभ नहीं हो रहा है और इसीलिये उद्योगपति इस पर धन नहीं लगा रहे। इसके विपरीत ए० सी० सी० ही 12 प्रतिशत लाभांश की घोषणा करती है जो बिना लाभ असम्भव है।

आशा है कि 1970-71 के अन्त तक हमारे यहां 2½ से 3 करोड़ टन सीमेंट का उत्पादन होने लगेगा।

Shri Achal Singh (Agra) : Undoubtedly, Industrialisation has registered great progress in our country after independence. By manufacturing cycles, sewing machines, electric fans etc. we are saving a lot of foreign exchange Compared to America, where hardly 8 or 9% people are engaged in Agriculture. In India 80% people are engaged in it and their living condition is none too good. The necessity to extend the industries in the villages need not be over-emphasised. It will help raise their standard.

उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् : लोक-सभा बुधवार, 21 अप्रैल, 1965 / 1 वैशाख, 1887 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थागित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April, 21, 1965/Vaisakha 1, 1887 (Saka).

GMGIPND—LS III—596 (Ai) LS—23-7-65—600.